



सत्यमेव जयते

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए



लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा

Dedicated to Truth in Public Interest

स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के कार्यकलापों की
अनुपालन लेखापरीक्षा
संघ सरकार (वाणिज्यिक)
2022 की संख्या. 8

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के कार्यकलापों की
अनुपालन लेखापरीक्षा
संघ सरकार (वाणिज्यिक)
2022 की संख्या. 8

विषय सूची

अध्याय/ पैराग्राफ	विषय	पृष्ठ सं.
	प्राक्कथन	ii
	कार्यकारी सार	iii
स्टील अथोरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड		
अध्याय I	रिफ्रैक्टरी प्रबंधन	1
अध्याय II	वित्तीय प्रबंधन	37

प्राक्कथन

1. भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की यह रिपोर्ट नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971, 1984 में यथा संशोधित, की धारा 19-ए के प्रावधानों के तहत सरकार को प्रस्तुत करने के लिए तैयार की गई है। .

2. इस लेखापरीक्षा रिपोर्ट में इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड (सेल) से संबंधित संचालन के 02 चयनित क्षेत्रों की समीक्षाएं शामिल हैं, जिनका विवरण नीचे दिया गया है:

क) रिफ़ैक्टरी प्रबन्धन

ख) वित्तीय प्रबंधन

3. लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किए गए लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप की गई है।

कार्यकारी सार

I प्रस्तावना

इस लेखापरीक्षा रिपोर्ट में इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड (सेल) से संबंधित संचालन के 02 चयनित क्षेत्रों की समीक्षा शामिल है। इन क्षेत्रों को संबंधित संगठन के कामकाज में उनके सापेक्ष महत्व के आधार पर समीक्षा के लिए लेखापरीक्षा में चुना गया था। इस ऑडिट रिपोर्ट में सेल से संबंधित निम्नलिखित समीक्षाएं शामिल हैं:

1. रिफ़ैक्टरी प्रबन्धन
2. वित्तीय प्रबन्धन

II मुख्य बातें

प्रतिवेदन में शामिल किए गए चयनित क्षेत्रों पर महत्वपूर्ण अभ्युक्तियों की मुख्य बातें नीचे दी गई हैं:

स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड में रिफ़ैक्टरी प्रबन्धन

रिफ़ैक्टरी अधात्विक सामग्री होती है जिसका उपयोग गर्मी को रोकने और तापमान को सहन करने के लिए फर्नेस और लेडल की आंतरिक लाइनिंग के लिए इस्पात उद्योग में और धातु तथा धातुमल को संभाले रखने और परिवहन करने के लिए पोत में किया जाता है। सेल ने इस्पात बनाने की प्रक्रिया में रिफ़ैक्टरियों की महत्वपूर्ण भूमिका के बावजूद रिफ़ैक्टरियों के लिए इसकी उत्पादन क्षमता को अपग्रेड करने और आधुनिक बनाने के लिए पर्याप्त उपाय नहीं किए।

(पैरा 1.1, 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4 एवं 1.3.5)

कम्पनी दुर्गापुर स्टील संयंत्र, अलाय स्टील्स संयंत्र और इंडियन आयरन एंड स्टील कम्पनी स्टील संयंत्र में रिफ़ैक्टरी की वार्षिक आवश्यकता का निर्धारण करने के लिए परिकल्पित रिफ़ैक्टरी टास्क फोर्स का गठन करने में विफल रही। अपनी आवश्यकता का निर्धारण करने में इसकी असमर्थता के कारण ₹257.15 करोड़ (31 मार्च 2020) मूल्य

की अधिक मालसूची धारिता रही जबकि कुछ मामलों में रिफैक्टरी की मालसूची 15 से 20 वर्षों के लिए अवरूद्ध रही।

(पैरा 1.3.7)

सेल आंतरिक उपलब्ध निष्क्रिय क्षमता का इष्टतम उपयोग करने में भी विफल रहा और इसने उच्च लागत पर बाह्य स्रोतों से अधिप्राप्ति के कारण 2015-16 से 2019-20 के दौरान ₹34.83 करोड़ का अतिरिक्त व्यय किया।

(पैरा 1.3.10)

अधिप्राप्ति प्रक्रिया में विलम्ब और कीमत वैधता अवधि की परिणामी समाप्ति के कारण भी 2015-16 से 2019-20 के दौरान ₹13.07 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

(पैरा 1.3.9)

सेल एक अच्छा विक्रेता आधार विकसित करने में भी विफल रहा और इसने एकल निविदा आधार पर मर्दों की अधिप्राप्ति करना जारी रखा। राउरकेला स्टील संयंत्र ने 2013-14 से 2019-20 के दौरान ₹113.39 करोड़ के लिए एकल निविदा पर टुंडिश रिफैक्टरी अधिप्राप्त की और बोकारो इस्पातसंयंत्र ने स्वाम्य आधार पर 2015-16 से 2019-20 के दौरान उसी आपूर्तिकार से ₹90.28 करोड़ मूल्य के रिफैक्टरी सैटों की अधिप्राप्ति की।

(पैरा 1.3.8)

कम्पनी ने पूरी लेडल प्रबन्धन प्रणाली के कार्यान्वयन और न्यू जनरेशन स्लाईड गेट प्रणाली के आंशिक कार्यान्वयन में विलम्ब के कारण परिहार्य व्यय किया। यदि भिलाई इस्पातसंयंत्र ने अनुबद्ध समय के अन्दर पूरी लेडल प्रबन्धन प्रणाली के लिए आर्डर दिया होता तो इसे ₹19.47 करोड़ की बचत हो सकती थी। यद्यपि पूरी लेडल प्रबन्धन को लाभप्रद पाया गया था, फिर भी प्रबन्धन ने राउरकेला इस्पातसंयंत्र और एलॉय इस्पातसंयंत्र में इसे कार्यान्वित नहीं किया है।

(पैरा 1.3.11)

उसी रूप में सेल रिफैक्टरी प्रबन्धन प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है ताकि आंतरिक सुविधाओं का इष्टतम उपयोग किया जा सके और रिफैक्टरी के लिए अधिप्राप्ति की लागतों में कमी की जा सके।

(पैरा 1.4)

स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में रिफ्रेक्टरी प्रबन्धन प्रणाली पर अध्याय के संबंध में लेखापरीक्षा अनुशंसा करती है कि:

- कंपनी, इस्पात संयंत्रों की मांग के अनुसार बुनियादी ईंटों, मैग्नेशिया कार्बन ईंटों, फायरक्ले/उच्च एल्यूमिना ईंटों और स्लाइड गेट, सिलिका ईंटों आदि जैसे रिफ्रेक्टरियों के लिए संस्थानिक उत्पादन सुविधा को बढ़ाने और उन्नयनकरण के लिए कदम उठा सकती है और निजी पार्टियोंसे खरीदारी से बच सकती है ।
- प्रबंधन निर्धारित मानदंडों के अनुसार बुनियादी ईंटों, ड्राइ रैमिंग मास, मैग्नेशिया कार्बन ईंटों आदि जैसी प्रयुक्त या अस्वीकृत सामग्री का उपयोग करने के लिए आवश्यक कदम उठा सकता है और सेल रिफ्रेक्टरी ईकाई में रखी पुरानी रिफ्रेक्टरी सिलिका ईंटों का उपयोग करने की संभावना का पता लगा सकता है ।
- प्रबंधन यह सुनिश्चित कर सकता है कि कंपनी के सभी इस्पात संयंत्रों में बुनियादी ईंटों, मैग्नीशिया कार्बन ईंटों, फायरक्ले/उच्च एल्यूमिना ईंटों और स्लाइड गेट, सिलिका ईंटों आदि जैसे रिफ्रेक्टरी की आवश्यकता के निर्धारण के लिए रिफ्रेक्टरी कार्य बल या किसी अन्य समान पर्यवेक्षी निकाय का गठन किया जाए।
- प्रबंधन द्वारा कंपनी द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार मालसूची रखने के प्रयास किए जा सकते हैं और तकनीकी उन्नयन/आधुनिकीकरण योजनाओं के आधार पर मौजूदा मालसूचीधारिता और आवश्यकता के निर्धारण पर विचार करने के बाद अधिप्राप्तिकी जानी चाहिए ।
- प्रबंधन, एक या सीमित आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भरता से बचने के लिए रिफ्रेक्टरी मर्दों के लिए नियमित रूप से विक्रेता आधार को विस्तारित करने का प्रयास कर सकता है ।
- अधिप्राप्ति प्रक्रियाओं को निर्धारित समय के भीतर पूरा किया जा सकता है क्योंकि विलम्ब के परिणामस्वरूप बोली कीमत की वैधता समाप्त हो जाती है जिससे अतिरिक्त लागतें आती हैं, जो कंपनी के वित्तीय हित के लिए हानिकारक होती हैं ।

- उत्पादन योजना को इस्पात संयंत्रों और रिफ़ैक्टरी इकाइयों के बीच सिंक्रनाइज़ किया जा सकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आंतरिक सुविधाओं का पूर्ण उपयोग किया जा सके और बाहरी खरीद कम से कम हो ।
- प्रबंधन द्वारा टोटल लैडल प्रबंधन को लाभकारी पाया गया और इसलिए राउरकेला इस्पात संयंत्र और एलाय इस्पात संयंत्र इसके कार्यान्वयन की व्यवहार्यता का मूल्यांकन कर सकते हैं ।

स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में वित्तीय प्रबन्धन

सेल ने 2015-16 से 2017-18 के दौरान हानियां उठाई और बाद में 2018-19 और 2019-20 के दौरान लाभ अर्जित किया जो मुख्यतया सब-ग्रेड फाईन, स्क्रेप आदि के मूल्य निर्धारण के कारण था। कम्पनी को पिछले 5 वर्षों में गिरती/स्थिर हुई क्रेडिट रेटिंग का सामना करना पड़ा जो खराब प्रचालनात्मक निष्पादन, ऋण के स्तरों और ब्याज लागत के कारण थी। सेल द्वारा उधार ली गयी राशियां 2011-12 में ₹16,320 करोड़ से बढ़कर 31 मार्च 2020 को ₹54,127 करोड़ हो गयी। लेखापरीक्षा में पाया गया कि कम्पनी द्वारा ऋण और ब्याज की प्रतिरक्षा करने का निर्णय संगत नहीं था। विदेशी मुद्रा उतार-चढ़ाव के संदर्भ में 400 मिलियन अमरीकी डॉलर के ऋण की प्रतिरक्षा न करने के कारण ₹194 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ। कम्पनी ने मार्च 2017 से दिसम्बर 2017 के दौरान कुछ मामलों को छोड़कर क्रेताओं के क्रेडिट पर ब्याज (एलआईबीओआर) की प्रतिरक्षा नहीं की।

(पैरा 2.4.1 एवं 2.4.4)

सेल की 21 संयुक्त उद्यम कम्पनियों में से, आठ परिचालन में थीं, तीन परियोजनाधीन थीं/व्यवहार्यता के चरण में थीं और दस निष्क्रिय थीं अथवा परिसमापनाधीन थीं। कम्पनी ने संयुक्त उद्यम कम्पनियों में निधियों के निवेश के लिए कोई नीति अथवा दिशानिर्देश तैयार नहीं किए थे। लेखापरीक्षा में सेल द्वारा संयुक्त उद्यम कम्पनियों में अलाभप्रद निवेश के मामले पाए गए।

(पैरा 2.4.5)

देनदारी ₹3,297 करोड़ (2015-16) से बढ़कर ₹9,020 करोड़ (2019-20) हो गए थे। रेलस के लिए कीमत वृद्धि के प्रति ₹1959.46 करोड़ के दावे के प्रस्तुत करने में विलम्ब हुआ।

(पैरा 2.4.8)

इस्पात संयंत्रों द्वारा न्यूनतम गारंटीकृत गैसों को प्राप्त न करने के कारण अतिरिक्त व्यय किया गया। रेलवे द्वारा अनुमत निःशुल्क समय के बाद इंजन के अवरोधन के कारण इंडियन आयरन एंड स्टील कम्पनी स्टील संयंत्र द्वारा इंजन के भाड़ा प्रभागों के प्रति ₹41.09 करोड़ का परिहार्य व्यय किया गया। सेल ने वैगनों के कम लदान के कारण ₹397.90 करोड़ का निरर्थक भाड़ा और वैगनों के अधिक लदान के लिए शास्ति के रूप में ₹7.66 करोड़ भी प्रदत्त किए। अनुमत मात्रा की बजाय अधिक जल की खपत के कारण भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा ₹58.33 करोड़ का अतिरिक्त व्यय किया गया।

(पैरा 2.4.10)

ऋण इक्विटी अनुपात, ब्याज को कवर करने वाले अनुपात और शुद्ध ऋण का ब्याज, कर, मूल्यहास और सेल के परिशोधन से पूर्व आय से अनुपात सेल की वित्तीय स्थिति को दर्शाने वाले महत्वपूर्ण अनुपात कम्पनी की वित्तीय अस्थिरता और बिगडती हुई क्रेडिट प्रोफाइल के भी सूचक थे।

(पैरा 2.4.2 एवं 2.5)

स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में *वित्तीय प्रबन्धन* पर अध्याय के संबंध में लेखापरीक्षा अनुशंसा करती है कि:

- *प्रबंधन, बजट अनुमानों को प्रभावित करने वाले सभी कारकों पर विचार कर सकता है ताकि तैयार किया गया बजट यथार्थवादी और प्राप्य हो।*
- *एसबीआई केंद्रीयकृत नकदी क्रेडिट लेखा में डेबिट शेष पर ब्याज का भुगतान करने से बचने के लिए, कंपनी अपनी निधि की आवश्यकता का सटीक अनुमान सुनिश्चित कर सकती है और ऐसे डेबिट शेष पर परिहार्य ब्याज के भुगतान के प्रभाव का भी निर्धारण कर सकती है।*

- कंपनी के वित्तीय हित को सुरक्षित करने के लिए कंपनी विदेशी विनिमय में उतार-चढ़ाव और ब्याज के लिए ऋण की प्रतिरक्षा के लिए प्रचलित प्रथाओं का पालन कर सकती है।
- संयुक्तउद्यमों/अन्य में निधियों के निवेश के लिए नीति तैयार की जा सकती है और इष्टतम प्रतिफल सुनिश्चित करने के लिए निधियों का विवेकपूर्ण तरीके से निवेश किया जाना चाहिए।
- कंपनी त्रैमासिक कीमतों को समय पर अंतिम रूप देने और सूचित करने के लिए प्रयास कर सकती है और एनटीपीसी को अनंतिम कीमत के आधार पर भुगतान करने के लिए समझा सकती है।
- कंपनी अपने वित्तीय हित की रक्षा के लिए नियत तारीखों के बाद देयों की वसूली के मामले में ब्याज के उद्ग्रहण के लिए एक खंड को शामिल करने का प्रयास कर सकती है।
- कंपनी मुख्य सलाहकार, लागत, वित्त मंत्रालय को वास्तविक समय के आधार पर उत्पाद-वार और प्रक्रिया-वार खपत / इनपुट-आउटपुट विवरण और लागत डेटा प्रदान करने के लिए एक संरचित और मजबूत लागत लेखांकन और सूचना प्रणाली विकसित कर सकती है ताकि विक्रेताओं (रेलवे) से दावों में विलंब न हो और वित्तपोषण की लागत पर अतिरिक्त व्यय न हो।
- प्रबंधन इस तरह की शास्ति से बचने के लिए पिछले वर्षों में गैसों के वास्तविक खपत पैटर्न को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम टेक ऑफमात्रा को नीचे की ओर संशोधित करने के लिए पहल कर सकता है।
- कंपनी (क) विलम्ब प्रभारों में कमी के लिए लक्ष्य निर्धारित कर सकती है (ख) इंजन किराया प्रभारों को कम करने के लिए योजना के तहत अनुमत निर्धारित समय के भीतर सामग्री के लदान करने/उतराई में नियंत्रणीय विलंब को रोकने के लिए आवश्यक उपाय कर सकती है (ग) निष्क्रिय भाड़े के कारण परिहार्य व्यय को कम करने के लिए वैगनों के प्रकार, आकार और वहन क्षमता के संदर्भ में निष्क्रिय भाड़े के लिए सहनशीलता सीमा निर्धारित कर सकती है।

अध्याय I: रिफ़्रेक्टरी प्रबंधन

1.1 प्रस्तावना

स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल या कंपनी), भारत में एक प्रमुख इस्पात उत्पादक कंपनी ने 2018-20 के दौरान वार्षिक लगभग 17.5 मिलियन टन गर्म धातु का उत्पादन किया। यह भिलाई, बोकारो, राउरकेला, दुर्गापुर और बर्नपुर में पांच एकीकृत इस्पात संयंत्रों; दुर्गापुर, सेलम और भद्रावती में तीन विशेष इस्पात संयंत्र और चंद्रपुर में एक फेरो एलॉय संयंत्र का परिचालन करता है।

रिफ़्रेक्टरी अधात्विक सामग्री है जो उच्च तापमान पर अपनी क्षमता को बनाए रखता है और ऊष्मा और दबाव के लिए प्रतिरोधी हैं। रिफ़्रेक्टरी का उपयोग इस्पात उद्योग में फर्नेस और लैडल्स¹ की आंतरिक लाइनिंग के लिए ऊष्मा का प्रतिरोध करने और तापमान का सामना करने के लिए और जलपोत में धातु और धातुमल को पकड़ने और परिवहन करने के लिए किया जाता है। रिफ़्रेक्टरी की आवश्यकता को संस्थानिक सुविधाओं के साथ-साथ बाहरी पक्षों से भी पूरा किया जाता है। 2015-20 के दौरान, सेल ने ₹7,913 करोड़ की रिफ़्रेक्टरी की अधिप्राप्ति की और ₹6,676 करोड़² के रिफ़्रेक्टरी की खपत की।

1.2 लेखापरीक्षा के उद्देश्य और लेखापरीक्षा का कार्य क्षेत्र

लेखापरीक्षा उद्देश्य यह निर्धारण करने के लिए थे कि क्या:

- (i) रिफ़्रेक्टरी के लिए आवश्यकता को वास्तविक रूप से निर्धारित किया गया था और अधिप्राप्ति प्रक्रिया दक्षता, मितव्ययता और प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए उचित और पारदर्शी थी;
- (ii) संस्थानिक उत्पादित रिफ़्रेक्टरियों और खरीदे गए रिफ़्रेक्टरियों की लागत की तुलना की गई थी और जहां आवश्यक हो, प्रबंधन द्वारा संस्थानिक उत्पादन और लागत दक्षता की सुविधाओं को बढ़ाने के लिए आवश्यक कार्रवाई की गई थी; और

¹ जलपोत पिघली हुई धातुओं को परिवहन और बाहर निकालने के लिए उपयोग किया जाता है।

² 2015-16: ₹1,311.91 करोड़, 2016-17: ₹1,103.58 करोड़, 2017-18: ₹1,034.60 करोड़, 2018-19: ₹1,332.59 करोड़, 2019-20: ₹1,893.78 करोड़.

(iii) संविदा प्रबंधन के लिए मॉनिटरिंग तंत्र मौजूद था और आने वाली सामग्री का निरीक्षण किया गया था और शास्त्रिआदि की कटौती के संबंध में खरीद आदेशों के निबंधन और शर्तों का पालन किया गया था।

लेखापरीक्षा में 2015-16 से 2019-20 तक पांच वर्षों की अवधि के लिए सेल³ के सभी इस्पात संयंत्रों और सेल रिफ्रेक्टरी इकाई⁴ के रिकॉर्ड की जांच की गई।

1.3 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

1.3.1 संस्थानिक सुविधाओं का निष्पादन

सेल को रिफ्रेक्टरी (i) सेल रिफ्रेक्टरी इकाई में संस्थानिक सुविधाओं से; भिलाई इस्पात संयंत्र में रिफ्रेक्टरी विनिर्माण संयंत्र और राउरकेला इस्पात संयंत्र में चूना डोलोमाइट ईंट संयंत्र, (ii) सेल की सहायक कंपनी सेल रिफ्रेक्टरी कंपनी लिमिटेड और (iii) बाह्य स्त्रोतों से अधिप्राप्ति से प्राप्त होती है। सेल संयंत्रों ने 2015-20 के दौरान ₹7,913 करोड़⁵ में रिफ्रेक्टरी की अधिप्राप्ति की, जिसमें से 42 प्रतिशत संस्थानिक थे और शेष भारतीय निर्माताओं और विदेशी आपूर्तिकर्ताओं से खरीदे गए थे।

1.3.2 सेल रिफ्रेक्टरी इकाई का निष्पादन और संवर्धन

सेल रिफ्रेक्टरी इकाई 1.27 लाख टन की वार्षिक क्षमता के साथ बुनियादी ईंटों, मैग्नीशिया कार्बन ईंटों, फायरक्ले/उच्च एल्यूमिना ईंटों और स्लाइड गेट, सिलिका ईंटों आदि जैसी रिफ्रेक्टरी का उत्पादन करती है। 2015-16 से 2019-20 के लिए सेल रिफ्रेक्टरी इकाई का उत्पादन निष्पादन तालिका 1.1 में दिया गया है:

³ भिलाई, बोकारो, राउरकेला, दुर्गापुर और बर्नपुर में इस्पात संयंत्र और दुर्गापुर, सलेम और भद्रावती में तीन विशेष इस्पात संयंत्र।

⁴ सेल रिफ्रेक्टरी यूनिट का मुख्य कार्यालय बोकारो स्टील सिटी में स्थित है। सेल रिफ्रेक्टरी यूनिट की चार उत्पादन इकाइयां हैं, जिनमें से तीन झारखंड में बोकारो के पास और एक छत्तीसगढ़ के भिलाई में स्थित है।

⁵ 2015-16 से 2019-20 की अवधि के दौरान, सेल संयंत्रों ने ₹7,913 करोड़ के लिए रिफ्रेक्टरी की अधिप्राप्ति की, जिसमें से ₹6,676 करोड़ के रिफ्रेक्टरी की खपत हुई। शेष इन्वेंटी में होगा।

तालिका 1.1: 2015-16 से 2019-20 के लिए सेल रिफ़ैक्टरी इकाई का उत्पादन निष्पादन
(इकाइयाँ टन में)

वर्ष	वर्तमान क्षमता	वार्षिक उत्पादन योजना	प्रतिशत में क्षमता के लिए वार्षिक नियोजित उत्पादन	वास्तविक उत्पादन	प्रतिशत में वार्षिक नियोजित उत्पादन के लिए वास्तविक उत्पादन	प्रतिशत में क्षमता के लिए वास्तविक उत्पादन
2015-16	127200	121800	96	95613	79	75
2016-17	127200	114100	90	86863	76	68
2017-18	127200	109000	86	88392	81	69
2018-19	127200	109000	86	95396	88	75
2019-20	127200	108569	85	93272	86	73

ऊपर दी गई तालिका से यह देखा जा सकता है कि सेल रिफ़ैक्टरी इकाई द्वारा नियोजित वार्षिक उत्पादन क्षमता का 85 से 96 प्रतिशत के बीच था, जबकि वास्तविक उत्पादन 2015-16 से 2019-20 के दौरान नियोजित उत्पादन का 76 से 88 प्रतिशत और क्षमता का 68 से 75 प्रतिशत के बीच था। इस प्रकार, वार्षिक उत्पादन योजना पांच वर्ष की अवधि में लगातार कम हो रही है।

1.3.3 सेल रिफ़ैक्टरी इकाई का संवर्धन

सेल संयंत्रों के आधुनिकीकरण और विस्तार योजना (2015 तक पूरा हो जाना अपेक्षित) के पूरा होने के बाद रिफ़ैक्टरी की मांग में पर्याप्त वृद्धि प्रत्याशित थी। बाह्य बाजार पर निर्भरता से बचने के लिए, विशेष रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में, आपूर्ति में उतार-चढ़ाव का ध्यान रखने और बाजार मूल्य पर अप्रत्यक्ष रूप से जांच करने के लिए, सेल प्रबंधन ने संस्थानिक रिफ़ैक्टरी उत्पादन की वर्तमान क्षमताओं का अध्ययन करने और एक कार्य योजना तैयार करने का निर्णय लिया। तदनुसार, रिफ़ैक्टरी उत्पादों जिसके लिए कंपनी की क्षमता नहीं थी और जिन्हें आधुनिकीकरण के बाद सेल की संपूर्ण रिफ़ैक्टरी आवश्यकता को पूरा करने के लिए विकसित किए जाने की आवश्यकता थी, का पता लगाने के लिए एक समिति का गठन किया गया था (फरवरी, 2014)। समिति को उन उत्पादों, क्षेत्रों, सेवाओं की भी पहचान करनी थी जहां सेल को बाहरी प्रौद्योगिकी की आवश्यकता थी।

समिति ने सिफारिश की थी (अप्रैल 2014) कि (i) सेल के सेल रिफ़ैक्टरी इकाई और सेल रिफ़ैक्टरी कंपनी लिमिटेड में मौजूदा विनिर्माण सुविधाओं में संवर्धन, जिसमें मौजूदा

प्रौद्योगिकी और उपकरणों का उन्नयन भी शामिल है; (ii) सेल रिफ्रेक्टरी ईकाई में प्रौद्योगिकी अंतरण/टाई-अप के माध्यम से अथवा प्रमुख वैश्विक रिफ्रेक्टरी विनिर्माता के साथ संयुक्त उद्यम में उन मदों के लिए नई आधुनिक विनिर्माण सुविधा की स्थापना, जिनका इसने उत्पादन नहीं किया था; और (iii) बोकारो इस्पात संयंत्र के अंदर नई मडगन मास⁶ विनिर्माण सुविधा की स्थापना और ₹690 करोड़ की अनुमानित लागत से उस संयंत्र आदि की क्षमता में बाद में वृद्धि।

इस संबंध में, लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित को पाया:

- (i) प्रबंधन ने पांच वर्ष बीत जाने के बाद भी उन्नयन के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए। सेल संयंत्रों की आधुनिकीकरण और विस्तार योजना को उत्पादन में लगभग 70 प्रतिशत की अपेक्षित वृद्धि के साथ कार्यान्वित किया गया था। हालांकि, सेल रिफ्रेक्टरी ईकाई का आधुनिकीकरण और उन्नयन अभी तक पूरा नहीं हुआ था (मई 2021)।
- (ii) सेल रिफ्रेक्टरी ईकाई बोकारो इस्पात संयंत्र को 'सिंगल हीट स्लाइड गेट रिफ्रेक्टरी'⁷ की आपूर्ति करती है। हालांकि, बोकारो इस्पात संयंत्र को 'सिंगल हीट स्लाइड गेट रिफ्रेक्टरी' से 'मल्टीपल हीट स्लाइड गेट रिफ्रेक्टरी'⁸, में स्थानांतरित(2015) करने के बाद, सेल रिफ्रेक्टरी ईकाई ने प्रौद्योगिकी का उन्नयन नहीं किया। परिणामस्वरूप, बोकारो इस्पात संयंत्र ने 2015-20 के दौरान निजी आपूर्तिकर्ताओं से ₹31 करोड़ की सामग्री की अधिप्राप्ति की। भिलाई इस्पात संयंत्र ने सेल रिफ्रेक्टरी ईकाई से नई पीढ़ी की 'स्लाइड गेट रिफ्रेक्टरी सिस्टम' की आपूर्ति के लिए प्रौद्योगिकी को बदलने के लिए कहा (2014), जिसे सेल रिफ्रेक्टरी ईकाई द्वारा लागू नहीं किया गया था। परिणामस्वरूप, भिलाई इस्पात संयंत्र ने 2015-20 के दौरान ₹35.01 करोड़ में निजी आपूर्तिकर्ताओं से इसकी अधिप्राप्ति की।

⁶ मडगन मास ब्लास्ट फर्नेस में उपयोग किया जाने वाला एक प्रकार की रिफ्रेक्टरी है।

⁷ जब तरल इस्पात को टुंडिश में आगे के प्रसंस्करण के लिए डाला जाता है, तो स्लाइड गेट रिफ्रेक्टरी सिस्टम के रूप में जाना जाने वाला एक विशेष प्रकार की रिफ्रेक्टरी का उपयोग किया जाता है। जब इस रिफ्रेक्टरी सेट को प्रत्येक हीट के बाद बदल दिया जाता है तो इसे सिंगल हीट स्लाइड गेट रिफ्रेक्टरी सेट कहा जाता है।

⁸ जब स्लाइड गेट रिफ्रेक्टरी सेट को 2 हीट से अधिक हीट के बाद बदल दिया जाता है, तो इसे एकाधिक हीट स्लाइड गेट रिफ्रेक्टरी सेट कहा जाता है।

इसके अतिरिक्त, भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा कोक ओवन बैटरी-2 की कोल्ड मरम्मत के लिए सिलिका ईंटों की आवश्यकता को सेल रिफ्रेक्टरी ईकाई द्वारा पूरा नहीं किया गया था। सेल रिफ्रेक्टरी ईकाई 4,600 टन की आवश्यकता के प्रति 1,043 टन की आपूर्ति करने के लिए सहमत हुई (सितंबर 2018) और कोक ओवन बैटरी-10 के लिए, सेल रिफ्रेक्टरी ईकाई 8,800 टन की आवश्यकता के प्रति 1,400 टन की आपूर्ति करने के लिए सहमत हुई (सितंबर 2017)। इसके अलावा, अप्रैल 2018 से सितंबर 2018 के दौरान आपूर्ति की जाने वाली 5,300 टन सिलिका ईंटों के लिए भिलाई इस्पात संयंत्र की आवश्यकता के प्रति, सेल रिफ्रेक्टरी ईकाई ने सामग्री की आपूर्ति नहीं की। इस प्रकार, सेल रिफ्रेक्टरी ईकाई द्वारा सिलिका ईंटों की आपूर्ति नहीं किए जाने के कारण, भिलाई इस्पात संयंत्र को निजी कंपनियों से ₹58.98 करोड़ में सिलिका ईंटों की अधिप्राप्ति करनी पड़ी।

इस प्रकार, चूंकि सेल रिफ्रेक्टरी ईकाई ने रिफ्रेक्टरी सामग्री की आपूर्ति नहीं की थी, इसलिए बोकारो और भिलाई में इस्पात संयंत्रों को निजी पक्षों से ₹125 करोड़ की अधिप्राप्ति करनी पड़ी।

(iii) कंपनी ने नई मडगन मास विनिर्माण सुविधा की स्थापना के संबंध में समिति की सिफारिशों पर कोई कार्यवाही नहीं की। इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी इस्पात संयंत्र (बर्नपुर में स्थित), राउरकेला इस्पात संयंत्र और भिलाई इस्पात संयंत्र ने ₹151.35 करोड़ (इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी इस्पात संयंत्र: ₹41.24 करोड़, भिलाई इस्पात संयंत्र: ₹30.75 करोड़, राउरकेला इस्पात संयंत्र: ₹79.36 करोड़) के लिए निजी कंपनियों से मडगन मास की अधिप्राप्ति की।



चित्र 1.1: मडगन मास

प्रबंधन/मंत्रालय ने उत्तरदिया (मई 2021/नवंबर 2021) कि इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी केन्द्र, सेल को, मार्च 2018 में सेल रिफ्रेक्टरी ईकाई में क्षमता विस्तार का अध्ययन सौंपा गया था और उनकी सिफारिशों (सितंबर 2018) पर अनुवर्ती कार्यवाही की गई है। इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी केन्द्र, सेल द्वारा प्रस्तुत एक प्रस्तावनोट (नवंबर 2020) सक्रिय रूप से विचाराधीन था।

इसमें आगे बताया गया है कि मडगन क्ले विनिर्माण के लिए संस्थानिक क्षमता के विकास के लिए वैश्विक भागीदारों को आमंत्रित रुचि की अभिव्यक्ति जारी (मार्च 2020) की गई थी। तकनीकी रूप से सक्षम एक विक्रेता मिल गया था और सेल रिफ़ैक्टरीईकाई द्वारा इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी केन्द्र, सेल से एक उपयुक्त प्रस्ताव बनाने का अनुरोध किया गया था।

प्रबंधन/मंत्रालय का उत्तर इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए तर्कसंगत नहीं है कि इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी केन्द्र, सेल को समिति की सिफारिशों के चार वर्षों के बाद मार्च 2018 में सेल रिफ़ैक्टरी ईकाई में क्षमता विस्तार का अध्ययन सौंपा गया था। इसके अलावा, समिति (2014 में गठित) और इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी केन्द्र, सेल की सिफारिशों का अभी तक पूरी तरह से अनुपालन नहीं किया गया था।

इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी केन्द्र, सेल ने सेल संयंत्रों की रिफ़ैक्टरी आवश्यकता को पूरा करने के लिए स्टील रिफ़ैक्टरी ईकाई के क्षमता विस्तार के लिए सितंबर 2018 में अपना प्रस्ताव नोट प्रस्तुत किया था। प्रस्ताव नोट में इस्पात संयंत्रों में प्रौद्योगिकी परिवर्तनों के अनुरूप उत्पादन क्षमता बढ़ाने और प्रौद्योगिकी के उन्नयन के लिए तत्काल, अल्पकालिक और दीर्घकालिक उपायों के लिए कतिपय पहलुओं पर विचार किया गया था। 2.5 वर्ष बीत जाने के बाद भी अप्रैल 2021 तक इसका पूरी तरह से पालन नहीं किया गया। इस प्रकार सेल रिफ़ैक्टरी ईकाई का उन्नयन न होने के कारण इस्पात संयंत्रों को निजी कंपनियों से आपूर्तिपर निर्भर रहना पड़ा।

1.3.4 चूना डोलोमाइट और ईट संयंत्र का निष्पादन और संवर्धन

राउरकेला इस्पात संयंत्र के चूना डोलोमाइट ईट संयंत्र को 1991 में मैग्नीशिया कार्बन ईटों के उत्पादन के लिए उन्नयन किया गया था। 1991 में प्रत्येक 1,600 टन क्षमता की दो हाइड्रोलिक प्रेस (प्रेस 4 और 5) स्थापित की गई थी। चूना डोलोमाइट ईट संयंत्र से वार्षिक उत्पादन इसकी क्षमता 8,570 टन प्रति वर्ष के प्रति 2015-16 से 2019-20 के दौरान केवल 4,213 टन से 4,910 टन प्रति वर्ष के बीच थी, और राउरकेला इस्पात संयंत्र की औसत वार्षिक आवश्यकता 12,200 टन की थी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि प्रेस 4 और 5 दोनों का 20 वर्षों का उनका उपयोगी कार्यकाल समाप्त हो गया था और उन्हें बार-बार मरम्मत की आवश्यकता थी जो पुर्जों की

अनुपलब्धता के कारण कठिन थी। प्रेस 4 को अगस्त 2017 में बट्टे खाते में डाला गया था। इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी केंद्र, सेल ने ₹19.82 करोड़ की अनुमानित लागत पर मौजूदा 1,600 टन प्रेस को 2,000 टन हाइड्रोलिक प्रेस द्वारा बदलने के लिए एक व्यवहार्यता रिपोर्ट (दिसंबर 2018) प्रस्तुत की। हालांकि, मई 2019 में प्रस्तुत प्रस्ताव को निवेश प्रस्ताव स्क्रीनिंग समिति द्वारा मंजूरी नहीं दी गई थी। प्रेस 5 की खराब स्थिति और लेडल और कनवर्टर ईटों की उच्च मांग को ध्यान में रखते हुए, उपरोक्त प्रस्ताव को निवेश प्रस्ताव स्क्रीनिंग समिति के विचार के लिए फिर से प्रस्तुत किया गया था (17 अगस्त 2019), जिसे फिर से अस्वीकार कर दिया गया था। ईट संयंत्र का उन्नयन न करने और बट्टे खाते में डाले गए प्रेसों के प्रतिस्थापन न करने के परिणामस्वरूप चूना डोलोमाइट ईट संयंत्र से कम उत्पादन हुआ और बाह्य स्रोतों से मैग्नेशिया कार्बन ईटों की अधिप्राप्ति पर निर्भरता जारी रही।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (मई 2021) कि मामले को 2020-21 तक मंजूरी मिलने की उम्मीद थी। मंत्रालय ने बताया (नवंबर 2021) कि प्रस्ताव को जुलाई 2020 में निवेश प्रस्ताव स्क्रीनिंग समिति में रखा गया था, जिसमें यह सुझाव दिया गया था कि एक नया अनुमान तैयार किया जा सकता है। चूंकि यह प्रस्ताव अनुमान की तुलना में बहुत अधिक था, इसलिए नए सिरे से अनुमान तैयार किया जा रहा था ताकि मामले को अनुमोदन के लिए निवेश प्रस्ताव स्क्रीनिंग समिति के समक्ष रखा जा सके।

लेखापरीक्षा में पाया गया है कि 11 महीनों के बाद निवेश प्रस्ताव जांच समिति को प्रस्ताव पुनः प्रस्तुत किया गया था और इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी केन्द्र, सेल की सिफारिश के तीन वर्ष बीत जाने के बाद भी प्रबंधन अनुमानों को संशोधित करने की प्रक्रिया में था।

1.3.5 रिफ़ैक्टरी सामग्री संयंत्रों का निष्पादन और संवर्धन

भिलाई इस्पात संयंत्र में दो रिफ़ैक्टरी सामग्री संयंत्र I और II हैं जो क्रमशः कास्टेबल्स⁹ और मैग्नेशिया कार्बन ईटों का उत्पादन करते हैं। लेखापरीक्षा में पाया गया है कि रिफ़ैक्टरी सामग्री संयंत्रों I और II से उत्पादन 2015-16 से 2019-20 के दौरान उनकी

⁹ कास्टेबल एक प्रकार का रिफ़ैक्टरी है जिसका उपयोग रिफ़ैक्टरी लाइनिंग और स्टील लैंडल, हॉट मेटल लैंडल्स, ब्लास्ट फर्नेस, रीहीटिंग फर्नेस आदि जैसे विभिन्न उपकरणों में लगाने एवं मरम्मत के लिए किया जाता है।

क्षमता का क्रमशः 16 से 97 प्रतिशत और 5 से 12 प्रतिशत के बीच था, जैसा कि नीचे दी गई तालिका में बताया गया है:

तालिका: 1.2

2015-16 से 2019-20 के दौरान रिफ्रैक्टरी सामग्री संयंत्रों की क्षमता और वास्तविक उत्पादन

(इकाइयाँ टन में)

वर्ष	रिफ्रैक्टरी सामग्री संयंत्र I: कास्टेबल			रिफ्रैक्टरीसामग्री संयंत्र II: मैग्नीशिया कार्बन ईंटें		
	क्षमता	वास्तविक उत्पादन	क्षमता से वास्तविक उत्पादन का प्रतिशत	क्षमता	वास्तविक उत्पादन	क्षमता से वास्तविक उत्पादन का प्रतिशत
2015-16	5,000	4,853	97	6,600	648	10
2016-17	5,000	2,791	56	6,600	339	5
2017-18	5,000	2,036	41	6,600	620	9
2018-19	5,000	2,649	53	6,600	686	10
2019-20	5,000	782	16	6,600	794	12
कुल	25,000	13,111	53	33,000	3,087	9

2015-16 से 2019-20 के दौरान, रिफ्रैक्टरी सामग्री संयंत्र I से कुल उत्पादन केवल 13,111 टन (53 प्रतिशत) था, जबकि कास्टेबल की उत्पादन क्षमता 25,000 टन थी। रिफ्रैक्टरी सामग्री संयंत्र II में, मैग्नीशिया कार्बन ईंटों का उत्पादन केवल 3,087 टन (9 प्रतिशत) था, जबकि 2015-16 से 2019-20 के दौरान 33,000 टन की क्षमता थी।

रिफ्रैक्टरी सामग्री संयंत्र-II की रेटेड क्षमता मैग्नेशिया कार्बन ईंटों के लिए 6,600 टन प्रति वर्ष थी, जिसका उत्पादन उपयुक्त मोल्ड एंड डाई की अनुपलब्धता के कारण नहीं किया जा सकता था। लेखापरीक्षा में पाया गया है कि उपर्युक्त के उन्नयन के लिए, ₹35 करोड़ के लिए हाइड्रोलिक प्रेस की अधिप्राप्ति के लिए शुरू किए गए एक प्रस्ताव को स्थगित रखा गया था। हाइड्रोलिक प्रेस की अधिप्राप्ति न होने के कारण भिलाई इस्पात संयंत्र ने सेल रिफ्रैक्टरी ईकाई और निजी पार्टियों से महंगी मैग्नेशिया कार्बन ईंटें खरीदीं।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (मई 2021) कि रिफ्रैक्टरी सामग्री संयंत्र-II में एक नई पीढ़ी की प्रेस स्थापित करने के प्रस्ताव को स्थगित कर दिया गया था क्योंकि इस तरह के प्रेस सेल

रिफ्रैक्टरी ईकाई और सेल रिफ्रैक्टरी कंपनी लिमिटेड में उपलब्ध हैं। मंत्रालय ने आगे कहा (नवंबर 2021) कि सेल रिफ्रैक्टरी ईकाई का उन्नयन उसी समय हो रहा था। इसलिए, रिफ्रैक्टरी सामग्री संयंत्र-II की ईट शॉप के उन्नयन में एक साथ निवेश करना विवेकपूर्ण नहीं समझा गया था।

प्रबंधन/मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सेल रिफ्रैक्टरी इकाई में संवर्धन अभी तक नहीं हुआ था और यदि रिफ्रैक्टरी सामग्री संयंत्र-II का उन्नयन समय पर किया गया होता, तो 33,000 टन मैग्नेशिया कार्बन ईटों (2015-20 के दौरान) के उत्पादन की मौजूदा क्षमता का उपयोग किया जा सकता था। इसके अलावा इस तरह के गैर-उन्नयन के कारण, भिलाई इस्पात संयंत्र ने 2019-20 के दौरान ₹1.55 लाख प्रति टन की दर से ₹81.86 करोड़ मूल्य के निजी स्रोतों से मैग्नीशिया कार्बन ईटों की अधिप्राप्ति की, जो रिफ्रैक्टरीसामग्री संयंत्र II की परिवर्तनीय लागत ₹1.20 लाखप्रति टन से बहुत अधिक थी और इससे बचा जा सकता था।

सिफारिश संख्या 1: कंपनी, इस्पात संयंत्रों की मांग के अनुसार बुनियादी ईटों, मैग्नेशिया कार्बन ईटों, फायरक्ले/उच्च एल्यूमिना ईटों और स्लाइड गेट, सिलिका ईटों आदि जैसे रिफ्रैक्टरियों के लिए संस्थानिक उत्पादन सुविधा को बढ़ाने और उन्नयन करने के लिए कदम उठा सकती है और निजी पार्टियों से खरीदारी से बच सकती है।

1.3.6 संस्थानिक सुविधाओं के अन्य मुद्दे

1.3.6.1 सेल रिफ्रैक्टरी इकाई, समुद्री जल मैग्नेशिया, मैग्नीशिया कार्बन ईटों के लिए कच्चे माल, की केंद्रीय अधिप्राप्ति एजेंसी होने के नाते, जुलाई 2018 से जून 2020 तक चरणबद्ध तरीके से 999 यूरो प्रति टन की दर से दो वर्षों (पहले वर्ष के लिए 11,232 टन और दूसरे वर्ष में 11,218 टन) के लिए 22,450 टन समुद्री जल मैग्नेशिया की आपूर्ति के लिए मैसर्स आरएचआई ऑस्ट्रिया को स्वीकृति पत्र जारी किया गया (जनवरी 2018)।

इस संबंध में, लेखापरीक्षा में पाया गया कि सेल रिफ्रैक्टरी ईकाई ने 2015-16 में एक वर्ष के लिए स्वीकृति पत्र जारी किया था, जब दर 575 यूरो प्रति टन थी और 2016-17 में जब दर 436 यूरो प्रति टन थी। इस प्रकार, जब दर कम थी, सेल रिफ्रैक्टरी ईकाई ने एक वर्ष के लिए प्रतिबद्धता की और जब दर में तेजी से वृद्धि हुई, तो उसने 2018 में दो

वर्ष के लिए ऐसा किया। लेखापरीक्षा ने पाया कि 2019-2020 के दौरान समुद्री जल मैग्नेशिया की कीमत में लगातार गिरावट आई है। 2020 में स्वीकृति पत्र की अवधि की समाप्ति के बाद, कंपनी ने फिर से 505 यूरोप्रति टन की दर से एक वर्ष के लिए स्वीकृति पत्र जारी किया। यदि सेल रिफ़ैक्टरी इकाई ने पिछले वर्षों की तरह 2018-19 में एक वर्ष के लिए स्वीकृति पत्र जारी किया होता, तो कंपनी दूसरे वर्ष में प्राप्त 6,805 टन समुद्री जल मैग्नेशिया के लिए ₹15.80 करोड़ बचा सकती थी।

प्रबंधन/मंत्रालय ने बताया (मई 2021/नवंबर 2021) कि वित्त वर्ष 2017-18 के अंत के दौरान बाजार में व्याप्त अनिश्चितता को देखते हुए और समुद्री जल मैग्नेशिया के लिए कच्चे माल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, सबसे उचित और उपयुक्त निर्णय लिया गया था।

प्रबंधन/मंत्रालय का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि बाजार में अनिश्चितता के मामले में, कंपनी को दो वर्षों के लिए दीर्घकालिक संविदा के लिए नहीं जाना चाहिए था।

1.3.6.2 सेल रिफ़ैक्टरी इकाई, तकनीकी रूप से स्वीकार्य मानदंडों के अनुसार इस्पात संयंत्रों से प्रयुक्त या अस्वीकृत सामग्री का आंशिक रूप से उपयोग करती है ताकि विभिन्न उत्पादों जैसे बुनियादी ईंटों, ड्राइरैमिंग मास, मैग्नेशिया कार्बन ईंटों आदि का उत्पादन किया जा सके। उत्पादन की लागत में कमी के लिए, प्रबंधन ने अपने कच्चे माल अर्थात् क्रमशः डेड बर्नट मैग्नेशिया, रोटरी किलन कैल्साइंड बॉक्साइट और समुद्री जल मैग्नेशिया के स्थान पर उपयोग किए गए बुनियादी ईंट ग्रेग, एल्यूमिना सिलिकेट ग्रेग और मैग्नेशिया कार्बन ईंटों का उपयोग करने के लिए मानदंड निर्धारित किए हैं। प्रयुक्त/अस्वीकृत ईंटों की मात्रा का उपयोग मानक के अनुसार नहीं किया गया था जिसके परिणामस्वरूप कच्चे माल की लागत ₹28.09 करोड़ से अधिक थी। प्रयुक्त सामग्रियों की कम खपत बॉल मिल¹⁰ की कम उपलब्धता और श्रमबल की कमी के कारण थी। लेखापरीक्षा में पाया गया कि बॉल मिल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने में प्रबंधन की असमर्थता के परिणामस्वरूप प्रयुक्त की गई सामग्री की कम खपत हुई।

प्रबंधन/मंत्रालय ने उत्तर दिया (मई 2021/नवंबर 2021) कि अस्वीकृत ईंटों का उपयोग ईंटों और मास की कुछ विशिष्ट गुणवत्ता तक सीमित है और उपयोग सख्ती से गुणवत्ता

¹⁰ बॉल मिल सामग्री को क्रश करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक उपकरण है। प्रयुक्त और नई सामग्री को बॉल मिल में अलग अलग क्रश किया जाता है।

पर आधारित है और इस तरह बजट से वास्तविक उपयोग में मामूली भिन्नता है। यह उपयोग इस्पात संयंत्रों से उपलब्ध प्रयुक्त ईट गोग की मात्रा के अधीन भी है जो हाल के दिनों के दौरान महत्वपूर्ण हो गए थे। सेल रिफ्रेक्टरी ईकाई बोकारो और भिलाई इस्पात संयंत्रों में ईट के गोग के डिस्पोजेबल स्टॉक की समीक्षा करेगी ताकि अंत में इसका संभावित उपयोग किया जा सके।

प्रबंधन/मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यह पाया गया था कि अस्वीकृत ईटों की वास्तविक खपत स्वयं कंपनी द्वारा ऐसी ईटों के उपभोग के लिए निर्धारित मात्रा के वार्षिक लक्ष्य के 9 प्रतिशत से 80 प्रतिशत के बीच थी। इसके अतिरिक्त, बोकारो इस्पात संयंत्र और भिलाई इस्पात संयंत्र (जैसा कि पैरा 1.3.12.2 में प्रकाश डाला गया है) में अस्वीकृत ईटों का भारी भंडार पड़ा हुआ था। इसके अलावा, यह भी पाया गया कि 2015-16 से 2019-20 के दौरान, सभी प्रकार के अस्वीकृत ईटों की खपत निर्धारित लक्ष्य की तुलना में कम थी (2017-18 और 2018-19 के दौरान ईट गोग के संबंध में छोड़कर)।

1.3.6.3 सेल रिफ्रेक्टरी ईकाई में ₹23.94 करोड़ मूल्य की 4,695.17 टन सिलिका ईटें 15-20 वर्षों से अधिक समय से पड़ी थीं। कुल स्टॉक में से, 1,500 टन का उत्पादन भिलाई इस्पात संयंत्र के ऑर्डरके प्रति किया गया था और 3,200 टन सिलिका ईटें अतिरिक्त उत्पादन के कारण संचित हो गई थीं। लेखापरीक्षा में पाया गया कि (i) भिलाई इस्पात संयंत्र के कोक ओवन बैटरी-1 की कोल्ड मरम्मत 2017-18 में की गई थी और (ii) कोक ओवन बैटरी-2 की मरम्मत प्रगति पर थी (मार्च 2020)। तथापि, भिलाई इस्पात संयंत्र ने उपर्युक्त कोक ओवन मरम्मत कार्यों में न तो इन ईटों का उपयोग किया और न ही भंडारों के स्थानांतरण के लिए स्थान आबंटित किया। इसलिए, ये रिफ्रेक्टरियां सेल रिफ्रेक्टरी ईकाई में पड़े थे। प्रबंधन भी अपनी सहायक संयंत्रों या इकाइयों को अतिरिक्त सिलिका ईटों को नहीं बेच सकता था। इस प्रकार, अतिरिक्त उत्पादित सामग्री को बेचने में असमर्थता के परिणामस्वरूप ₹ 23.94 करोड़ अवरुद्ध हो गए।

प्रबंधन/ मंत्रालय ने उत्तर दिया (मई 2021/नवंबर 2021) कि सेल रिफ्रेक्टरी ईकाई सिलिका ईट उत्पादन के अपने ऑर्डरकी बुकिंग के लिए भिलाई इस्पात संयंत्र और अन्य सेल इकाइयों के साथ लगातार संपर्क में थी और यदि समान आकार के साथ कोई आगामी ऑर्डर प्राप्त हुआ था, तो स्टॉक को समाप्त करने की संभावना थी।

प्रबंधन/मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि भिलाई इस्पात संयंत्र ने नियमित रूप से कोक ओवन बैटरी में मरम्मत और रखरखाव किया था और कोक ओवन बैटरी-1 में अंतिम मरम्मत 2017-18 में की गई थी। चूंकि कोक ओवन बैटरी-2 की मरम्मत प्रगति पर थी, प्रबंधन को इन ईंटों के उपयोग की संभावना का पता लगाना चाहिए। इसके अलावा, चूंकि स्टॉक 10-15 वर्ष पुराना था, इसलिए शीघ्रता से इसके उपयोग का पता लगाने की आवश्यकता है, विशेष रूप से इस तथ्य के कारण कि सेल रिफ्रेक्टरी ईकाई ने भी अपने लेखाओं में इन सामग्रियों के लिए प्रावधान किया है।

सिफारिश संख्या 2: प्रबंधन निर्धारित मानदंडों के अनुसार बुनियादी ईंटों, ड्राइ रैमिंग मास, मैग्नेशिया कार्बन ईंटों आदि जैसी प्रयुक्त या अस्वीकृत सामग्री का उपयोग करने के लिए आवश्यक कदम उठा सकता है और सेल रिफ्रेक्टरी ईकाई में रखी पुरानी रिफ्रेक्टरी सिलिका ईंटों का उपयोग करने की संभावना का पता लगा सकता है।

1.3.7 खराब मालसूची प्रबंधन

स्टोर और पुर्जों की मालसूची प्रबंधन, 2017 (नीति 2017) पर नीति दिशानिर्देशों के पैरा 5.2 में निर्धारित किया गया है कि रिफ्रेक्टरी के लिए मालसूची धारिता तीन महीने की खपत के बराबर होनी चाहिए।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 31 मार्च 2020 तक भिलाई, बोकारो, दुर्गापुर, राउरकेला और बर्नपुर में इस्पात संयंत्रों में ₹257.15 करोड़ की अतिरिक्त धारिता थी क्योंकि धारित मालसूची की कीमत ₹578.15 करोड़ थी जो तीन महीने के लिए ₹321 करोड़ के मानदंडों से अधिक थी। इसमें से, ₹34.31 करोड़ मूल्य की मालसूची पांच वर्ष से अधिक समय से अपरिवर्तित रखी हुई थी। बोकारो इस्पात संयंत्र और राउरकेला इस्पात संयंत्र में रखे ₹90.27 करोड़ के अतिरिक्त स्टॉक पर रिफ्रेक्टरी कार्यबल द्वारा उपयोग या निपटान के लिए चर्चा नहीं की गई थी जबकि भिलाई इस्पात संयंत्र में यद्यपि रिफ्रेक्टरी कार्यबल ने इस पर चर्चा की थी, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।

प्रबंधन/मंत्रालय ने स्वीकार किया (मई 2021/नवम्बर 2021) कि समीक्षाधीन अवधि के दौरान मालसूची स्तर मानदंडों से अधिक रहा है, जबकि राउरकेला इस्पात संयंत्र ने उच्च मालसूचीस्तर पर कोई उत्तर नहीं दिया था।

लेखापरीक्षा ने रिफ्रेक्टरी की आवश्यकता के निर्धारण से संबंधित निम्नलिखित को पाया:

1.3.7.1 इस्पात संयंत्रों में रिफ़्रेक्टरी की वार्षिक आवश्यकता का निर्धारण करने के लिए रिफ़्रेक्टरी कार्य बल का गठन किया गया था जिसमें रिफ़्रेक्टरी प्रयोक्ता विभागों, सामग्री प्रबंधन विभाग, वित्त विभाग और रिफ़्रेक्टरी विभाग के सदस्य शामिल थे।

लेखापरीक्षा में पाया गया है कि भिलाई इस्पात संयंत्र, बोकारो इस्पात संयंत्र और राउरकेला इस्पात संयंत्र में रिफ़्रेक्टरी कार्यबल का गठन किया गया था, लेकिन दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, एलाय इस्पात संयंत्र और बर्नपुर में इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी स्टील प्लांट में कार्यबल का गठन नहीं किया गया था। इन तीन संयंत्रों में रिफ़्रेक्टरी विभाग और संबंधित रिफ़्रेक्टरी प्रयोक्ता विभागों द्वारा रिफ़्रेक्टरी की आवश्यकता का निर्धारण किया जा रहा है। सेलम इस्पात संयंत्र में निर्धारण प्रयोक्ता विभागों द्वारा स्वयं किया जाता है। इस प्रकार, विभिन्न इस्पात संयंत्रों में रिफ़्रेक्टरी कार्यबल अथवा किसी अन्य पर्यवेक्षी निकाय के गठन में एकरूपता की कमी थी।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (मई 2021) कि राउरकेला इस्पात संयंत्र में 2005-06 से रिफ़्रेक्टरी कार्यबल के लाभों को देखते हुए, इसे 2015-16 में भिलाई और बोकारो में लागू किया गया था। मंत्रालय ने उत्तर दिया (नवंबर 2021) कि कम आवश्यकता के कारण सेलम इस्पात संयंत्र में रिफ़्रेक्टरी कार्यबल का गठन नहीं किया गया था। बेहतर प्रशासन के लिए दुर्गापुर इस्पात संयंत्र और इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी इस्पात संयंत्र को राउरकेला, बोकारो और भिलाई में इस्पात संयंत्रों के अनुरूप एक कार्यबल बनाने की सलाह पहले ही दी जा चुकी है।

सिफारिश संख्या 3: प्रबंधन यह सुनिश्चित कर सकता है कि कंपनी के सभी इस्पात संयंत्रों में बुनियादी ईंटों, मैग्नीशिया कार्बन ईंटों, फायरक्ले/उच्च एल्यूमिना ईंटों और स्लाइड गेट, सिलिका ईंटों आदि जैसे रिफ़्रेक्टरी की आवश्यकता के निर्धारण के लिए रिफ़्रेक्टरी कार्य बल या किसी अन्य समान पर्यवेक्षी निकाय का गठन किया जाए।

1.3.7.2 बोकारो इस्पात संयंत्र ने कोक ओवन बैटरी-6 की हॉट कॉम्प्लेक्स रिपेयर करने के लिए प्रस्ताव दिया था (जनवरी, 2014), जिसमें सिलिका ईंटों और सिलिका मोर्टार की आवश्यकता की संगणना अनुमान के आधार पर की गई थी। तदनुसार, मैसर्स टीआरएल क्रोसाकी रिफ़्रेक्टरीज लिमिटेड को ₹13.41 करोड़ के लिए खरीदऑर्डर जारी किया गया था (जुलाई 2014)। सामग्री की आपूर्ति (सितम्बर 2014 से नवम्बर, 2014 तक) अनुसूची के अनुसार की गई थी और प्रबंधन ने अक्टूबर-नवम्बर, 2014 के दौरान कोक

ओवन बैटरी-6 की हॉट कॉम्प्लेक्स रिपेयर की थी। लेखापरीक्षा में पाया गया कि ₹13.41 करोड़ के मूल्य के रिफ्रैक्टरियों में से, वास्तविक खपत केवल ₹2.05 करोड़ (15 प्रतिशत) मूल्य की थी। इसके अलावा, उपर्युक्त सामग्री का पूरी तरह से उपभोग किए बिना, बोकारो इस्पात संयंत्र ने कोक ओवन बैटरी-5 और 6 की मरम्मत और रखरखाव के लिए ₹5.82 करोड़ (₹3.67 करोड़ और ₹2.15 करोड़) में रिफ्रैक्टरी (सिलिका ईंटों और सिलिका मोर्टार) की खरीदारी की (जून 2015 तथा नवम्बर 2016)।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि कोक ओवन बैटरी-6 दिसंबर 2017 से पुनर्निर्माण के लिए बंद थी और इन रिफ्रैक्टरियों का उपयोग नहीं किया गया था क्योंकि नई कोक ओवन बैटरी के बाद के पुनर्निर्माण में, रिफ्रैक्टरी सहित सभी सामग्रियों की आपूर्ति निर्माण एजेंसी द्वारा की गई थी। इस प्रकार, सिलिका ईंटों की आवश्यकता के उचित निर्धारण की कमी के कारण मालसूची अवरुद्ध रही।

प्रबंधन ने उत्तर देते हुए (मई 2021) कुछ आमतौर पर उपयोग की जाने वाली सिलिका ईंटों के संबंध में समग्र खपत डेटा प्रस्तुत किया और बताया कि सिलिका ईंटों की खपत न केवल कोक ओवन बैटरी-6 लागत केंद्र में बल्कि अन्य लागत केंद्रों में भी अनजाने में बुक की गई थी।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि प्रबंधन ने कोक ओवन बैटरी-6 के संबंध में लेखापरीक्षा में इंगित किए गए विशिष्ट मामले का उत्तर नहीं दिया था और केवल कुछ आमतौर पर उपयोग किए जाने वाली सिलिका ईंटों की खपत के डेटा को प्रस्तुत किया था। लेखापरीक्षा ने पाया कि सभी तीन खरीद ऑर्डर (जुलाई 2014, जून 2015 और नवंबर 2016) के प्रति दिसंबर 2017 से केवल ₹0.29 करोड़ (1.69 प्रतिशत) मूल्य की सिलिका ईंटों का उपयोग किया गया था।

मंत्रालय ने उत्तर दिया (नवंबर 2021) कि सिलिका ईंटों की मालसूची के लाभप्रद उपयोग के लिए लेखापरीक्षा मुद्दे और कोक ओवन बैटरी-5 की आगामी कोल्ड मरम्मत के दौरान खपत के उचित लेखांकन को संबोधित किया जाएगा।

1.3.7.3 वर्ष 2013-14 के दौरान बोकारो इस्पात संयंत्र द्वारा ₹3.34 करोड़ मूल्य के विभिन्न विनिर्देशों (64421, 74053 और 67881) की फायर क्ले ईंटों की अधिप्राप्ति की

गई थी। लेखापरीक्षा ने पाया कि अक्टूबर 2020 तक ₹2.11 करोड़ की सामग्री की खपत नहीं हुई थी, जो आवश्यकता से अधिक अधिप्राप्तिको दर्शाता है।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (मई 2021) कि कोक ओवन बैटरी 1, 2 और 7 को बेहतर निष्पादन के साथ आधुनिक डिजाइन किए गए डोर में उन्नयन किया गया था, जहां उपरोक्त पारंपरिक आकारों की आवश्यकता नहीं थी। हालांकि, कोक ओवन बैटरी 3, 4 और 5 में बचे हुए स्टॉक को उत्तरोत्तर खपत किया जाएगा। मंत्रालय ने आगे कहा (नवंबर 2021) कि नवंबर 2020 से जून 2021 के दौरान 88.65 टन (₹0.09 करोड़) डोर ईंटों की खपत हुई थी।

प्रबंधन/मंत्रालय का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि कोक ओवन बैटरियों 1 और 2 का उन्नयन क्रमशः जून 2011 और फरवरी 2012 में पूरा कर लिया गया था, जबकि अधिप्राप्ति 2013-14 में की गई थी। इसलिए, प्रबंधन को फायर क्ले ईंटों की अधिप्राप्तिसे पहले उन्नयन के बारे में पता था। उत्तर में इस तथ्य पर भी प्रकाश डाला गया है कि आवश्यकता के गलत निर्धारणके कारण, 2013-14के दौरान अधिप्राप्ति की गई सामग्रियों का पूरी तरह से उपभोग नहीं किया गया था। कंपनी ने ऐसी मालसूची मर्दों में अपनी निविधों को अवरुद्ध कर दिया है और स्थान को अवरुद्ध करने के अलावा इस लेखे में परिहार्य वहन लागत भी जारी रखी है।

1.3.7.4 चीन सरकार ने अप्रैल 2017 से खनन उद्योगों पर क्लैम्पडाउन शुरू की, जिसके परिणामस्वरूप फ्यूज्ड मैग्नेशिया की कमी हो गई, जो स्टील लैडल और कन्वर्टर लाइनिंग रिफ्रैक्टरी के विनिर्माण में उपयोग किया जाने वाला एक प्रमुख कच्चा माल है। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र ने संभावित स्टॉक आउट स्थिति के कारण सीमितनिविदा पूछताछके माध्यम से 20 स्टील लैडल सेटों की आपातकालीन अधिप्राप्ति का निर्णय लिया(13 नवंबर 2017)। इस बीच, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र ने मैसर्स कोस्मोक्राफ्ट को ₹43.64 लाख प्रति सेट पर 60 सेटों के लिए खरीद ऑर्डर जारी किया(17 नवंबर 2017)। इसके बावजूद, इस्पात संयंत्र ने मेसर्स टीआरएल क्रोसाकी रिफ्रैक्टरीज लिमिटेड को ₹55 लाख प्रति सेट पर 20 सेटों के लिए आपातकालीन अधिप्राप्ति ऑर्डर भी प्रस्तुत किया (9 दिसंबर 2017)।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि यद्यपि इस्पात संयंत्र को बाजार में सेटों की कमी के बारे में पता था, लेकिन यह मैसर्स कोस्मोक्राफ्ट के साथ करार करते समय आवश्यकता का सही

निर्धारण करने में विफल रहा और ₹2.27 करोड़ के अतिरिक्त व्यय पर बाद में आपातकालीन अधिप्राप्ति की।

प्रबंधन/मंत्रालय ने उत्तर दिया (मई 2021/नवंबर 2021) कि 20सेटों के लिए आपातकालीन अधिप्राप्ति कार्रवाई की गई थी क्योंकि यह दिसंबर 2017 के दूसरे पखवाड़े में 15-20सेटों के लिए स्टॉक आउट स्थिति और उत्पादन के किसी भी हानि से बचने की अपेक्षा कर रहा था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि मेसर्स कोस्मोक्राफ्ट से अधिप्राप्ति अगस्त 2017 में शुरू की गई थी और निर्धारित सुपुर्दगी 2 जनवरी 2018 से थी, जबकि मेसर्स टीआरएल क्रोसाकी रिफ्रेक्टरीज लिमिटेड से आपातकालीन खरीद का सुपुर्दगी कार्यक्रम 21 दिसंबर 2017 को 10 सेटों और 6 जनवरी 2018 को 10 सेटों के लिए था। इस प्रकार, यदि प्रबंधन ने सामग्री की महत्वपूर्णता को ध्यान में रखते हुए आवश्यकता का निर्धारण किया होता और सुपुर्दगी कार्यक्रम के लिए योजना बनाई होती, तो आपातकालीन अधिप्राप्ति से बचा जा सकता था।



चित्र 1.2: चेकर सिलिका ईंटे

बोकारो इस्पात संयंत्र ने सितंबर 2010 में मेसर्स टीआरएल क्रोसाकी रिफ्रेक्टरीज लिमिटेड से ₹2.57 करोड़ में चेकर सिलिका ईंटों के 1,25,010 टुकड़े खरीदे। सेल रिफ्रेक्टरी यूनिट और मेसर्स टीआरएल क्रोसाकी रिफ्रेक्टरीज लिमिटेड को क्रमशः ₹0.35 करोड़ और ₹0.31 करोड़ के लिए 10,000 टुकड़ों और 14,540 टुकड़ों के लिए दो और ऑर्डर जारी किए गए थे (अगस्त 2011 और मई 2014)। लेखापरीक्षाने पाया कि दूसरे और तीसरे खरीद ऑर्डर जारी करने के समय, चेकर सिलिका ईंटों के क्रमशः 1,21,902 और 46,677 टुकड़ों का स्टॉक उपलब्ध था और बाद के ऑर्डरको देने में औचित्य की कमी थी।

प्रबंधन/मंत्रालय ने उत्तर दिया (मई 2021/नवंबर 2021) कि 2011 में प्रस्तुत किया गया खरीद ऑर्डर स्टोव की अनुमानित आपातकालीन पूंजीगत मरम्मत के लिए परियोजना डिवीजन द्वारा ईंटों की अधिप्राप्ति के लिए था और 2014 के दौरान अधिप्राप्ति निर्माण

डिवीजन द्वारा ब्लास्ट फर्नेस स्टोव की आपातकालीन मरम्मत के लिए की गई थी। शेष ईंटों का उपयोग भविष्य में स्टोव की मरम्मत में किया जाएगा।

प्रबंधन/मंत्रालय के उत्तर में दो विभागों के बीच समन्वय की कमी पर प्रकाश डाला गया है जिसके कारण परिहार्य खरीद हुई। वर्ष 2010-11 में अधिप्राप्ति की गई सामग्री का 10 वर्ष बाद भी उपभोग नहीं हो सका। अक्टूबर 2020 तक ₹1.05 करोड़ मूल्य के 46,077 टुकड़ों का संचय हुआ था।

1.3.7.5 राउरकेला इस्पात संयंत्र ने कोक ओवन बैटरी 1 से 5 की पूंजीगत मरम्मत और कोक ओवन बैटरी-6 के कोक ड्राई कूलिंग प्लांट की रिलाइनिंग के लिए क्रमशः ₹0.87 करोड़ और ₹0.16 करोड़ में फायरक्ले ईंटें प्राप्त की (मार्च 2016 तथा



चित्र 1.3: फायरक्ले ईंटें

नवंबर 2017)। लेखापरीक्षा ने पाया कि कोक

ओवन बैटरी के लिए अधिप्राप्ति किए गए 1,66,000 टुकड़ों की मात्रा में से 1 से 5 तक, ₹0.66 करोड़ मूल्य के 1,19,981 टुकड़ों का उपयोग नहीं किया गया था। कोक ओवन बैटरी-6 के मामले में, सामग्री जारी नहीं की गई थी और स्टोर में रखी थी।

प्रबंधन/मंत्रालय ने उत्तर दिया (मई 2021/नवंबर 2021) कि फायरक्ले ईंटों की कोक ओवन बैटरी 1 से 5 की पुरानी बैटरी की पूंजीगत मरम्मत के लिए अधिप्राप्ति की गई थी। बैटरियों के पुनर्निर्माण के दौरान, डिजाइन को बदल दिया गया था और ईंटें गतिहीन हो गई थीं। इसमें आगे बताया गया है कि भविष्य में कोक ओवन बैटरी-6 में पूंजीगत मरम्मत शुरू की जाएगी, जिसमें सभी ईंटों का उपभोग किया जाएगा।

इस प्रकार, प्रबंधन ने इस तथ्य को स्वीकार कर लिया है कि फायरक्ले की ईंटों के लिए वास्तविक आवश्यकता से अधिक अतिरिक्त अधिप्राप्ति की गई थी जो अप्रचलित हो गई। इसके अलावा, कोक ओवन बैटरी-6 के संबंध में फायरक्ले ईंटों की अधिप्राप्ति सितंबर 2017 में की गई थी, जो अप्रयुक्त भी रखी गई। कंपनी ने ऐसी मालसूची मदों में अपनी निधि को अवरुद्ध कर दिया है और स्थान अवरुद्ध करनेके अलावा, ऐसी मालसूची पर परिहार्य वहन लागत भी जारी है।

सिफारिश संख्या 4: प्रबंधन द्वारा कंपनी द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार मालसूची रखने के प्रयास किए जा सकते हैं और तकनीकी उन्नयन/आधुनिकीकरण योजनाओं के आधार पर मौजूदा मालसूचीधारिता और आवश्यकता के निर्धारण पर विचार करने के बाद अधिप्राप्तिकी जानी चाहिए।

1.3.8 रिफ्रैक्टरियों की अधिप्राप्ति

विक्रेताओं की परिवृद्धि न करना

सेल की खरीद और संविदा प्रक्रिया 2014 के पैरा 19 में अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्धारित किया गया है कि इनपुट सामग्री/सेवाओं की लागत को कम करने की दृष्टि से आपूर्तिके विकल्पों/स्रोतों का पता लगाने और/अथवा उनकी परिवृद्धि करने के लिए संयंत्रों का सतत् प्रयास होगा।

लेखापरीक्षा प्रबंधन द्वारा विक्रेता परिवृद्धि के संबंध में निम्नलिखित को पाया:

1.3.8.1 राउरकेला इस्पात संयंत्र की परीक्षण प्रक्रिया में यह निर्धारित किया गया है कि पहले परीक्षण के सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद, फर्म को दूसरे परीक्षण के लिए विचार किया जाएगा और दो सफल परीक्षणों के बाद, विक्रेताओं पर सामान्य निविदा के लिए विचार किया जाएगा। दो असफल परीक्षणों के मामले में, विक्रेता पर आगे के परीक्षण के लिए विचार नहीं किया जाएगा।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि राउरकेला इस्पात संयंत्र ने 2013 में मूल उपकरण विनिर्माता मैसर्स वेसुवियस से 90 प्रतिशत और परीक्षण विक्रेताओं से 10 प्रतिशत टुंडिश रिफ्रैक्टरी की अधिप्राप्ति करने का निर्णय लिया था। राउरकेला इस्पात संयंत्र ने परीक्षण के आधार पर मैसर्स आईएफजीएल को खरीद आर्डर जारी किया (अक्टूबर 2014), जिसे अप्रैल से दिसंबर 2016 तक सफलतापूर्वक संचालित किया गया था। राउरकेला इस्पात संयंत्र ने परीक्षण के आधार पर मैसर्स आईएफजीएल को सामग्री की आपूर्ति के लिए पुनः खरीद आर्डर जारी किए (जून, 2017)। सितंबर से नवंबर 2017 तक किया गया दूसरा परीक्षण संतोषजनक नहीं था। तत्पश्चात्, मैसर्स आईएफजीएल को कोई परीक्षण आर्डर नहीं दिया गया था। इसके बजाय, परीक्षण आर्डर एक अन्य पार्टी मैसर्स टीआरएल क्रोसाकी रिफ्रैक्टरीज लिमिटेड को प्रस्तुत किया गया था, जिसके साथ पहला और दूसरा परीक्षण जुलाई 2018 और अक्टूबर 2020 के बीच दो साल की अवधि में सफलतापूर्वक

किया गया था। इसलिए, आठ वर्षों में केवल एक विक्रेता की परिवृद्धि की जा सकी थी, जिससे अधिप्राप्ति की जानी बाकी थी।

इसके अलावा, राउरकेला इस्पात संयंत्र ने केवल दो परीक्षणों के विफल होने पर आगे के परीक्षण नहीं करने की अपनी परीक्षण प्रक्रिया का पालन नहीं किया। मैसर्स आईएफजीएल को एक सफल परीक्षण प्राप्त करने के बाद भी आगे के परीक्षणों के लिए विचार नहीं किया गया था। पर्याप्त विक्रेता आधार के अभाव में, राउरकेला इस्पात संयंत्र ने 2013-14 से 2019-20 के दौरान ₹113.39 करोड़ के लिए एकल निविदा के माध्यम से मैसर्स वेसुवियस से टुंडिश रिफ़्रेक्टरी की अधिप्राप्ति की।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (मई 2021) कि मैसर्स आईएफजीएल के दूसरे परीक्षण के बाद, मैसर्स टीआरएल क्रोसाकी रिफ़्रेक्टरीज लिमिटेड के विक्रेता परीक्षण किए गए थे और जैसा कि ये परीक्षण चल रहे थे, मैसर्स आईएफजीएल के साथ परीक्षणों को समायोजित नहीं किया जा सका। मंत्रालय ने बताया (नवंबर 2021) कि कास्टर III टोटल टुंडिश प्रबंधन के लिए दो प्रमाणित विक्रेता उपलब्ध थे। यह अपेक्षित था कि शीघ्र ही एक और विक्रेता परीक्षण शुरू किया जाएगा।

प्रबंधन का उत्तर इस तथ्य को देखते हुए स्वीकार्य नहीं है कि यद्यपि मैसर्स आईएफजीएल का दूसरा परीक्षण नवंबर 2017 में पूरा किया गया था, प्रबंधन ने परीक्षण को आगे जारी नहीं रखा था और इसके बावजूद परीक्षण के लिए अन्य पार्टियों को लगाया। इससे परीक्षण प्रक्रिया पूरी करने में देरी हुई। अगले परीक्षण के लिए मैसर्स आईएफजीएल द्वारा विचार किया जाना शेष है। लेखापरीक्षा ने पाया कि राउरकेला इस्पात संयंत्र 2013-14 से 2020-21 के बीच टुंडिश रिफ़्रेक्टरी के लिए एक प्रमाणित विक्रेता के रूप में सिर्फ एक पार्टी को ही अंतिम रूप दे सका क्योंकि मई 2021 में केवल एक और विक्रेता की पहचान की गई थी।

1.3.8.2 बोकारो इस्पात संयंत्र में नए जीटीसी 2085 रिफ़्रेक्टरी सेट के लिए विक्रेताओं की परिवृद्धि के लिए कोई प्रयास नहीं किए गए थे। नए जीटीसी 2085 रिफ़्रेक्टरी सेट को मैसर्स वेसुवियस से अधिप्राप्त किया गया (2014) और उसके बाद, बोकारो इस्पात संयंत्र ने 2015-20 के दौरान उसी आपूर्तिकर्ता से स्वामित्व आधार पर ₹90.28 करोड़ की अधिप्राप्ति को इस आधार पर जारी रखा कि इसे आपूर्तिकर्ता द्वारा

तीन वर्ष के लिए पेटेंट कराया गया था। लेखापरीक्षा ने पाया कि हालांकि, बोकारो इस्पात संयंत्र के रिफ्रेक्टरी टास्क फोर्स ने 2018-19 से मद को स्वामित्व मुक्त करने का निर्णय लिया (जनवरी 2016) हालांकि, ऐसा नहीं किया गया था।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (मई 2021) कि 2019 के साथ साथ-2020 में भी सहायक इकाइयों से संभावित विक्रेताओं को पंजीकृत करने की संभावना का पता लगाया गया था। विक्रेताओं की अनुपलब्धता के कारण स्वामित्व मुक्त करने की प्रक्रिया में देरी हुई है। मंत्रालय ने बताया (नवंबर 2021) कि जून 2021 में इस मामले को फिर से विक्रेताओं के साथ उठाया गया था।

प्रबंधन/मंत्रालय के उत्तर को तथ्य के इस संदर्भ में देखा जा सकता है कि 2014 से अधिप्राप्त कीजा रही मदों को अभी तक स्वामित्व मुक्त नहीं किया गया था।

सिफारिश संख्या 5: प्रबंधन, एक या सीमित आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भरता से बचने के लिए रिफ्रेक्टरी मदों के लिए नियमित रूप से विक्रेता आधार कोविस्तारित करने का प्रयास कर सकता है।

1.3.9 अधिप्राप्ति प्रक्रिया में विलंब

1.3.9.1 दुर्गापुर इस्पात संयंत्र ने तीन कन्वर्टर लाइनिंग सेटों की अधिप्राप्ति के लिए निविदा आमंत्रित की (जनवरी 2017)। निविदा समिति ने एल1 बोलीदाता, मेसर्स थिंगको हेपिंग सांवाह मिनरल्स कंपनी लिमिटेड को दो सेटों के लिए और एल2 बोलीदाता, मेसर्स पुयांग रिफ्रेक्टरीज ग्रुप कंपनी लिमिटेड को एक सेट के लिए ₹1.97 करोड़ प्रति सेट के लिए अधिप्राप्ति आर्डर देने की सिफारिश की (14 मार्च 2017)। हालांकि, निविदा को अंतिम रूप देने के दौरान, मूल्य वैधता समाप्त हो गई (15 अप्रैल 2017)। एल1 बोलीदाता ने इसकी कीमत वैधता बढ़ा दी जबकि एल2 बोलीदाता ने इसे नहीं बढ़ाया। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र ने एल1 बोलीदाता को तीन सेट के लिए खरीद आर्डर दिया (जून 2017), जो दिसंबर 2017 की निर्धारित अवधि के भीतर तीसरे सेट की आपूर्ति करने में विफल रहा और मई 2019 तक इसकी आपूर्ति की। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र ने मेसर्स कोस्मोक्राफ्ट से ₹4.51 करोड़ प्रति सेट की दर से आपातकालीन आधार पर एक सेट की अधिप्राप्ति की (फरवरी 2018)। मूल्य वैधता अवधि के भीतर निविदा प्रक्रिया को पूरा करने में दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की विफलता के परिणामस्वरूप ₹2.54 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

प्रबंधन/मंत्रालय ने उत्तर दिया (मई 2021/नवंबर 2021) कि ऑर्डर के निष्पादन में देरी मुख्य रूप से मैग्नीशिया के खनन पर चीन के प्राधिकारियों द्वारा सूचित की गई क्लैम्पडाउन की असाधारण स्थिति के कारण हुई थी।

प्रबंधन/मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यह मूल्य वैधता अवधि के भीतर खरीद आर्डर नहीं दे सका और उसके बाद अप्रैल 2017 से चीन सरकार द्वारा क्लैम्पडाउन किए जाने के कारण स्थिति गंभीर हो गई। इसलिए, तथ्य यह रहा कि प्रबंधन, निविदा प्रक्रिया को मूल्य वैधता अवधि के भीतर पूरा नहीं कर सका।

1.3.9.2 राउरकेला इस्पात संयंत्र के लिए 80 लैंडल मैनेजमेंट सेट की अधिप्राप्ति के लिए 14 सितंबर 2017 को तीन फर्मों के बीच रिवर्स आक्शन शुरू की गई थी। शुरुआती बोली मूल्य ₹13.88 लाख प्रति सेट था। चूंकि रिवर्स आक्शन के दो प्रयासों में बोलियां प्राप्त नहीं हुई थीं, प्रबंधन ने मामले को गैर- रिवर्स आक्शन के माध्यम से संसाधित करने का निर्णय लिया (सितम्बर 2017) जिसमें पार्टियों से सीलबंद उद्धृत मूल्य में कमी प्राप्त करने के बाद भौतिक मुहरबंद बोलियां खोली गईं।

लेखापरीक्षा ने पाया कि पार्टियों में से एक, मैसर्स सर्वेश रिफ्रैक्टरीज ने यह कहते हुए (22 सितंबर 2017) कीमत कमी बोली प्रस्तुत नहीं की कि उनकी कीमत अब वैध नहीं थी। मैसर्स सिनो ग्लोबल ने शून्य कटौती के साथ पत्र प्रस्तुत किया और मैसर्स कोस्मोक्राफ्ट ने इसे प्रस्तुत नहीं किया। राउरकेला इस्पात संयंत्र ने मूल बोलियां खोलने का निर्णय लिया जिसमें एल-1 बोली (मैसर्स सर्वेशर फ्रेक्ट्रीज) ₹21.49 लाख प्रति सेट, एल-2, मैसर्स कोस्मोक्राफ्ट, ₹26.47 लाख प्रति सेट और एल-3, मैसर्स सिनो ग्लोबल ₹31.78 लाख प्रति सेट की थी। निविदा समिति ने एल1 बोलीदाता को उस दर को कम करने के लिए कहा (17 अक्टूबर 2017) जिस पर उसकी सहमति नहीं थी क्योंकि मूल्य वैधता समाप्त हो गई थी और क्योंकि चीन में आधारभूत कच्चे माल में तेज वृद्धि थी। हालाँकि, एल 1 बोलीदाता ने सद्भावना के रूप में, केवल 15 सेटों के लिए ₹21.49 लाख प्रति सेट के आर्डर को स्वीकार किया। पुनर्निविदा के पहले चरण में 40 सेटों के लिए प्रति सेट ₹42.87 लाख और दूसरे चरण में 40 सेटों के लिए ₹34.17 लाख प्रति सेट पर पुनर्निविदा दर को अंतिम रूप दिया गया था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि निविदा प्रक्रिया कीमत वैधता तिथि के भीतर पूर्ण नहीं की गई थी। प्रबंधन ने तकनीकी-वाणिज्यिक मूल्यांकन के लिए 11 जुलाई 2017 (निविदा खोलने की तिथि) से 30 अगस्त 2017 तक 50 दिन का समय लिया, हालांकि, राउरकेला इस्पात संयंत्र में मद एक नियमित आवश्यकता थी और विक्रेता पुराने और प्रमाणि थे। 17 अक्टूबर 2017 को मूल्य वार्ता बैठक की गई थी। उस समय तक, कीमत वैधता समाप्त हो चुकी थी और चीन में आधारभूत कच्चे माल में अधिक वृद्धि के कारण, तीनों पार्टियों ने आर्डर को स्वीकार करने के लिए खेद व्यक्त किया था। इसके अलावा, मामले को संसाधित करने में अत्यधिक देरी हुई थी, हालांकि खरीद प्रस्ताव 16 मार्च 2017 को किया गया था। हालांकि, आर्डर को रिवर्स आक्शन मोड के माध्यम से अंतिम रूप दिया जाना था, रिवर्स आक्शन छह महीने के बाद 14 सितंबर 2017 को की गई थी। राउरकेला इस्पात संयंत्र इस बात से अवगत था कि चीन में आधारभूत कच्चे माल की अभूतपूर्व कीमत वृद्धि के कारण बाजार ऊपर की ओर बढ़ रहा था। ऑनलाइन एल-1 मूल्य बोली¹¹ स्वयं ही ₹35 लाख प्रति सेट थी जो पिछले खरीद कीमत से 152 प्रतिशत अधिक थी। इन परिस्थितियों में, प्रबंधन को बाजार की स्थितियों को समझना चाहिए था और निविदा को शीघ्रता से अंतिम रूप देना चाहिए था, जबकि उद्धृत बोली कीमत वैध था। अंतिम रूप देने में अत्यधिक देरी ने बोलीदाता को यह दलील लेने की अनुमति दी कि उनका उद्धृत कीमत अब वैध नहीं थी।

इस प्रकार, निविदा प्रक्रिया को पूरा करने में देरी के कारण, कीमत वैधता अवधि की समाप्ति पुनर्निविदा का कारण बनी और ₹ 10.53 करोड़¹² का अतिरिक्त व्यय हुआ था।

प्रबंधन/मंत्रालय ने उत्तर दिया (मई 2021/नवम्बर 2021) कि विस्तारित निविदा खोलने की तिथि के बावजूद पुनर्निविदा और उचित प्रस्ताव प्रस्तुत न करने के कारण विलम्ब

¹¹ प्रति निलामी के लिए जाने से पहले, मूल दर निर्धारित करने के लिए ऑनलाइन बोली प्राप्त की गई थी।

¹² कुल की गई निविदा मात्रा 80 सेट थी। एल 1 पार्टी ने 15 सेटों की आपूर्ति की। इस प्रकार 65 सेटों की आपूर्ति की जानी बाकी थी। पुनर्निविदा दो चरणों में 80 सेटों के लिए की गई थी (प्रत्येक चरण में 40 सेट)। चूंकि एल 1 पार्टी (मेसर्स सर्वेश रिफ्रेक्ट्रीज) ने 56 सेटों के लिए उद्धृत किया था, लेकिन केवल 15 सेटों की आपूर्ति की थी, इसलिए पुनर्निविदा कीमत और एल 1 कीमत के बीच के अंतर की तुलना 41 (56 -15) सेट (₹8.68 करोड़) के लिए की गई थी। शेष 24 सेटों (₹1.85 करोड़) के लिए पुनर्निविदा कीमत और एल 2 कीमत के अंतर की तुलना की गई थी।

हुआ था। तथ्य यह रहा कि निविदा प्रक्रिया, कीमत वैधता तिथि के भीतर पूर्ण नहीं की गई थी जिसके कारण अतिरिक्त व्यय हुआ।

सिफारिश संख्या 6: अधिप्राप्ति प्रक्रियाओं को निर्धारित समय के भीतर पूरा किया जा सकता है क्योंकि विलम्ब के परिणामस्वरूप बोली कीमत की वैधता समाप्त हो जाती है जिससे अतिरिक्त लागतें आती हैं, जो कंपनी के वित्तीय हित के लिए हानिकारक होती हैं।

1.3.10 लागत लाभ विश्लेषण के बिना अधिप्राप्ति

लेखापरीक्षा ने बाहरी स्रोतों से कंपनी द्वारा रिफ्रेक्टरीज की अधिप्राप्ति के उदाहरणों को देखा, जहाँ सेल रिफ्रेक्टरी इकाई की परिवर्तनीय लागत बाहरी स्रोतों से अधिप्राप्ति की लागत से कम थी। ऐसे ही कुछ उदाहरणों की चर्चा नीचे की गई है:

1.3.10.1 सिलिका ईंटें

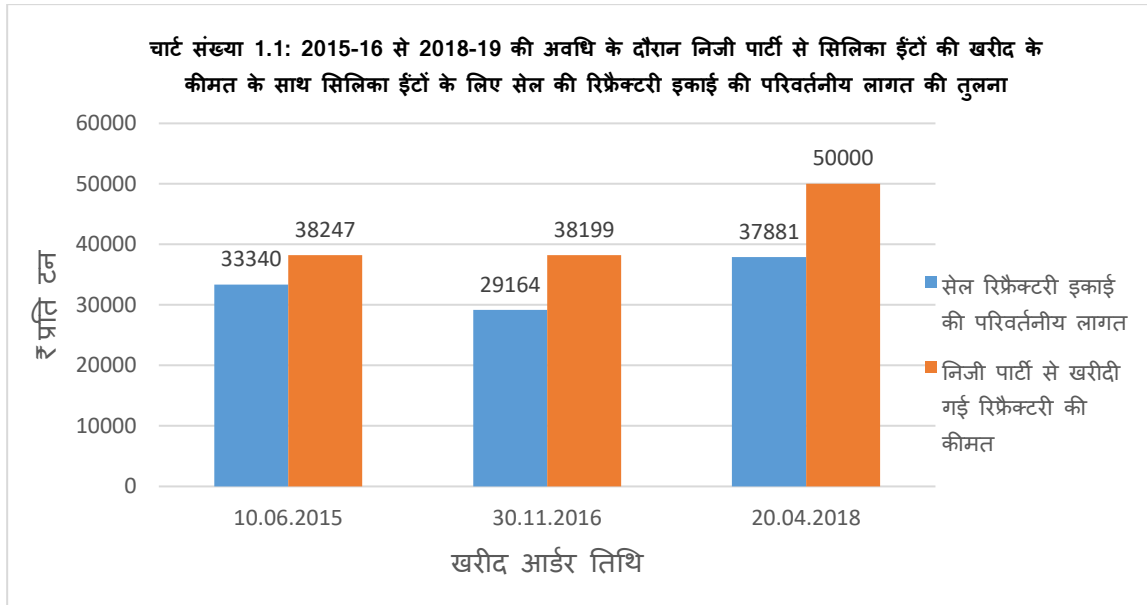
i) बोकारो स्टील प्लांट में, रिफ्रेक्टरी टास्क फोर्स ने दो विक्रेताओं (मैसर्स ओसीएल इंडिया लिमिटेड और मैसर्स टीआरएल क्रोसाकी रेफ्रेक्ट्रीज लिमिटेड) से सिलिका ईंटों की अधिप्राप्ति के लिए सीमित निविदा के माध्यम से इन आपूर्तिकर्ताओं को केवल प्रमाणिक विक्रेता मानते हुए सिफारिश की



चित्र 1.4: सिलिका ईंटें

(2015-18)। 2015-20 के दौरान मैसर्स टीआरएल क्रोसाकी रेफ्रेक्ट्रीज लिमिटेड को ₹7.73 करोड़ के तीन खरीद आर्डर जारी किए गए। लेखापरीक्षा ने पाया कि सेल की रिफ्रेक्टरीज इकाई सिलिका ईंटों का उत्पादन कर रही थी और अन्य सेल संयंत्रों को इसकी आपूर्ति कर रही थी। तथापि, बोकारो इस्पात संयंत्र ने सेल रिफ्रेक्टरी इकाई को सिलिका ईंटों की आवश्यकता के बारे में पर्याप्त और समय पर सूचना नहीं दी और निजी पार्टियों से अधिक कीमत पर अधिप्राप्ति की। संयंत्र ने 6 अप्रैल 2014 से दो महीने के भीतर सेल की रिफ्रेक्टरी यूनिट को 3,427 टन सिलिका ईंटों और 420 टन सिलिका मोर्टार की आपूर्ति करने का अनुरोध किया (31 मार्च 2014)। सेल रिफ्रेक्टरी इकाई ने अपनी असमर्थता व्यक्त की क्योंकि वे भिलाई इस्पात संयंत्र के लिए सिलिका ईंटों का निर्माण कर रहे थे, जो अगस्त/सितंबर 2014 तक जारी रहेगा। लेखापरीक्षा ने पाया कि वर्ष 2015-16, 2016-17 और 2018-19 के लिए सिलिका ईंटों के लिए सेल रिफ्रेक्टरी इकाई की

परिवर्तनीय लागत निजी पार्टी से खरीदी गई सामग्री की लागत से कम¹³ थी जैसा कि नीचे चार्ट में देखा गया है। इस प्रकार, बोकारो इस्पात संयंत्र, सेल रिफ़्रेक्टरी इकाई से सिलिका ईंटें प्राप्त करके ₹ 1.34 करोड़ बचा सकता था।



प्रबंधन/मंत्रालय ने उत्तर दिया (मई 2021/नवंबर 2021) कि सेल की रिफ़्रेक्टरी इकाई ने अन्य सेलइकाइयों के प्रति अपनी पूर्व प्रतिबद्धता के कारण बोकारो इस्पात संयंत्र द्वारा आपेक्षित सुपूर्दगी अनुसूची का पालन करने और सभी आकृति और आकारों की आपूर्ति करने के लिए असमर्थता व्यक्त की। मंत्रालय ने आगे बताया कि सेल की रिफ़्रेक्टरी इकाई को एक संभावित विक्रेता के रूप में नहीं मानना विवेकपूर्ण समझा गया क्योंकि इससे आवश्यक सिलिका ईंटों की अधिप्राप्ति में विलम्ब हो सकता था।

प्रबंधन/मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि बोकारो इस्पात संयंत्र को यह पता था कि प्रत्येक कोक ओवन बैटरी की आकृति और आकार भिन्न होते हैं और इसलिए मरम्मत और रखरखाव के निर्णय के लिए उचित योजना की आवश्यकता होती है। सेल रिफ़्रेक्टरी इकाई को समय पर सूचित किया जाना चाहिए था। इसके अलावा, यह तथ्य कि सेल रिफ़्रेक्टरी इकाई ने एक बार इनकार कर दिया, इस निष्कर्ष का आधार नहीं बन सकता कि यह बार-बार मना करेगा क्योंकि बोकारो इस्पात संयंत्र ने 2015-16 से 2018-

¹³वर्ष 2015-16, 2016-17 और 2018-19 के लिए सिलिका ईंटों के लिए सेल रिफ़्रेक्टरी इकाई की परिवर्तनीय लागत क्रमशः ₹33,340, ₹29,164 और ₹37,881 प्रति टन थी। जून 2015, नवंबर 2016 और अप्रैल 2018 के खरीद आदेशों के लिए निजी पार्टियों से खरीदी गई सामग्री की कीमत क्रमशः ₹38,247, ₹38,199 और ₹50,000 प्रति टन थी।

19 के दौरान कई मौकों पर निजी पार्टियों से उच्च कीमत पर सिलिका ईंटों की अधिप्राप्ति करना जारी रखा। साथ ही, अधिप्राप्ति मामलों को संसाधित करते समय, इस तथ्य का उल्लेख नहीं किया गया था कि सेल रिफ़ैक्टरी इकाई ने आपूर्ति करने से इनकार कर दिया था और इसके बजाय अधिप्राप्ति मामलों में केवल दो प्रमाणिक विक्रेताओं (मैसर्स टीआरएल क्रोसाकी रिफ़ैक्टरीज लिमिटेड और मैसर्स ओसीएल इंडिया लिमिटेड) की उपलब्धता का उल्लेख किया गया था।

ii) दुर्गापुर इस्पात संयंत्र ने 2017 में निर्धारित कोक ओवन बैटरी-3 की कोल्ड रिपेयर के लिए सिलिका ईंटों की आपूर्ति के लिए सेल रिफ़ैक्टरी इकाई पर विचारइस दलील पर नहीं किया, कि सेल रिफ़ैक्टरी इकाई योग्य नहीं थी, और ₹19.31 करोड़ में मैसर्स टीआरएल क्रोसाकी रिफ़ैक्टरीज लिमिटेड को खरीद आर्डर जारी किया (मई 2018)। चूंकि सेल की रिफ़ैक्टरी इकाई सेल संयंत्रों को नियमित रूप से सिलिका ईंटों की आपूर्ति कर रही थी, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र का दावा गलत था। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र सेल रिफ़ैक्टरी इकाई को आर्डर देकर ₹4.87 करोड़¹⁴ बचा सकता था क्योंकि सेल रिफ़ैक्टरी इकाई में उत्पादन की परिवर्तनीय लागत अधिप्राप्ति की लागत से कम थी।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (मई 2021) कि सेल की रिफ़ैक्टरी इकाई ने दुर्गापुर इस्पात संयंत्र द्वारा दी गई निर्धारित अवधि के अनुसार सिलिका ईंटों की आपूर्ति करने में असमर्थता व्यक्त की।

प्रबंधन का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा ने पाया कि दुर्गापुर इस्पात संयंत्र ने सेल रिफ़ैक्टरी इकाई को दिसंबर 2017 से सिलिका ईंटों की आपूर्ति करने के लिए कहा था (मार्च 2017) और सेल रिफ़ैक्टरी इकाई ने प्री-बुकिंग की दलील पर 2017 के दौरान सामग्री की आपूर्ति करने से मना कर दिया था। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र ने जुलाई 2018 से संपूर्ण अवधि के साथ मई 2018 में एक निजी पार्टी को इसके लिए खरीद आर्डर दिया। इस प्रकार, सेल रिफ़ैक्टरी इकाई को संपूर्ण अवधि के पुनर्निर्धारण के बारे में सूचना नहीं दी गई थी।

¹⁴ 4,950 टन *₹39,000 (अधिप्राप्ति लागत) - ₹29,164 (एसआरयू की परिवर्तनीय लागत)} = ₹4.87 करोड़।

1.3.10.2 स्टील लैडल रिफ्रैक्टरीज सेट

i) बोकारो इस्पात संयंत्र ने 2015-20 के दौरान सेल रिफ्रैक्टरी इकाई और बाहरी स्रोतों से स्टील लैडल के लिए रिफ्रैक्टरीज की अधिप्राप्ति की। लेखापरीक्षा ने पाया कि सेल रिफ्रैक्टरी इकाई में स्टील लैडल रिफ्रैक्टरी सेट के उत्पादन की परिवर्तनीय लागत ₹54.61 लाख प्रति सेट थी जो 2018-19 के दौरान ₹88.31 लाख के बाहरी स्रोतों से अधिप्राप्ति लागत से कम थी। यदि रिफ्रैक्टरी टास्क फोर्स ने सेल रिफ्रैक्टरी इकाई की परिवर्तनीय लागत का बाहरी स्रोतों से अधिप्राप्ति लागत के साथ विश्लेषण किया होता और सेल रिफ्रैक्टरी इकाई को आर्डर दिया होता, तो बोकारो इस्पात संयंत्र 2018-19 के दौरान ₹20.07 करोड़ बचा सकता था।



चित्र 1.5: स्टील लैडल रिफ्रैक्टरी

प्रबंधन/मंत्रालय ने उत्तर दिया (मई 2021/नवंबर 2021) कि सेल रिफ्रैक्टरी इकाई लैडल रिफ्रैक्टरी सेट (लगभग 80 हीटें) का औसत उपयोगी कार्यकाल निजी आपूर्तिकर्ताओं (लगभग 110 हीटें) की तुलना में बहुत कम है और समान उपयोगी कार्यकाल के लिए, सेल की रिफ्रैक्टरी इकाई लैडल रिफ्रैक्टरी सेट की लागत के निजी आपूर्तिकर्ता की लागत से अधिक है।

प्रबंधन/मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा ने पाया कि सेल रिफ्रैक्टरी इकाई लैडल रिफ्रैक्टरी सेट की औसत उपयोगी कार्यकाल 101 हीट था जबकि निजी पार्टियों द्वारा आपूर्ति किए गए लैडल रिफ्रैक्टरी सेट का औसत उपयोगी कार्यकाल 105 हीट था। प्रबंधन ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया था कि हीट में अंतर केवल मामूली था। सेल की रिफ्रैक्टरी इकाई लैडल रिफ्रैक्टरी सेट की परिवर्तनीय लागत उसके मामूली कम हीट निष्पादन के बाद भी बाहर से अधिप्राप्ति लागत से सस्ती थी।

ii) दुर्गापुर इस्पात संयंत्र ने मई 2018 में निजी पार्टियों से ₹45.22 लाख प्रति सेट पर 180 स्टील लैडल रिफ्रैक्टरी सेट की अधिप्राप्ति की, लेकिन सेल रिफ्रैक्टरी इकाई को आर्डर नहीं दिया। लेखापरीक्षा ने पाया कि इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी इस्पात संयंत्र, एक नजदीकी संयंत्र, ने अप्रैल 2018 में सेल रिफ्रैक्टरी इकाई से ₹38.97 लाख प्रति सेट

की दर से 130 स्टील लैडल रिफ़ैक्टरी सेट की अधिप्राप्ति की। सेल की रिफ़ैक्टरी इकाई से 180 स्टील लैडल रिफ़ैक्टरी सेटों की अधिप्राप्ति न करने के परिणामस्वरूप ₹8.55 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ है।

प्रबंधन/मंत्रालय ने उत्तर दिया (मई 2021/नवंबर 2021) कि सेल रिफ़ैक्टरी इकाई को उसकी वार्षिक कारोबार योजना 2018-19 के दौरान लैडल रिफ़ैक्टरी सेट की आपूर्ति के लिए संपर्क किया गया था, लेकिन सेल रिफ़ैक्टरी इकाई आवश्यकता के अनुसार आपूर्ति के लिए सहमत नहीं थी। इसने आगे बताया कि सेल की रिफ़ैक्टरी इकाई ने इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी इस्पात संयंत्र को इसकी आपूर्ति के लिए कोई हीट गारंटी नहीं दी थी और रिफ़ैक्टरी के उपयोग की भी प्लांट द्वारा अलग से व्यवस्था की गई थी। जबकि दुर्गापुर इस्पात संयंत्र में निजी विक्रेताओं ने हीट गारंटी के साथ लैडल रिफ़ैक्टरी सेट की आपूर्ति की और लैडल का परिचालन भी उनके कार्यक्षेत्र में था। इसलिए, सेल रिफ़ैक्टरी इकाई से इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी इस्पात संयंत्र द्वारा अधिप्राप्त किए गए लैडल रिफ़ैक्टरी सेट की लागत की तुलना दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की बाहरी विक्रेता से अधिप्राप्ति से नहीं की जा सकती है।

प्रबंधन/मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि दुर्गापुर इस्पात संयंत्र ने जनवरी 2018 में 180 स्टील लैडल रिफ़ैक्टरी सेटों के लिए खरीद प्रक्रिया शुरू की थी, जबकि उसने उसी महीने केवल 60 सेटों के लिए सेल रिफ़ैक्टरी इकाई से संपर्क किया था। इसके अलावा, लेखापरीक्षा ने रिफ़ैक्टरी के उपयोग के लिए प्रभारों पर भी विचार किया जो निजी एजेंसी को देय होगा और इसे ध्यान में रखने के बाद भी, यह पाया गया था कि सेल रिफ़ैक्टरी इकाई की लागत सस्ती थी। प्रबंधन/मंत्रालय के उत्तर को इस तथ्य को इस संदर्भ में देखा जा सकता है कि सेल के अन्य इस्पात संयंत्र इस अवधि के दौरान सेल की रिफ़ैक्टरी इकाई को आर्डर दे रहे थे।

1.3.10.3 ट्रफ एंड रन्नर कास्टेबल सेट

बोकारो इस्पात संयंत्र ने ₹20.16 करोड़ में ब्लास्ट फर्नेस-5 की स्थापना और मरम्मत के लिए ट्रफ और रन्नर कास्टेबल सेट की खरीद के लिए मेसर्स काल्डेरीज इंडिया रिफ्रैक्टरीज लिमिटेड को खरीद आर्डर जारी किया (सितंबर 2019)। लेखापरीक्षा ने पाया कि निविदा दस्तावेज खोलने से पहले, सेल रिफ्रैक्टरी इकाई ने कार्य निष्पादित करने की इच्छा व्यक्त की (फरवरी 2019)। इसके अलावा,



चित्र 1.6: कास्टेबल

बोकारो इस्पात संयंत्र ने सेल रिफ्रैक्टरी इकाई को प्री-कास्ट प्री-फायर्ड ब्लॉकों के साथ ब्लास्ट फर्नेस 1 में रिफ्रैक्टरी कास्टेबल और रन्नर सेट के दो सेटों की स्थापना, अनुप्रयोग और मरम्मत का कार्य पहले दिया था (फरवरी 2019) और यह ब्लास्ट फर्नेस 3 और 4 के दोनों कास्ट हाउस की आवश्यकता को पूरा कर रहा था। हालांकि, बोकारो इस्पात संयंत्र ने इस आधार पर प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया (मार्च 2019) कि उसे कास्ट हाउसों के ट्रफ की मरम्मत और रखरखाव पर सेल रिफ्रैक्टरी इकाई के साथ कोई अनुभव नहीं था, जहां प्री-कास्ट प्री-फायर ब्लॉक लागू किया गया था।

प्रबंधन/मंत्रालय ने उत्तर दिया (मई 2021/नवंबर 2021) कि बोकारो इस्पात संयंत्र को कास्टेबल सेल रिफ्रैक्टरी इकाई के निष्पादन का कोई अनुभव नहीं था और बाहरी आपूर्तिकर्ताओं के साथ जाना विवेकपूर्ण था।

उत्तर इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए यह स्वीकार्य नहीं है कि सेल की रिफ्रैक्टरी इकाई ने स्पष्ट रूप से बताया (फरवरी 2019) कि यह बोकारो इस्पात संयंत्र, भिलाई इस्पात संयंत्र, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र और राउरकेला इस्पात संयंत्र की आपूर्ति सह अनुप्रयोग आधार पर लंबे समय से कास्टेबल ब्लास्ट फर्नेस ट्रफ की आवश्यकता को पूरा कर रहा था। इसके अलावा इसमें ब्लास्ट फर्नेस 5 के दोनों कास्ट हाउस की मांग को पूरा करने की अतिरिक्त क्षमता थी और ब्लास्ट फर्नेस 1 के लिए किए गए प्री-कास्ट प्री-फायर ब्लॉकों की आपूर्ति करने का आश्वासन दिया। सेल की रिफ्रैक्टरीज इकाई उपयोग कार्य की देखभाल के लिए ब्लास्ट फर्नेस क्षेत्र में सेवा दल तैनात कर रही थी। इस आश्वासन और आंतरिक स्रोतों से सामग्री की उपलब्धता के बावजूद, बोकारो इस्पात संयंत्र ने बिना किसी वैध आधार के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और एक निजी पार्टी को कार्य सौंप दिया।

इसलिए, कंपनी ने बाहरी स्रोतों से उच्च लागत पर अधिप्राप्ति के कारण अतिरिक्त व्यय किया, जब अप्रयुक्त क्षमता आंतरिक रूप से उपलब्ध थी।

सिफारिश संख्या 7: उत्पादन योजना को इस्पात संयंत्रों और रिफ्रेक्टरी इकाइयों के बीच सिंक्रनाइज़ किया जा सकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आंतरिक सुविधाओं का पूर्ण उपयोग किया जा सके और बाहरी खरीद कम से कम हो।

1.3.10.4 राउरकेला इस्पात संयंत्र द्वारा गैर उपलब्ध-आंतरिक सुविधाओं द्वारा अधिप्राप्ति

राउरकेला इस्पात संयंत्र ने कोक ओवन बैटरी-5ए की हॉट मरम्मत का निर्णय लिया (अगस्त 2016) और सेल रिफ्रेक्टरी इकाई से मार्च 2017 तक सिलिका ईंटों की आपूर्ति करने का अनुरोध किया। सेल रिफ्रेक्टरी इकाई ने सूचित किया (सितंबर 2016) कि बड़ी संख्या और जटिल आकृतियों के कारण जो उन्होंने हाल के दिनों में नहीं बनाए थे। सामग्री की आपूर्ति सितंबर 2017 और दिसंबर 2017 के बीच की जा सकती है। हालांकि, आवश्यकता की तात्कालिकता पर विचार करते हुए, राउरकेला इस्पात संयंत्र ने 25 सितंबर 2017 से 31 मार्च 2018 की संपूर्ण अवधि के साथ सामग्री (₹ 0.92 करोड़) की खरीद (सितंबर 2017) की। इसी तरह, कोक ओवन बैटरी-5बी, राउरकेला के हॉट फ्ल्यू लाइनिंग के लिए इस्पात संयंत्र ने सिलिका ईंटों की आपूर्ति के लिए सेल रिफ्रेक्टरी इकाई से अनुरोध किया (जुलाई 2018)। हालांकि, सेल रिफ्रेक्टरी इकाई (अगस्त 2018) ने पहले की तरह ही समान आधार का हवाला दिया। राउरकेला इस्पात संयंत्र ने मार्च 2020 तक निर्धारित संपूर्ण अवधि के साथ एक वर्ष के बाद मेसर्स डालमिया सीमेंट (भारत) लिमिटेड को ₹5.73 करोड़ के लिए खरीद आर्डर दिया (अगस्त 2019)।

लेखापरीक्षा ने पाया कि कोक ओवन बैटरी-5ए के लिए राउरकेला इस्पात संयंत्र ने मार्च 2018 तक आपूर्ति अवधि के साथ आर्डर दिया था, हालांकि सेल रिफ्रेक्टरी इकाई दिसंबर 2017 तक इसकी आपूर्ति करने के लिए तैयार थी। सेल रिफ्रेक्टरी इकाई को इसकी वार्षिक कारोबार योजना में मरम्मत योजना के बारे में पूर्व में सूचित नहीं किया गया था। इस प्रकार, सेल की रिफ्रेक्टरीज इकाई उनके उत्पादन की योजना बनाने में सक्षम नहीं थी और कंपनी को बाहरी आपूर्तिकर्ताओं से अधिप्राप्ति करनी पड़ी थी।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (मई 2021) कि सेल की रिफ्रैक्टरी इकाई के पास राउरकेला इस्पात संयंत्र को ईंटों की आपूर्ति करने में तकनीकी बाधाएँ थीं और उन्हें अपनी प्रक्रिया को संशोधित करने के लिए एक वर्ष से अधिक की आवश्यकता थी। मंत्रालय ने आगे बताया (नवम्बर 2021) कि विक्रता से आपूर्ति दिसंबर 2017 से काफी पहले पूरी होने की उम्मीद थी और यह बताया कि देरी निविदा प्रक्रिया के कारण थी न कि संपूर्ण अवधि के कारण।

उत्तर इस तथ्य को देखते हुए स्वीकार्य नहीं है कि राउरकेला इस्पात संयंत्र ने मार्च 2018 तक निर्धारित संपूर्णता के साथ बाहरी स्रोतों से रिफ्रैक्टरियों (5ए-कोक ओवन बैटरी के लिए) की अधिप्राप्ति की, जबकि सेल रिफ्रैक्टरी इकाई दिसंबर 2017 तक इसकी आपूर्ति करने के लिए तैयार थी। जैसेकि निविदा प्रक्रिया में विलम्ब हो रहा था, प्रबंधन को निर्धारित अवधि के भीतर इसकी आपूर्ति के लिए सेल रिफ्रैक्टरी इकाई से परामर्श करना चाहिए था। इसके अलावा, सेल रिफ्रैक्टरी इकाई कोक ओवन बैटरी-5बी के लिए भी शेप मोल्ड तैयार कर सकती है, दोनों आकार और प्रौद्योगिकी में समान है।

1.3.11 रिफ्रैक्टरियों का उपयोग

1.3.11.1 भिलाई इस्पात संयंत्र में टोटल लैडल प्रबंधन के क्रियान्वयन में देरी

भिलाई इस्पात संयंत्र विभिन्न एजेंसियों से लैडल, स्लाइड गेट, पोरस प्लग और अन्य आवश्यक रिफ्रैक्टरियों के लिए रिफ्रैक्टरी की अधिप्राप्ति करता है और रिफ्रैक्टरियों की गुणवत्ता/बेमेलता के अंतर के कारण, निष्पादन की पूरी क्षमता की उम्मीद नहीं थी। इसलिए इसने कुल लैडल प्रबंधन के लिए प्रस्तावित किया (जनवरी 2015) जिसमें (i) लैडल लाइनिंग रिफ्रैक्टरी, (ii) पर्जिंग रिफ्रैक्टरी और (iii) स्लाइड गेट रिफ्रैक्टरी जिसमें (क) उपयुक्त गारंटी क्लॉज को लागू करके रिफ्रैक्टरी की गुणवत्ता का आश्वासन (ख) मध्य-अभियान मरम्मत को कम करके लैडल उपलब्धता में सुधार और (ग) उच्च लैडल उपयोगी कार्यकाल के लाभदायक तंत्र शामिल है। भिलाई इस्पात संयंत्र ने परिकल्पना की (फरवरी 2017) कि कुल लैडल प्रबंधन के बाद, प्रति सेट हीट मौजूदा 54.41 से बढ़कर 65 हो जाएगी और प्रति हीट¹⁵ ₹17,832.73 की लागत की बचत होगी।

¹⁵ प्रबंधन ने गणना की है कि कुल लैडल प्रबंधन के तहत ₹58,746.06 प्रति हीट अनुमानित लागत थी और मौजूदा स्थिति के अनुसार ₹76,578.79 प्रति हीट लागत थी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि जनवरी 2015 में शुरू किए गए कुल लैडल प्रबंधन के प्रस्ताव को सितंबर 2016 में अनुमोदित किया गया था। परीक्षण खरीद आर्डर दिसंबर 2018 और फरवरी 2019 में दिए गए थे। इस प्रकार, प्रबंधन को खरीद आर्डर जारी करने के अनुमोदन से ढाई वर्ष तक का समय लगा।

लेखापरीक्षा ने पाया कि दोनों परीक्षण खरीद आदेशों में प्राप्त हीट, 65 की परिकल्पित हीट के मुकाबले 65 और 115 के बीच थी। इस प्रकार, परीक्षण निष्पादन से पता चला कि कुल लैडल प्रबंधन भिलाई इस्पात संयंत्र के लिए फायदेमंद था। क्रय/संविदा प्रक्रिया, 2014 के पैरा 13.5 में निर्धारित किया गया है कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा संविदा/क्रय आर्डर प्रदान करने का समय अनुशंसा प्रस्तुत करने की तिथि से एक माह से अधिक नहीं होना चाहिए। हालांकि, भिलाई इस्पात संयंत्र को खरीद आर्डर देने में 26 महीने (सितंबर 2016 से दिसंबर 2018) लगे। यदि भिलाई इस्पात संयंत्र ने निर्धारित समय के भीतर आर्डर दिया होता, तो कंपनी 24 महीने (जनवरी 2017 से दिसंबर 2018) के लिए ₹19.47 करोड़¹⁶ बचा सकती थी। इसके अलावा, हालांकि भिलाई इस्पात संयंत्र ने परीक्षण शुरू किया जिसने परिकल्पित लाभों की पुष्टि की, बोकारो इस्पात संयंत्र, राउरकेला इस्पात संयंत्र और एलॉय इस्पात संयंत्र ने अपने संबंधित संयंत्रों में कुल लैडल प्रबंधन के परीक्षण के लिए कोई प्रयास नहीं किया है।

प्रबंधन/मंत्रालय ने उत्तर दिया (मई 2021/नवंबर 2021) कि भिलाई इस्पात संयंत्र में विक्रेताओं द्वारा सामग्री का बिल देरी से जमा करने के कारण विलम्ब हुआ था। बोकारो इस्पात संयंत्र द्वारा लेखापरीक्षा सुझावों पर विचार किया जाएगा। राउरकेला इस्पात संयंत्र में लैडल रिफ़ैक्टरी प्रबंधन और लैडल परिचालन रिफ़ैक्टरी प्रबंधन की प्रणाली थी। दोनों प्रणालियों को मिलाकर कुल लैडल प्रबंधन अलाभप्रद हो सकता है क्योंकि विक्रेता आधार दोनों के लिए अलग था और बहुत कम सामान्य विक्रेता उपलब्ध थे। एलॉय इस्पात संयंत्र में लैडल प्रबंधन प्रचलित है।

¹⁶ ₹19.47 करोड़ = ₹17,832.73 * 2,730 हीट * 4 (जैसा कि 2,730 हीट छह महीने की अवधि के लिए हैं और हानि की गणना दो साल के लिए की जा रही है)। ₹17,832.73 प्रति हीट मौजूदा स्थिति में लागत प्रति हीट के बीच अंतर के रूप में लिया गया है: ₹76,578.79 और कुल लैडल प्रबंधन के तहत प्रति हीट अनुमानित लागत: ₹58,746.06 है। प्रबंधन ने अनुमान लगाया है कि टोटल लैडल प्रबंधन के तहत 2,730 हीट प्रस्तावित परीक्षण आर्डर के संबंध में छह महीने की अवधि को कवर करेंगे।

प्रबंधन/मंत्रालय के उत्तर को इस तथ्य के संदर्भ में देखा जा सकता है कि भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा खरीद आर्डर देने में विलम्ब हुआ था। हालांकि, प्रबंधन द्वारा टोटल लैडल प्रबंधन को लाभकारी पाया गया, लेकिन राउरकेला इस्पात संयंत्र और एलॉय इस्पात संयंत्र में इसे क्रियान्वित नहीं किया गया है।

सिफारिश संख्या 8: प्रबंधन द्वारा टोटल लैडल प्रबंधन को लाभकारी पाया गया और इसलिए राउरकेला इस्पात संयंत्र और एलॉय इस्पात संयंत्र इसके कार्यान्वयन की व्यवहार्यता का मूल्यांकन कर सकते हैं।

1.3.11.2 भिलाई इस्पात संयंत्र में नई पीढ़ी के स्लाइड गेट सिस्टम के आंशिक क्रियान्वयन के कारण अतिरिक्त व्यय

लैडल स्लाइड गेट रिफ्रैक्टरी प्रणाली लिक्विड स्टील कास्टिंग में प्रवाह नियंत्रण उपकरण का एक महत्वपूर्ण प्रकार है। लैडल स्लाइड गेट प्रणाली का मूल कार्य लैडल से टुंडिश¹⁷ तक लिक्विड स्टील के प्रवाह को नियंत्रित करना है। 2009 तक, भिलाई इस्पात संयंत्र की स्टील मेल्टिंग शॉप-2 पारंपरिक प्रकार के स्लाइड गेट प्रणाली अर्थात् फ्लोकन 6300 का उपयोग कर रही थी। 2009 में एक नई पीढ़ी की स्लाइड गेट प्रणाली को पारंपरिक प्रणाली पर कई हीट विश्वसनीयता और प्रति हीट पर्याप्त लागत में कमी के लाभ के साथ प्रस्तुत किया गया था। लाभों को दृष्टिगत रखते हुए, भिलाई इस्पात संयंत्र ने 2014-15 से नई पीढ़ी के स्लाइड गेट प्रणाली के 100 प्रतिशत उपयोग के लिए प्रस्तावित किया (दिसंबर 2013)।



चित्र:1.7: नई पीढ़ी के स्लाइड गेट सिस्टम

लेखापरीक्षा ने पाया कि भिलाई इस्पात संयंत्र ने इसे पूरी तरह से क्रियान्वित नहीं किया था। 2015-20 के दौरान नई पीढ़ी के स्लाइड गेट प्रणाली के लिए की गई अधिप्राप्ति का मूल्य स्लाइड गेट रिफ्रैक्टरी की कुल अधिप्राप्ति के मूल्य का 60 प्रतिशत था। यह 2009-15 के दौरान नई पीढ़ी के स्लाइड गेट प्रणाली की अधिप्राप्ति से केवल मामूली अधिक

¹⁷ तल में एक या एक से अधिक छेद वाले एक चौड़े धातु के कंटेनर का उपयोग पिघली हुई धातु को एक इंगोट मोल्ड में डालने के लिए किया जाता है ताकि छींटे से बचा जा सके और एक चिकना प्रवाह दिया जा सके।

था, जो कि 57 प्रतिशत था। यह भी पाया किया गया कि 2015-20 के दौरान पुरानी प्रणाली में ₹5,864 और ₹6,507 प्रति हीट के प्रति नई प्रणाली में प्रति हीट लागत ₹4,370 और ₹6,187 के बीच थी। इस प्रकार, 2015-20 के दौरान, नई पीढ़ी के स्लाइड गेट प्रणाली के 100 प्रतिशत उपयोग को प्राप्त करने में असमर्थता के परिणामस्वरूप ₹3.41 करोड़¹⁸ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

प्रबंधन/मंत्रालय ने उत्तर दिया (मई 2021/नवंबर 2021) कि चूंकि स्लाइड गेट रिफ्रेक्टरीज उत्पादन से जुड़े महत्वपूर्ण उपभोज्य हैं, इसलिए पूरी तरह से निजी विक्रेताओं पर निर्भर रहना विवेकपूर्ण नहीं था। सेल की रिफ्रेक्टरीज इकाई से अधिप्राप्ति को नीतिगत रूप से निजी आपूर्तिकर्ताओं के प्रति जोखिम बीमा के रूप में 30 प्रतिशत से 40 प्रतिशत तक रखा गया था। हालांकि, भिलाई इस्पात संयंत्र अब टोटल लैडल प्रबंधन के आधार पर लैडल रिफ्रेक्टरीज की अधिप्राप्ति करने जा रहा था।

प्रबंधन/मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है। सेल की रिफ्रेक्टरी इकाई को उत्पादन क्षमता में वृद्धि करनी थी ताकि भिलाई इस्पात संयंत्र की नई पीढ़ी के स्लाइड गेट प्रणाली की पूरी आवश्यकता सेल रिफ्रेक्टरी इकाई द्वारा पूरी की जा सके। हालांकि, सेल की रिफ्रेक्टरी इकाई द्वारा 2017 में जारी रुचि की अभिव्यक्ति को छोड़कर आज तक कोई पहल नहीं की गई थी, जिसका कोई परिणाम नहीं निकला। प्रबंधन का यह तर्क कि ऐसी महत्वपूर्ण वस्तु के लिए पूरी तरह से बाहरी विक्रेताओं पर निर्भर रहना विवेकपूर्ण नहीं होगा, इस तथ्य के सन्दर्भ में देखा जा सकता है कि कुल लैडल प्रबंधन के तहत, नई पीढ़ी की स्लाइड गेट प्रणाली पूरी तरह से निजी पार्टियों से खरीदे जा रही हैं।

1.3.12 अन्य मामलें

1.3.12.1 दुर्गापुर इस्पात संयंत्र में जोखिम खरीद के प्रति आपूर्तिकर्ता से ₹17.41 करोड़ की वसूली न होना

दुर्गापुर इस्पात संयंत्र ने अक्टूबर 2017 की निर्धारित सपूर्दगी तिथि के साथ ₹19.12 लाख प्रति सेट पर 144 सेट के लिए मैसर्स ओरिंद स्पेशल रिफ्रेक्टरीज पर स्टील लैडल सेट लाइनिंग रिफ्रेक्टरीज के लिए खरीद आर्डर जारी किया (नवंबर 2016)। मैसर्स ओरिंद

¹⁸ नई स्लाइड गेट रिफ्रेक्टरी प्रणाली की लागत प्रति हीट और पारंपरिक स्लाइड गेट रिफ्रेक्टरी प्रणाली की लागत प्रति हीट के बीच अंतर पारंपरिक स्लाइड गेट रिफ्रेक्टरी प्रणाली की वास्तविक खपत के साथ गुणा किया जाता है।

स्पेशल रिफ्रेक्टरीज ने 65 सेटों की आपूर्ति नहीं की। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र ने मेसर्स टीआरएल क्रोसाकी रिफ्रेक्टरीज लिमिटेड से ₹50 लाख प्रति सेट की दर से 60 सेट की अधिप्राप्ति की (फरवरी 2018)। हालांकि, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र ने केवल अन्य 47 सेटों के लिए खरीद आदेशों के आधार पर एक वर्ष के बाद जोखिम खरीद नोटिस जारी किया (सितंबर 2018) जो मेसर्स टीआरएल क्रोसाकी रिफ्रेक्टरीज लिमिटेड और मैसर्स सर्वेश रिफ्रेक्टरीज को प्रति सेट ₹21.50 लाख पर जारी किए गए थे और मेसर्स ओरिंद स्पेशल रिफ्रेक्टरीज से ₹1.12 करोड़¹⁹ की वसूली की। लेखापरीक्षा ने पाया कि दुर्गापुर इस्पात संयंत्र फरवरी 2018 में की गई खरीद के आधार पर ₹ 50 लाख प्रति सेट की दर से जोखिम खरीद के प्रति वसूली राशि की गणना कर सकता था। इस प्रकार, जोखिम खरीद राशि के गलत आरोपण के कारण ₹17.41 करोड़ की कम वसूली हुई।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (मई 2021) कि मैसर्स ओरिंद स्पेशल रिफ्रेक्टरीज की निरंतर विफलता के कारण, शेष 47 सेटों के लिए जोखिम खरीद की गई थी और प्रक्रिया के अनुसार, विक्रेता से ₹ 1.12 करोड़ की अंतर राशि वसूली की गई थी। मंत्रालय ने बताया (नवंबर 2021) कि ऐसे सभी विक्रेताओं के प्रति किसी भी जोखिम खरीद कार्रवाई से दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के अलावा अन्य सेल संयंत्रों को भी इस तरह के महत्वपूर्ण उत्पादन से जुड़े मद की आपूर्ति प्रभावित होगी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि आपूर्तिकर्ता द्वारा निर्धारित सपूर्दगी अवधि (अक्टूबर 2017)के भीतर आपूर्ति करने में विफलता के बाद, कंपनी को जोखिम खरीद कार्रवाई करनी चाहिए थी क्योंकि कंपनी को उच्च लागत पर स्टील लैडल सेट लाइनिंग रिफ्रेक्ट्रीज की अधिप्राप्ति करनी थी। हालांकि, जोखिम खरीद कार्रवाई तब की गई जब दर कम थी जो विक्रेता के अनुकूल थी और कंपनी के लिए अलाभप्रद थी।

1.3.12.2 बोकारो इस्पात संयंत्र और भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा ₹36.51 करोड़ मूल्य की स्क्रेप ईंटों का निपटान न करना

सेल, संयंत्र के अंदर रिलाइनिंग कार्यों के लिए विभिन्न प्रकार की रिफ्रेक्ट्रीज ईंटों की अधिप्राप्ति करता है। कुछ गारंटीकृत मापदंडों को प्राप्त करने और आकार में कमी और भौतिक और रासायनिक गुणों में परिवर्तन के बाद, ईंटें आगे उपयोग के लिए अनुपयुक्त

¹⁹ ₹1.12 करोड़ की वसूली मेसर्स ओरिंद स्पेशल रिफ्रेक्ट्रीज से की गई थी क्योंकि फरवरी 2020 तक इसके द्वारा 18 और सेटों की आपूर्ति की गई थी और केवल 47 सेटों की सपूर्दगी नहीं हुई थी।

हो जाती हैं। इन ईंटों को तब स्क्रेप के रूप में घोषित किया जाता है और लॉट के निर्माण के लिए मुख्य स्टोर में स्थानांतरित कर दिया जाता है और इसे निपटान के लिए मार्केटिंग विंग को सौंप दिया जाता है। सेल का अपना रिफ़ैक्टरी प्लांट भी है जहां इन स्क्रेप की गई ईंटों की निर्माण लागत को कम करने के लिए कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है। लेखापरीक्षा ने पाया कि बोकारो इस्पात संयंत्र में ₹26.61 करोड़ मूल्य की 57,839 टन और भिलाई इस्पात संयंत्र में ₹9.90 करोड़ मूल्य की 7,761 टन स्क्रेप ईंटों का स्टॉक था। राउरकेला इस्पात संयंत्र और दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के मामले में, इस्तेमाल की गई ईंटों को नियमित रूप से बेचा जाता था।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (मई 2021) कि बोकारो इस्पात संयंत्र में, सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट्स (एसएपी) डेटा में स्टॉक के रूप में दिखने वाली मात्रा भौतिक रूप से उपलब्ध नहीं हो सकती। भिलाई इस्पात संयंत्र में प्रयुक्त/अस्वीकृत/टूटी हुई ईंटों को नियमित रूप से बिक्री के लिए प्रस्तुत किया जाता था। मंत्रालय ने उत्तर दिया (नवंबर 2021) कि बोकारो इस्पात संयंत्र में 52,750 टन की स्क्रेप ईंटों का स्टॉक था।

प्रबंधन/मंत्रालय का उत्तर अपने आप में ही स्क्रेप ईंटों के स्टॉक के प्रबंधन में कमियों को उजागर करता है। चूंकि स्क्रेप का अपना आर्थिक मूल्य है, इसलिए लापता मर्दों के कारण हानि की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। बोकारो इस्पात संयंत्र और भिलाई इस्पात संयंत्र के मामले में, प्रबंधन को इस तरह के स्क्रेप का उचित लेखांकन सुनिश्चित करना चाहिए और राजस्व को बढ़ाने के लिए प्राथमिकता के आधार पर इनका निपटान करना चाहिए।

1.4 निष्कर्ष

सेल ने इस्पात बनाने की प्रक्रिया में रिफ़ैक्टरीज की महत्वपूर्ण भूमिका के बावजूद, रिफ़ैक्टरीज के लिए अपनी उत्पादन क्षमता के उन्नयन और आधुनिकीकरण के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए। कंपनी दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, एलॉए इस्पात संयंत्र और इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी इस्पात संयंत्र में रिफ़ैक्टरी की वार्षिक आवश्यकता का निर्धारण करने के लिए परिकल्पित रिफ़ैक्टरी टास्क फोर्स का गठन करने में भी विफल रही। इसकी आवश्यकताओं का निर्धारण करने में असमर्थता के कारण कुल ₹257.15 करोड़ (31 मार्च 2020) की अतिरिक्त इन्वेंट्री होल्डिंग और रिफ़ैक्टरीज की इन्वेंट्री 15 से 20 वर्षों के लिए

अवरुद्ध हो गई। सेल आंतरिक उपलब्ध अप्रयुक्त क्षमता का इष्टतम उपयोग करने में भी विफल रहा और उच्च लागत पर बाहरी स्रोतों से स्थापन्न और अधिप्राप्ति में देरी के कारण अतिरिक्त व्यय किया गया। कंपनी ने टोटल लैडल प्रबंधन प्रणाली के कार्यान्वयन में देरी और नई पीढ़ी के स्लाइड गेट प्रणाली के आंशिक कार्यान्वयन के कारण परिहार्य व्यय भी किया। इस प्रकार, सेल में रिफ्रैक्टरी प्रबंधन प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है ताकि आंतरिक सुविधाओं का इष्टतम उपयोग किया जा सके और रिफ्रैक्टरीज की अधिप्राप्ति के लिए लागत कम की जा सके।

अध्याय II: वित्तीय प्रबंधन

2.1 प्रस्तावना

स्टील अथॉरिटी आफ इंडिया लिमिटेड(कंपनी या सेल), भारत की सबसे बड़ी इस्पात बनाने वाली कंपनी है। यह भिलाई, बोकारो, राउरकेला, दुर्गापुर और बर्नपुर में स्थित पांच एकीकृत इस्पात संयंत्रों, दुर्गापुर, सलेम और भद्रावती में तीन विशेष इस्पात संयंत्रों और चंद्रपुर में एक फेरो एलॉय संयंत्र में लोहा और इस्पात का उत्पादन करता है। वित्तीय प्रबंधन को कंपनी के कॉर्पोरेट कार्यालय द्वारा किया जाता है जबकि उत्पादों का विपणन मुख्य रूप से कंपनी के केंद्रीय विपणन संगठन द्वारा किया जाता है जो घरेलू बिक्री और इस्पात उत्पादों के निर्यात का समन्वय और पर्यवेक्षण भी करता है। भारत सरकार (जीओआई) के पास सेल¹ के 75 प्रतिशत इक्विटी शेयर हैं।

2.2 लेखापरीक्षा के उद्देश्य और कार्यक्षेत्र

वित्तीय प्रबंधन में वित्तीय गतिविधियों की योजना, आवंटन और नियंत्रण शामिल है। इसमें (क) वित्तीय निर्णय (ख) निवेश निर्णय, और (ग) लाभांश निर्णय शामिल हैं। 'सेल में वित्तीय प्रबंधन' की लेखापरीक्षा इस उद्देश्य के साथ की गई थी कि क्या:

- i) निधियों की आवश्यकता का कुशलतापूर्वक निर्धारण किया गया था और सुदृढ़ पूंजी संरचना को बनाए रखा गया था;
- ii) निधियां उपलब्ध थीं और उनका इष्टतम अधिकतम उपयोग किया गया था;
- iii) प्रतिदाय सुनिश्चित करने के लिए विवेकपूर्ण तरीके से निवेश किया गया था और निर्धारित नीति के अनुसार लाभांश घोषित/भुगतान किया गया था;
- iv) प्राप्य मदों का प्रबंधन प्रभावी था।

वर्ष 2015-16 से 2019-20 के लिए सभी इस्पात संयंत्रों, केंद्रीय विपणन संगठन और सेल के कॉर्पोरेट कार्यालय के रिकॉर्ड की जांच की गई।

¹ 13 जनवरी 2021 से भारत सरकार की हिस्सेदारी को सेल की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी के 65 प्रतिशत तक कम कर दिया गया था।

2.3 वित्तीय निष्पादन

पिछले पांच वर्षों के दौरान सेल का वित्तीय निष्पादन नीचे दर्शाया गया है:

तालिका:2.1

पिछले पांच वर्षों के दौरान सेल का वित्तीय निष्पादन

(राशि: ₹ करोड़ में)

वर्ष	गर्म धातु का उत्पादन (मिलियन टन में)	कुल आय	कुल व्यय	कर से पहले का लाभ	निवल धन ²	आकस्मिक देयता
2015-16	15.721	39,667	46,850	(-)7,198	39,196	32,583
2016-17	15.726	50,303	54,937	(-)4,851	36,009	36,905
2017-18	15.982	59,447	60,232	(-)759	35,714	26,867
2018-19	17.513	67,500	63,773	3,338	38,152	28,278
2019-20	17.438	62,646	58,703	3,171	39,777	35,297

सेल को 2015-16 से 2017-18 के दौरान हानि हुई और उसके बाद 2018-19 और 2019-20 में लाभ अर्जित किया। 2015-16 से 2019-20 तक गर्म धातु का उत्पादन 11 प्रतिशत बढ़ा, जबकि इसी अवधि के दौरान कुल आय में 58 प्रतिशत की वृद्धि हुई। सेल के निष्पादन में 2018-19 के दौरान मुख्य रूप से बिक्री योग्य इस्पात के उच्च उत्पादन, बिक्री प्राप्ति में वृद्धि, कम स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्रतिपूर्ति और कम कोक दर आदि के कारण सुधार हुआ। 2019-20 के लिए लाभ मुख्य रूप से सब-ग्रेड लौह अयस्क फाइन्स, एम्बेडेड आयरन और स्टील स्क्रैप के मूल्यांकन और लौह अयस्क फाइन युक्त स्लाइम का मूल्यांकन के कारण था और कोई संगत नकदी उत्पन्न नहीं की थी। इसके अलावा, 31 मार्च 2020 तक, आकस्मिक देयता (संभावित व्यय) ₹35,297 करोड़ थी, जो कंपनी के निवल धन (₹39,777 करोड़) का 88 प्रतिशत थी और आय (₹62,646 करोड़) के आधे से अधिक थी। कुल आकस्मिक देयता में से, कंपनी के प्रति अपीलीय या न्यायिक निर्णयों के लिए लंबित दावों की राशि ₹29,844 करोड़ थी। लेखापरीक्षा ने पाया कि न्यायिक निर्णय कंपनी के विरुद्ध जा सकते हैं और इसलिए, भविष्य में भौतिक नकदी बहिर्वाह का जोखिम था।

²निवल धन = कुल परिसंपत्ति - कुल देयताएं

2.4 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

2.4.1 निधि और पूंजीगत संरचनाकी आवश्यकता का निर्धारण

निधि प्रबंधन, कंपनी के कॉर्पोरेट कार्यालय द्वारा किया जाता है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष की शुरुआत में, वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक कारोबार योजना के आधार पर संयंत्रों/इकाइयों से महीने-वार निधि की आवश्यकता प्राप्त की जाती है। दैनिक आवश्यकता प्राप्त करने के लिए महीने-वार निधि आवश्यकता को विघटित किया जाता है। सेल को अपनी बिक्री से प्राप्त राशि या उधार से निधि प्राप्त होती है।

2.4.1.1 बजट अनुमानों और वास्तविकताओं में विचलन

परिचालन बजट³ के लिए सेल के कॉर्पोरेट दिशानिर्देशों पर जोर दिया गया है कि बजट यथार्थवादी और प्राप्य होना चाहिए। लेखापरीक्षा ने पाया कि वर्ष 2015-16 से 2019-20 के लिए बजट प्रावधान और वास्तविक उपयोग में महत्वपूर्ण विचलन थे जैसा कि नीचे विवरण दर्शाया गया है:

तालिका 2.2: बजटीय और वास्तविक आय और व्यय में विचलन

(राशि: ₹ करोड़ में)

विवरण	आय	व्यय				
	निवलबिक्री -घरेलू	कच्चा माल (कोयला/कोक के अलावा)	स्टोर और स्पेयर	मरम्मत/ रखरखाव	रेलवेमा लभाड़ा	ब्याज
बजट 2019-20	74781	10010	4253	1888	3500	3162
वास्तविक 2019-20	57282	6133	3436	1563	2211	3487
विचलन %	23	39	19	17	37	-10
बजट 2018-19	70074	10236	3813	2032	3074	2886
वास्तविक 2018-19	63292	6218	2977	1474	2611	3155
विचलन %	10	39	22	27	15	-9
बजट 2017-18	60844	7627	2877	1379	1653	2763
वास्तविक 2017-18	55971	5202	2406	1244	2242	2823
विचलन %	8	32	16	10	-36	-2
बजट 2016-17	58974	6746	3599	1428	1808	2290

³ प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए सेल बोर्ड द्वारा बजट अनुमान को 'परिचालन बजट अनुमान (ओबीई)' के रूप में अनुमोदित किया जाता है। परिचालन बजट में बजट वार्षिक लाभ और हानि लेखा, आय और व्यय, लाभप्रदता अनुपात, बजटीय मासिक लक्ष्य शामिल हैं।

विवरण	आय	व्यय				
	निवलबिक्री -घरेलू	कचामाल (कोयला/कोक के अलावा)	स्टोर और स्पेयर	मरम्मत/ रखरखाव	रेलवेमा लभाड़ा	ब्याज
वास्तविक 2016-17	47376	4857	2303	1139	1162	2528
विचलन %	20	28	36	20	36	-10
बजट 2015-16	64217	7925	3574	1448	1375	1954
वास्तविक 015-16	42727	4992	2321	1068	1131	2300
विचलन %	33	37	35	26	18	-18

भिलाई में ब्लास्ट फर्नेस के असंगत परिचालन और राउरकेला, दुर्गापुर और बर्नपुर में नई सुविधाओं से उत्पादन के स्थिरीकरण में समस्या के कारण गर्म धातु, कच्चे इस्पात और बिक्री योग्य इस्पात का उत्पादन बजटीय उत्पादन से लगातार कम (12 से 21 प्रतिशत) था। बिक्री (8 से 33 प्रतिशत कम), कच्चा माल (28 से 39 प्रतिशत कम), स्टोर और स्पेयर (16 से 36 प्रतिशत कम), मरम्मत और रखरखाव (10 से 27 प्रतिशत कम) रेलवे भाड़ा (36 प्रतिशत अधिक से 37 प्रतिशत कम), ब्याज और वित्त प्रभार (2 से 18 प्रतिशत अधिक) के लिए बजट और वास्तविकता में व्यापक भिन्नताएं भी पाई गईं।

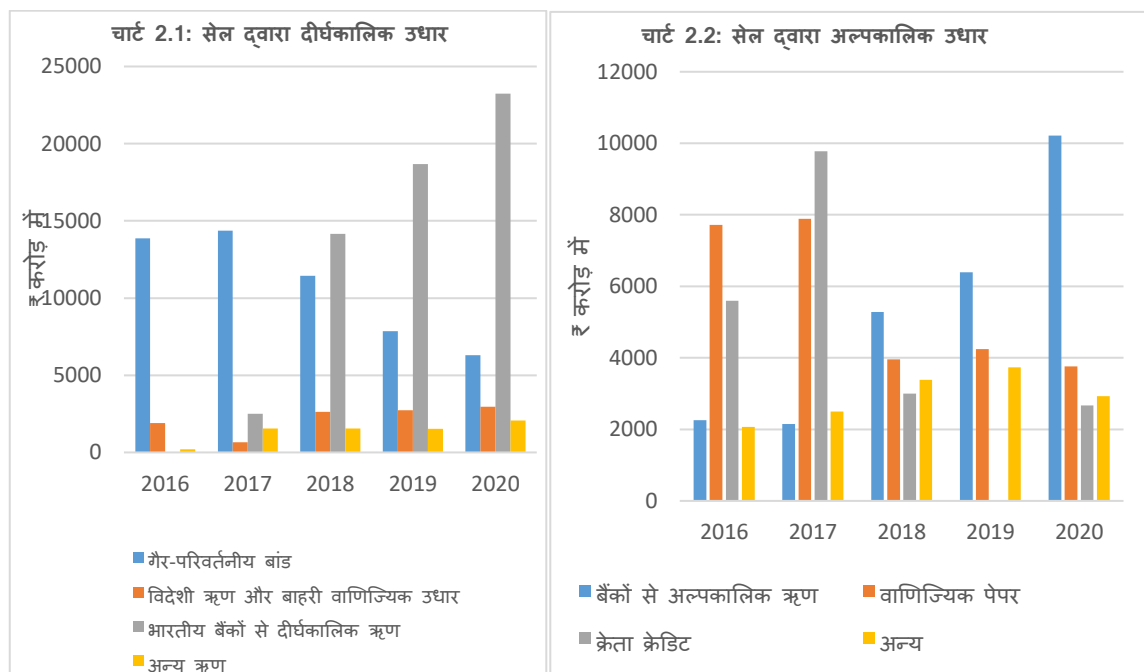
प्रबंधन ने उत्तर दिया (मई 2021) कि शाप्स में अप्रत्याशित खराबी, नई सुविधाओं से उत्पादन में वृद्धि के दौरान आने वाली समस्याओं और नई सुविधाओं को शुरू करने में देरी के परिणामस्वरूप निर्धारित लक्ष्यों के प्रति कमी हुई।

प्रबंधन का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि बजट की तैयारी के दौरान उत्पादन में तेजी और नई परियोजनाओं को शुरू करने जैसे कारकों पर विचार किया जाना चाहिए था। सेल की लेखापरीक्षा समिति ने भी पाया (2019) कि लक्ष्य अधिक यथार्थवादी रूप से निर्धारित किया जा सकता था।

सिफारिश संख्या 1: प्रबंधन, बजट अनुमानों को प्रभावित करने वाले सभी कारकों पर विचार कर सकता है ताकि तैयार किया गया बजट यथार्थवादी और प्राप्य हो।

2.4.1.2 निधि का उधार लेना

सेल, पूंजीगत व्यय, परिचालन व्यय और पुनर्भुगतान दायित्वों के लिए दीर्घकालिक ऋण (अवधि ऋण, बॉन्ड्स, बाहरी वाणिज्यिक उधार⁴) और अल्पकालिक ऋण (बैंकों से ऋण, वाणिज्यिक पत्र⁵, खरीदारों के क्रेडिट⁶) उधार लेता है। 2015-16 से 2019-20 के दौरान, सेल द्वारा उधार का विवरण नीचे चार्ट और तालिका में दिया गया है:



तालिका: 2.3

2015-16 से 2019-20 के दौरान सेल द्वारा उधार का विवरण

(राशि: ₹ करोड़ में)

31 मार्च तक	दीर्घकालिक उधार					अल्पकालिक उधार					कुल उधार (क+ख)	दीर्घकालिक और अल्पकालिक ऋणों का अनुपात
	गैर-परिवर्तनीय बांड	विदेशी ऋण और बाहरी वाणिज्यिक उधार	भारतीय बैंकों से दीर्घावधि ऋण	अन्य ऋण	कुल (क)	बैंकों से अल्पकालिक ऋण	वाणिज्यिक पेपर	क्रेताओं के क्रेडिट	अन्य	कुल (ख)		
2016	13878	1899	0	204	17496	2256	7721	5598	2070	17645	35,141	50:50
2017	14364	664	2500	1559	19087	2152	7884	9777	2496	22309	41,396	46:54

⁴बाहरी वाणिज्यिक उधार, विदेशी स्रोतों से विदेशी मुद्रा में धन उधार लेने के लिए उपयोग किए जाने वाले वित्तीय साधन हैं।

⁵वाणिज्यिक पत्र एक असुरक्षित मुद्रा बाजार साधन है जो 7 से 365 दिनों के कार्यकाल के साथ वचन पत्र के रूप में जारी किया जाता है।

⁶बायर्स क्रेडिट, एक अल्पकालिक ऋण सुविधा है जो एक विदेशी ऋणदाता द्वारा माल की खरीद के लिए आयातकों को दी जाती है।

2018	11443	2621	14156	1557	29777	5284	3962	2998	3388	15632	45,409	66:34
2019	7860	2727	18681	1535	30803	6390	4241	0	3736	14367	45,170	68:32
2020	6304	2956	23236	2064	34560	10212	3757	2672	2926	19567	54,127	64:36

*(इस्पात विकास निधि से ऋण: ₹204 करोड़)

लेखापरीक्षा ने पाया कि सेल के पास 2011-12 में ₹16,320 करोड़ की उधारी थी जो 31 मार्च 2016 (₹35,141 करोड़) तक दोगुनी हो गई और 31 मार्च 2020 तक बढ़कर ₹54,127 करोड़ हो गई। उधार में वृद्धि मुख्य रूप से कंपनी द्वारा लागू आधुनिकीकरण और विस्तार योजना के वित्तपोषण के लिए निधि में वृद्धि के कारण थी। लेखापरीक्षा ने पाया कि:

(i) सेल बोर्ड चाहता था (मार्च 2017) कि दीर्घकालिन और अल्पकालिन उधार 70:30 के अनुपात में होने चाहिए। कंपनी की कठिन वित्तीय स्थिति को देखते हुए, इसने आगे दीर्घकालिक से अल्पकालिक उधार का अनुपात 80:20 रखने का निर्णय लिया (दिसम्बर 2017)। बोर्ड ने इस बात पर भी बल दिया कि वर्तमान इस्पात उद्योग परिदृश्य और सेल की अनिश्चित वित्तीय स्थिति को देखते हुए, अल्पकालिक ऋणों को दीर्घकालिक ऋणों द्वारा प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता है। हालाँकि, मार्च 2016 तक, सेल में दीर्घकालिक और अल्पकालिक ऋणों का अनुपात लगभग 50:50 था और 31 मार्च 2020 तक यह 64:36 था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि सेल ने 2015-16 से 2019-20 के दौरान ₹39,776 करोड़ का दीर्घकालिक ऋण लिया, जिसमें से केवल ₹18,220 करोड़ (46 प्रतिशत) का पूंजीगत व्यय पर व्यय किया गया था और शेष राशि कार्यशील पूंजीगत आवश्यकताओं पर व्यय की गई थी। आगे यह भी पाया गया कि, सामान्यतः दीर्घकालिक ऋण पूंजीगत व्यय के लिए उधार लिए जाते हैं जबकि अल्पकालिक ऋण कार्यशील पूंजीगत आवश्यकताओं के लिए होते हैं। हालाँकि, कंपनी ने न तो कोई नीति बनाई है और न ही ऐसी गतिविधियाँ निर्धारित की हैं जिनके लिए दीर्घकालिक और अल्पकालिक ऋणों का उपयोग किया जाएगा। इस प्रकार, कंपनी अल्पकालिक ऋणों और इसके आंतरिक राजस्व सृजन से कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ थी और इसके लिए दीर्घकालिक उधार निधि पर निर्भर थी।

(ii) 31 मार्च 2020 को कुल उधारी में से, 4-7 वर्षों की अवधि के लिए जुटाए गए गैर-परिवर्तनीय बांड 12 प्रतिशत और सावधि ऋण 51 प्रतिशत थे। कंपनी को अगले 10 वर्षों (2020-30) में इन दोनों के कारण चुनौतियों के बंचिग का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें बांडों और सावधि ऋणों के कारण बकाया कुल राशि का 63 प्रतिशत मोचन/चुकौती के लिए देय हो जाता है। यह अल्पकालिक ऋण (कुल उधार का 36 प्रतिशत) और ब्याज भुगतान की चुकौती के अतिरिक्त है।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (मई 2021) कि कंपनी की क्रेडिट रेटिंग के अधोमुखी संशोधन का आसन्न खतरा था। वित्तीय वर्ष 2017-18 और 2018-19 के दौरान चुकौती में किसी भी चूक की स्थिति से बचने के लिए दीर्घकालिक ऋणों द्वारा अल्पकालिक ऋणों का प्रतिस्थापन किया गया था, जब सेल में नकदी की कमी थी और यह नकदी के मामलों का सामना कर रहा था। इसने आगे बताया कि सेल के वित्तीय निष्पादन में सुधार के साथ, ऋण चुकाना चिंता का विषय नहीं होगा। यह भी कहा गया है कि एसबीआई से विशिष्ट ऋण केवल कैपेक्स के लिए निर्धारित किए गए थे और बाकी सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए थे, जिनका उपयोग कैपेक्स या अन्य जगहों के लिए किया जा सकता था।

प्रबंधन के उत्तर को इस तथ्य के संदर्भ में देखा जा सकता है कि यद्यपि कंपनी ने 2015-16 से 2019-20 तक अल्पकालिक ऋणों से दीर्घकालिक ऋणों के अनुपात में सुधार किया है, लेकिन 80:20 के अनुपात को प्राप्त करना अभी बाकी था जैसा कि बोर्ड चाहता है। इसके अलावा, अत्यधिक अल्पकालिक उधार, नकदी की स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं क्योंकि इसमें भारी प्रवर्निधारणीय जोखिम होता है और सेल को पिछले एक श्रण को चुकाने के लिए एक और अल्पकालिक ऋण लेना पड़ सकता है। इसके अलावा, सेल अल्पकालिक ऋणों के माध्यम से या परिचालन से, नकदी प्रवाह से अपनी कार्यशील पूंजी की आवश्यकता को पूरा करने में असमर्थ था और उसे दीर्घकालिक ऋणों पर निर्भर रहना पड़ा था।

2.4.1.3 वित्तीय क्रेडिट रेटिंग में गिरावट

क्रेडिट रेटिंग सामान्य शब्दों में या किसी विशेष ऋण या वित्तीय दायित्व के संबंध में एक उधारकर्ता की क्रेडिट योग्यता का मात्रात्मक निर्धारण है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां उधार लेने या उधार देने के वित्तीय इतिहास को ध्यान में रखती हैं और सत्व की क्रेडिट योग्यता पर

पहुंचती हैं। सेल की उधारी की रेटिंग आरबीआई द्वारा अनुमोदित रेटिंग एजेंसियों यानी केयर रेटिंग्स, इंडिया रेटिंग्स और ब्रिकवर्क रेटिंग्स द्वारा आंका जाता है। एजेंसियां रेटिंग प्रतीकों जैसे एएए, एए, ए+, ए-, ए1 आदि का उपयोग करती हैं। रेटिंग आउटलुक जैसे घनात्मक, ऋणात्मक और स्थिर भी रेटिंग एजेंसियों द्वारा प्रदान किया जाता है। रेटिंग आउटलुक क्रमशः क्रेडिट रेटिंग के अपेक्षित उन्नयन, अपन्नपन या स्थिरता को इंगित करता है। 2015-16 से 2019-20 के दौरान सेल के उपकरणों की क्रेडिट रेटिंग नीचे दी गई तालिका में दर्शाई गई है:

तालिका 2.4: 2016-17 से 2019-20 के दौरान सेल के उपकरणों की क्रेडिट रेटिंग

उपकरणों का नाम	प्रकार	केयर रेटिंग्स द्वारा सेल की क्रेडिट रेटिंग				
		2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
बांड	दीर्घकालिक	एए+	एए (ऋणात्मक)	एए- (ऋणात्मक)	एए- (स्थिर)	एए- (स्थिर)
वाणिज्यिक पेपर	अल्पकालिक	ए1+	ए1+	ए1+	ए1+	ए1+
निधि आधारित दीर्घकालिक ऋण	दीर्घकालिक	लागू नहीं	एए (ऋणात्मक)	एए- (ऋणात्मक)	एए- (स्थिर)	एए - (स्थिर)

मार्च 2016 में सेल के दीर्घकालिक उधारों (बॉन्डस और सावधि ऋण) की क्रेडिट रेटिंग एए+ थी, जो मार्च 2017 में ऋणात्मक आउटलुक के साथ एए तक कम हो गई और मार्च 2018 में एए- (ऋणात्मक) तक कम हो गई। क्रेडिट रेटिंग 2018-19 और 2019-20 में एए- (स्थिर) थी। लेखापरीक्षा ने आगे पाया किया कि 2020-21 में रेटिंग के लिए आउटलुक ऋणात्मक हो गया। 2015-16 से 2019-20 के दौरान अल्पकालिक ऋण के लिए क्रेडिट रेटिंग ए1+ (घनात्मक) थी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि पिछले पांच वर्षों के दौरान सेल की क्रेडिट रेटिंग में या तो गिरावट आई है या स्थिर बनी हुई है। यह इसके कमजोर परिचालन निष्पादन, उंचे कर्ज स्तर और ब्याज लागत में वृद्धि के कारण था। ऑपरेटिंग कैश फ्लो और चुकौती दायित्वों में गिरावट के परिणामस्वरूप क्रेडिट रेटिंग में और गिरावट आ सकती है, जो कि निधि और दीर्घकालिक ऋण के संबंध में रेटिंग आउटलुक के ऋणात्मक होने का भी संकेत है। रेटिंग में इस तरह की गिरावट से उधार लागत में वृद्धि होगी और भविष्य में निधि जुटाने में आगे कठिनाई होगी।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (मई 2021) कि भारत में सभी इस्पात कम्पनियों की रेटिंग को घरेलू भारतीय इस्पात उद्योग में गिरावट के कारण डाउनग्रेड किया गया था। सेल, प्रतिकूल इस्पात बाजार और दीर्घकाल में कम रेटिंग के बावजूद बड़ी मात्रा में निधि जुटा सकता है। सेल की औसत ब्याज दर घट रही है।

प्रबंधन का उत्तर इस तथ्य के संदर्भ में देखा जा सकता है कि 2016-17 से 2019-20 के दौरान दीर्घकालिक ऋणों के लिए इसी तरह की निजी क्षेत्र की स्टील कंपनी की क्रेडिट रेटिंग स्थिर थी। इसलिए प्रबंधन का यह तर्क कि सभी इस्पात कंपनियों की क्रेडिट रेटिंग कम कर दी गई थी, सही नहीं है। इसके अलावा, प्रबंधन ने पैरा 2.4.1.2(ii) के अपने उत्तर में स्वीकार किया है कि कंपनी की क्रेडिट रेटिंग में अपन्यन संशोधन एक आसन्न खतरा था।

2.4.2 अनुपात विश्लेषण

वित्तीय अनुपात का उपयोग इकाई के वित्तीय निष्पादन का निर्धारण करने के लिए किया जाता है। लेखापरीक्षा ने ऋण इक्विटी अनुपात⁷, ब्याज कवरेज अनुपात⁸, शुद्ध ऋणों⁹ से ब्याज, करों, मूल्यहास और सेल के परिशोधन से पहले की आय का अनुपात¹⁰ का विश्लेषण किया। विवरण नीचे दिया गया है:

तालिका 2.5: सेल के वित्तीय अनुपात

वर्ष	ऋण इक्विटी अनुपात	ब्याज कवरेज अनुपात	शुद्ध ऋण का ब्याज, करों, मूल्यहास और परिशोधन से पहले की आय से अनुपात
इष्टतम स्तर	1 बार या उससे कम	2 बार या उससे अधिक	2.5 से 3 बार या उससे कम
2015-16	0.9:1	-1.9	-15.94
2016-17	1.1:1	-0.7	61.60
2017-18	1.3:1	0.6	8.76
2018-19	1.2:1	1.8	4.39
2019-20	1.4:1	1.8	4.83

⁷ ऋण इक्विटी अनुपात: ऋण/इक्विटी; जहां ऋण दीर्घकालिक और अल्पकालिक ऋण को संदर्भित करता है और इक्विटी शेयरधारक की इक्विटी को संदर्भित करता है।

⁸ ब्याज कवरेज अनुपात: ब्याज और कर/ब्याज व्यय से पहले की आय।

⁹ शुद्ध ऋण: दीर्घकालिक ऋण + अल्पकालिक ऋण - नकद और नकद समकक्षा।

¹⁰ शुद्ध ऋण से ब्याज, करों, मूल्यहास और परिशोधन से पहले की आय का अनुपात: शुद्ध ऋण/ब्याज, करों, मूल्यहास और परिशोधन से पहले आय।

ऋण इक्विटी अनुपात: यह कंपनी के वित्तीय प्रभावन क्षमता¹¹ का मूल्यांकन करता है। सेल का ऋण इक्विटी अनुपात 2015-16 से 2019-20 की अवधि के दौरान बढ़ा और 0.9:1 और 1.4:1 के बीच रहा। लेखापरीक्षा ने पाया कि सेल में ऋण इक्विटी अनुपात 1:1 के इष्टतम स्तर की तुलना में प्रतिकूल था। प्रतिकूल ऋण इक्विटी अनुपात इंगित करता है कि कंपनी की परिसंपत्तियों की तुलना में अधिक देनदारियां हैं और यह वित्तीय अस्थिरता का भी संकेत है।

ब्याज कवरेज अनुपात: यह अनुपात उधार पर ब्याज का भुगतान करने के लिए एक सत्त्व के पास उपलब्ध कवर की सीमा को इंगित करता है। अनुपात जितना अधिक होगा, कंपनी की ब्याज भुगतान को कवर करने की क्षमता उतनी ही अधिक होगी। सेल का ब्याज कवरेज अनुपात (-) 1.9 से 1.8 था। 2017-18 से 2019-20 के दौरान, सेल का ब्याज कवरेज अनुपात इष्टतम स्तर से कम था जबकि 2015-16 और 2016-17 के दौरान यह ऋणात्मक था। प्रतिकूल ब्याज कवरेज अनुपात ब्याज के भुगतान में कठिनाई को दर्शाता है।

शुद्ध ऋण का ब्याज, करों, मूल्यहास और परिशोधन से पहले की आय से अनुपात: यह अनुपात वित्तीय लाभों और कंपनी के अपने ऋण का भुगतान करने की क्षमता को मापता है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के अनुसार यह अनुपात 2.5 से 3 गुना होना चाहिए। लेखापरीक्षा ने पाया कि शुद्ध ऋण का ब्याज, करों, मूल्यहास, और परिशोधन से पहले की आय से अनुपात 2016-17 से 2019-20 के दौरान 4.39 और 61.60 गुना के बीच था। 2015-16 के दौरान, जैसा कि सेल को निवल घाटा हुआ था, तो अनुपात (-)15.94 गुना था, जबकि 2016-17 में अनुपात में 61.60 गुना का भारी उछाल आया क्योंकि ब्याज, करों, मूल्यहास और परिशोधन से पहले की आय सकारात्मक हो गई और वहाँ निवल ऋण में वृद्धि हुई थी।

इस प्रकार, जब वांछित इष्टतम स्तर से इसकी तुलना की गई तो सेल के लिए अनुपात प्रतिकूल था। शुद्ध ऋण का ब्याज, करों, मूल्यहास और परिशोधन से पहले की आय से अनुपात 3 से अधिक होना यह दर्शाता है कि कंपनी का परिचालन अपने ऋण का भुगतान

¹¹ प्रभावन क्षमता विशेष रूप से उधार लिए गए पैसे का उपयोग करने की एक निवेश रणनीति है, एक निवेश की संभावित वापसी को बढ़ाने के लिए विभिन्न वित्तीय साधनों या उधार ली गई पूंजी का उपयोग करना। प्रभावन क्षमता भी ऋण की राशि को संदर्भित कर सकती है जो एक फर्म परिसंपत्तियों के वित्तपोषण के लिए उपयोग करती है।

करने के लिए इष्टतम स्तर पर नहीं है जिसके परिणामस्वरूप अधिक उधारी हो सकती हैं।

लेखापरीक्षा ने पाया कि ऋण इक्विटी अनुपात में वृद्धि, शुद्ध ऋण का ब्याज, करों, मूल्यहास, और परिशोधन से पहले की आय से अनुपात और ब्याज कवरेज अनुपात में कमी कंपनी के खराब क्रेडिट प्रोफाइल को दर्शाती है।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (मई 2021) कि 2015-16 से 2019-20 के दौरान उत्पादन की मात्रा वांछित स्तर को प्राप्त नहीं की जा सकी। स्टील बाजार की सुस्त स्थिति, कम निवल बिक्री प्राप्ति, देनदारों में वृद्धि और इन्वेंट्री स्तर ने उधारी में वृद्धि में योगदान दिया है। परिणामस्वरूप, प्रमुख वित्तीय अनुपात मानदंडों से बहुत कम थे। उम्मीद है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में, सभी मुख्य वित्तीय अनुपात काफी अच्छे होंगे।

तथापि तथ्य यह है कि लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान वांछित इष्टतम स्तर की तुलना में सेल के लिए अनुपात प्रतिकूल था।

2.4.3 केंद्रीकृत नकद क्रेडिटलेखे का परिचालन

सेल का कॉर्पोरेट कार्यालय भारतीय स्टेट बैंक में इस्पात संयंत्रों और इकाइयों और उनके ग्राहकों के साथ दिन-प्रतिदिन के लेनदेन को संचालित करने के लिए एक केंद्रीकृत नकद क्रेडिट लेखा रखता है। कॉर्पोरेट कार्यालय केंद्रीय विपणन संगठन से बिक्री आय से निधि प्राप्त करता है और बैंकों/वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त करता है। इसके बाद प्राप्त निधियों को संबंधित संयंत्रों/इकाइयों को उनकी आवश्यकता के अनुसार वितरित किया जाता है और ऋणों की चुकौती के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है।

संयंत्र/इकाइयां अव्ययित शेष राशि को एसबीआई केंद्रीकृत नकद क्रेडिट लेखा में अंतरण कर देती हैं और कारोबारी दिन के अंत में, एसबीआई केंद्रीयकृत नकद क्रेडिट लेखा, डेबिट/क्रेडिट शेष दिखाता है। शून्य शेष, निधि के पूर्ण उपयोग को दर्शाता है जबकि डेबिट शेष दर्शाता है कि निधियों का उपयोग उपलब्धता से अधिक किया गया था। क्रेडिट शेष, अधिशेष निधि को दर्शाता है जिसका उपयोग कारोबारी दिन के दौरान नहीं किया गया था। लेखापरीक्षा ने अप्रैल 2016 और मार्च 2020 के बीच की अवधि के लिए 1,016 शेष स्थितियों का विश्लेषण किया और पाया कि 139 मामलों (13.68 प्रतिशत मामलों) में ₹500 करोड़ से अधिक का डेबिट शेष था, जिसमें से 48 मामलों (4.72 प्रतिशत मामलों)

में, यह ₹1,000 करोड़ से अधिक था। 43 मामलों (4.23 प्रतिशत मामलों) में, डेबिट शेष ₹ 2,000 करोड़ से अधिक था। 104 मामलों में क्रेडिट शेष को पाया गया, जिसमें से 14 मामलों में (कुल क्रेडिट शेष में से 13.46 प्रतिशत मामले) यह ₹100 करोड़ से अधिक था। लेखापरीक्षा ने पाया कि सेल ने 2016-17 से 2019-20 के दौरान इस तरह के डेबिट शेष पर ब्याज की उच्च दर के भुगतान के कारण ₹14.55 करोड़¹² (लगभग) का परिहार्य व्यय किया।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि कंपनी कई मामलों में निधि की आवश्यकता का सही निर्धारण करने में सक्षम नहीं थी और अधिक ब्याज का भुगतान करने से बचने और एसबीआई केंद्रीकृत नकद क्रेडिट लेखा में पड़े क्रेडिट शेष को कम करने के लिए डेबिट शेष को कम से कम करने में सक्षम नहीं थी क्योंकि कंपनी को एक दिन के लिए क्रेडिट शेष पर कोई ब्याज नहीं मिला।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (मई 2021) कि सेल सावधानीपूर्वक अपने व्यय/नकदी निकासी प्रवाह की योजना बना रहा था। कभी-कभी एसबीआई केंद्रीकृत नकद क्रेडिट लेखा में डेबिट/क्रेडिट शेष उपलब्ध थे जब वांछित अंतरण प्राप्त नहीं हुए थे या बैंकिंग घंटों के बाद अच्छी राशि की प्राप्ति के मामले में था।

प्रबंधन का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा ने पाया था कि 2014-15 और 2015-16 के दौरान क्रेडिट शेष के केवल दो उदाहरण नोट किए गए थे जो दर्शाते हैं कि यदि इस दिशा में सचेत प्रयास किए गए थे, तो प्रबंधन 2016-17 से 2019-20 के दौरान डेबिट/क्रेडिट शेष की महत्वपूर्ण राशि से जुड़े कई उदाहरणों को नियंत्रित कर सकता था। यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण था क्योंकि प्रबंधन इस आधार पर परिहार्य व्यय कर रहा था क्योंकि डेबिट शेष में ब्याज का भुगतान शामिल था जबकि कंपनी ने एक दिन के लिए क्रेडिट शेष पर ब्याज अर्जित नहीं किया था।

सिफारिश संख्या 2: एसबीआई केंद्रीकृत नकदी क्रेडिट लेखा में डेबिट शेष पर ब्याज का भुगतान करने से बचने के लिए, कंपनी अपनी निधि की आवश्यकता का सटीक अनुमान सुनिश्चित कर सकती है और ऐसे डेबिट शेष पर परिहार्य ब्याज के भुगतान के प्रभाव का भी निर्धारण कर सकती है।

¹² 2016-17 से 2019-20 के दौरान सेल द्वारा जुटाए गए वाणिज्यिक पेपर की नकद ऋण दर और ब्याज की औसत दर के बीच अंतर के आधार पर गणना की गई राशि।

2.4.4 ऋणों की प्रतिरक्षा

प्रतिरक्षा एक जोखिम कम करने की तकनीक है जिसके तहत एक सत्व किसी परिसंपत्ति या देयता के उचित मूल्य या नकदी प्रवाह में भविष्य में होने वाले परिवर्तनों को समायोजन करने के लिए व्युत्पन्न या समान साधन का उपयोग करता है। ऋणों की प्रतिरक्षा में दो तत्व शामिल हैं- ऋण की मूल राशि की प्रतिरक्षा और उस पर ब्याज की प्रतिरक्षा यानी लिबोर। विदेशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव के जोखिम को कम करने के लिए मूलधन की प्रतिरक्षा आवश्यक है। ब्याज दर (लिबोर) में बदलाव के जोखिम को कम करने के लिए ब्याज की प्रतिरक्षा आवश्यक है।

2.4.4.1 बाहरी वाणिज्यिक उधारों की प्रतिरक्षा न करने के कारण ₹194 करोड़ का परिहार्य व्यय

सेल ने मार्च 2011 से दिसंबर 2012 के दौरान पूंजीगत योजना पर व्यय को पूरा करने के लिए विदेशी बैंकों से दीर्घकालिक ऋण उधार लिया। उधारी का विवरण नीचे तालिका में दिया गया है:

तालिका 2.6: सेल के बाहरी वाणिज्यिक उधारी का विवरण

क्रम सं.	बैंक का नाम	विदेशी मुद्रा की प्रतिरक्षा	ब्याज की प्रतिरक्षा (लिबोरके आधार पर)	ड्राउन की तिथि	मूल राशि (मिलियन डॉलर में)	ड्राउन की तिथि के अनुसार विनिमय की दर	राशि (₹करोड़ में)
1	बैंक ऑफ टोक्यो-मिजुबिशी यूएफजे लिमिटेड	नहीं	हाँ	11.03.2011	200	45.07	901.38
2	बैंक ऑफ टोक्यो-मिजुबिशी यूएफजे लिमिटेड	नहीं	नहीं	11.08.2011	200	45.34	906.71
3	सुमितोमो मिजुई बैंकिंग निगम	हाँ	हाँ	16.11.2011	300	50.92	1527.60
4	मिजुहो कॉर्पोरेशन बैंक	हाँ	हाँ	21.12.2012	150	55.13	827.85

यह देखा गया था कि बैंक ऑफ टोक्यो-मिजुबिशी यूएफजे लिमिटेड से दो बाहरी वाणिज्यिक उधारी में, प्रत्येक का मूल्य 200 मिलियन अमरीकी डालर था जिसे 2011 के

दौरान लिया गया था और 2015 से 2017 तक तीन चरणों में चुकाने योग्य था। मार्च 2011 और अगस्त 2011 में ली गई बाहरी वाणिज्यिक उधारी को क्रमशः मार्च 2017 और अगस्त 2017 में चुकाया गया था। इन दो उधारियों की विदेशी विनिमय में उतार-चढ़ाव के लिए प्रतिरक्षा नहीं की गई थी। इसके अलावा, सुमितोमो मुत्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन (नवंबर 2011 में 300 मिलियन अमरीकी डालर) और मिजुहो कॉर्पोरेशन बैंक (दिसंबर 2012 में 150 मिलियन अमरीकी डालर) से दो उधारियों की विदेशी विनिमय में उतार-चढ़ाव और लिबोर के मामले में पूरी तरह से प्रतिरक्षा की गई थी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि अमेरिकी डॉलर से भारतीय रुपये में समानता जुलाई 2011 तक स्थिर थी लेकिन विनिमय समानता अगस्त 2011 में रुपये के मुकाबले काफी बढ़ गई थी। डॉलर विनिमय दर सितंबर 2011 से बढ़ती प्रवृत्ति पर थी, इसलिए उपरोक्त दोनों उधारियों (क्रम संख्या 1 और 2 पर) की नवंबर 2011 के दौरान विदेशी विनिमय में उतार-चढ़ाव के संदर्भ में जोखिम को कम करने के लिए नवंबर 2011 में ली गई अन्य बाहरी वाणिज्यिक उधारियों के साथ प्रतिरक्षा की जानी चाहिए थी। विदेशी विनिमय की प्रतिरक्षा न करने के अलावा, कंपनी ने अगस्त 2011 में ली गई ₹906.71 करोड़ मूल्य की बाहरी उधारियों के लिए ब्याज (लिबोर) की प्रतिरक्षा भी नहीं की गई।

लेखापरीक्षा ने पाया कि मार्च 2011 और अगस्त 2011 में दो उधारी की विदेशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव के लिए प्रतिरक्षा नहीं की गई थी। जब विनिमय दर लगभग ₹45 प्रति डॉलर थी। नवंबर 2011 में सुमितोमो मुत्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन से लिए गए ऋण को बाजार जोखिम और ₹50.92 प्रति डॉलर की प्रचलित विनिमय दर के आधार पर पूरी तरह से प्रतिरक्षा (मूलधन और ब्याज) की गई थी। विदेशी विनिमय में उतार-चढ़ाव के संदर्भ में 400 मिलियन अमरीकी डालर (तालिका 2.6 की क्रम संख्या 1 और 2) के ऋणों की प्रतिरक्षा न करने के कारण ₹194 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (मई 2021) कि ऋणों की प्रतिरक्षा न करने का एक सचेत निर्णय लिया गया था क्योंकि प्रतिरक्षा लागत बहुत अधिक थी और भारतीय रुपये की समता में अमेरिकी डॉलर पहले ही बढ़ चुका था। कंपनी ने विदेशी मुद्रा बाजार में तत्कालीन प्रचलित अस्थिरता और ब्याज दर में मध्यस्थता के मद्देनजर नवंबर, 2011 में आहरित 300 मिलियन अमरीकी डालर की बाहरी वाणिज्यिक उधारी की प्रतिरक्षा की।

प्रबंधन का उत्तर ऋणों और ब्याज की प्रतिरक्षा के संबंध में कंपनी के निर्णय में एकरूपता की कमी को उजागर करता है। सेल, मार्च और अगस्त 2011 में ली गई दो बाहरी वाणिज्यिक उधारी की भी प्रतिरक्षा कर सकता था जैसा कि नवंबर 2011 में लिए गए बाहरी वाणिज्यिक उधारी के लिए कुछ महीनों के बाद किया गया था। प्रबंधन को यह पता था कि प्रतिरक्षा न करके, उन्हें पांच वर्ष से अधिक के लिए विदेशी विनिमय में उतार-चढ़ाव की अतिरिक्त लागत वहन करनी होगी। साथ ही, अगस्त 2011 में लिए गए ₹906.71 करोड़ मूल्य की बाह्य वाणिज्यिक उधारी के लिए ब्याज (लिबोर) की प्रतिरक्षा न करने पर प्रबंधन के उत्तर में कुछ नहीं कहा गया है, जबकि उन्होंने मार्च 2011 में ब्याज (लिबोर) की प्रतिरक्षा की थी।

2.4.4.2 क्रेताओं के क्रेडिट¹³ पर ब्याज (लिबोर) की प्रतिरक्षा न करना

कंपनी कोयले के आयात के लिए क्रेता क्रेडिट का लाभ उठाती है जो उधारी के अन्य स्रोतों की ब्याज दर की तुलना में सबसे सस्ती ब्याज दर वहन करती है। विनिमय दर के अलावा, सेल विदेशी विनिमय ऋण वहन ब्याज (लिबोर) के संबंध में ब्याज दर जोखिम के संपर्क में है। सेल की विदेशी मुद्रा जोखिम प्रबंधन नीति (फरवरी 2013) के अनुसार, कंपनी को यह सुनिश्चित करने के लिए कि विदेशी विनिमय दर में उतार-चढ़ाव से कोई जोखिम नहीं है, अल्पकालिक ऋणों के लिए विनिमय दर/मुद्रा जोखिम की प्रतिरक्षा करना आवश्यक था। विदेशी विनिमय जोखिम प्रबंधन समिति ने देखा कि चूंकि लिबोर के अल्पकालिक में अस्थिर रहने की संभावना है, इसलिए यह अल्पकालिक विदेशी मुद्रा ऋण के लिए ब्याज जोखिम की भी प्रतिरक्षा करने पर विचार कर सकता है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि सेल ने विदेशी विनिमय में उतार-चढ़ाव के संदर्भ में क्रेता ऋण की मूल राशि की प्रतिरक्षा की लेकिन मार्च 2017 से दिसंबर 2017 के दौरान कुछ मामलों को छोड़कर क्रेता क्रेडिट (लिबोर) पर ब्याज की प्रतिरक्षा नहीं की। 2015-20 के दौरान लाभ उठाए गए क्रेता के क्रेडिट का विवरण और लिबोर रेंज का विवरण नीचे दिया गया है:

¹³ क्रेता क्रेडिट एक अल्पकालिक ऋण सुविधा है जो एक विदेशी ऋणदाता द्वारा माल की खरीद के लिए आयातकों को दी जाती है।

तालिका 2.7: प्राप्त क्रेता क्रेडिट और लिबोर रेंज

वर्ष	कोयले का आयात (रैंकरोड़ में)	वर्ष के दौरान प्राप्य क्रेडिट की संख्या	प्राप्त क्रेडिट (रैंकरोड़ में)	लिबोर (न्यूनतम से अधिकतम)	रेंज से	लिबोर रेंज (वर्ष की शुरुआत और अंत में)	वर्ष के दौरान औसत लिबोर
2015-16	10789	153	6564	0.27 से 0.7125		0.27 से 0.6286	0.4017
2016-17	14250	173	10872	0.6261 से 1.15622		0.6266 से 1.15622	0.8649
2017-18	18000	39	2959	1.3035 से 1.64203		1.3035 से 1.57352	1.38283
2018-19*	-	0	0	0		0	0
2019-20	-	47	3646	0.7405 से 2.58113		2.58113 से 1.21563	1.90325

*सेल ने 2018-19 में क्रेता क्रेडिट का लाभ नहीं उठाया क्योंकि भारत में आयात के लिए क्रेता क्रेडिट के लिए वचन पत्र / आश्वासन पत्र जारी करने की प्रथा मार्च 2018 में आरबीआई द्वारा बंद कर दी गई थी। आरबीआई ने 13 मार्च 2019 से फिर से इस तरह की प्रथा की अनुमति दी थी।

यह देखा गया कि 2015-16 और 2019-20 के बीच लिबोर (10 गुना) में भारी वृद्धि हुई थी। सेल बोर्ड नेपूरी अवधि के लिए क्रेता क्रेडिट (केवल मूलधन) की प्रतिरक्षा जारी रखने का निर्णय लिया (8 दिसंबर 2015)। लेखापरीक्षा ने पाया कि प्रबंधन ने उपरोक्त अवधि के दौरान अत्यधिक अस्थिर बाजार में बढ़ती प्रवृत्ति के बावजूद क्रेताओं के ऋण पर ब्याज (लिबोर) को प्रतिरक्षा नहीं करने का निर्णय लिया। इसलिए, कंपनी लिबोर की भावी वृद्धि की भरपाई नहीं कर सकी।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (मई 2021) कि विदेशी विनिमय जोखिम प्रबंधन समिति के निर्णय के अनुसार क्रेता क्रेडिट का लाभ उठाने के समय मूलधन राशि की प्रतिरक्षा की गई थी जबकि ब्याज (लिबोर) को प्रतिरक्षा नहीं की गई थी क्योंकि यह काफी समय के लिए अस्थिर नहीं था और इसकी संभावना थी निकट भविष्य में स्थिर रहें।

प्रबंधन का उत्तर तर्कसंगत नहीं है। लिबोर में 2015-16 से 2019-20 के दौरान 0.27 प्रतिशत से बढ़कर 2.58 प्रतिशत लगातार वृद्धि हो गई। इस अवधि के दौरान ब्याज (लिबोर) के लिए औसत प्रतिरक्षा लागत लगभग 0.25 प्रतिशत थी और प्रति वर्ष लिबोर में औसत वृद्धि 0.50 प्रतिशत थी। चूंकि, 2015-20 के दौरान लिबोर में भारी वृद्धि हुई

थी, प्रबंधन को क्रेता क्रेडिट के लिए ब्याज (लिबोर) की प्रतिरक्षा करनी चाहिए थी। कंपनी का निर्णय भी फरवरी 2013 में विदेशी विनिमय जोखिम प्रबंधन समिति द्वारा व्यक्त विचारों के विपरीत था।

सिफारिश संख्या 3: कंपनी के वित्तीय हित को सुरक्षित करने के लिए कंपनी विदेशी विनिमय में उतार-चढ़ाव और ब्याज के लिए ऋण की प्रतिरक्षा के लिए प्रचलित प्रथाओं का पालन कर सकती है।

2.4.5 निधियों का निवेश

संयुक्त उद्यम कंपनियों, सहायक कंपनियों, एसोसिएट्स और उद्धृत और गैर-उद्धृत इक्विटी में सेल का कुल निवेश 31 मार्च 2020 (31 मार्च 2016 को ₹1,300 करोड़) को ₹1,611 करोड़ था। मार्च 2020 में सेल की 21 संयुक्त उद्यम कंपनियां और 4 सहायक कंपनियां थी। उपरोक्त में से आठ¹⁴ संयुक्त उद्यम, परिचालन में थे, तीन परियोजना/व्यवहार्यता चरण¹⁵ के अधीन थी और 10 निष्क्रिय या बंद¹⁶ होने के अधीन थी। केवल पांच संयुक्त उद्यम कंपनियां लाभ कमा रही थीं। लेखापरीक्षा ने पाया कि कंपनी ने संयुक्त उद्यमों/अन्य में निधियों के निवेश के लिए कोई नीति या दिशानिर्देश नहीं बनाए गए थे। लेखापरीक्षा ने सेल द्वारा संयुक्त उद्यमों में निष्फल निवेश के मामलों को पाया जिनकी चर्चा नीचे की गई है:

2.4.5.1 भिलाई जेपी सीमेंट लिमिटेड

i) सेल और जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड ने भिलाई जेपी सीमेंट लिमिटेड नामक एक संयुक्त उद्यम कंपनी का गठन किया (11 अप्रैल 2007)। सेल ने संयुक्त उद्यम कंपनी में ₹52.51 करोड़ का निवेश किया और 26 प्रतिशत शेयर अपने पास रखा और जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड के पास शेष 74 प्रतिशत हिस्सेदारी थी। भिलाई जेपी सीमेंट लिमिटेड और सेल के बीच दीर्घकालिक स्लैग बिक्री और जल आपूर्ति करार के

¹⁴ एनटीपीसी-सेल पावर कंपनी लिमिटेड, बोकारो पावर सप्लाई कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, एमजंक्शन सर्विसेज लिमिटेड, भिलाई जेपी सीमेंट लिमिटेड, इंटरनेशनल कोल वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड, सेल राइट्स बंगाल वैगन इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड, प्राइम गोल्ड-सेल जेवीसी लिमिटेड और सेल- बंसल सर्विस सेंटर लिमिटेड।

¹⁵ वीएसएल-सेल जेवीसी लिमिटेड, गेडकोल सेल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड और बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड।

¹⁶ सेल-एससीआई शिपिंग प्राइवेट लिमिटेड, सेल-एससीएल केरल लिमिटेड, सेल एमओआईएल फेरो एलॉयज प्राइवेट लिमिटेड, सेल-बंगाल एलॉय कास्टिंग्स प्राइवेट लिमिटेड, एसएएल-सेल जेवीसी लिमिटेड, टीएमटी एसएएल सेल जेवीसी लिमिटेड, अभिनव सेल जेवीसी लिमिटेड, एनएमडीसी सेल लिमिटेड, एस एंड टी माइनिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड और सेल कोबे आयरन इंडिया लिमिटेड।

अनुसार, संयुक्त उद्यम कंपनी को एक वित्तीय वर्ष में 10 लाख टन स्लैग उठाना था। 2016-17 से 2019-20 तक, भिलाई जेपी सीमेंट लिमिटेड ने करार के अनुसार प्रतिबद्ध मात्रा का केवल 2 से 3 प्रतिशत स्लैग ही उठाया। भिलाई इस्पात संयंत्र ने कम स्लैग उठाने के लिए, देर से भुगतान करने के लिए ब्याज और अन्य प्रभारों के लिए शास्ति उदग्रहित की। इसने संयुक्त उद्यम कंपनी को 30 सितंबर 2018 तक ₹53.89 करोड़ की कुल बकाया राशि के लिए नोटिस (नवंबर 2018) जारी किया। भिलाई जेपी सीमेंट लिमिटेड ने करार के अनुसार विवाद समाधान के लिए अनुरोध किया (दिसंबर 2018)। मार्च 2020 तक कुल बकाया ₹82.02 करोड़ था, जिसमें कम स्लैग उठाने के लिए ₹68.36 करोड़, देर से भुगतान के लिए ब्याज (₹1.08 करोड़), और अन्य प्रभारों (₹12.58 करोड़) की शास्ति शामिल थी। भिलाई इस्पात संयंत्र के विधि विभाग ने करार की शर्तों के अनुसार संयुक्त उद्यम कंपनी के विरुद्ध प्रशासनिक कार्रवाई की सलाह दी (मई 2017)।

ii) नवंबर 2015 में, जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी जयप्रकाश सीमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने यसबैंक लिमिटेड से ₹465 करोड़ का अंतरिम ऋण लिया। जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड (74 प्रतिशत) द्वारा रखे गए भिलाई जेपीसी मेंट लिमिटेड के शेयर को ऋण के मामले में प्रतिभूति के रूप में जय प्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड द्वारा यसबैंक लिमिटेड के पास गिरवी रखा गया था।

जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड और जयप्रकाश सीमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने ऋण की अदायगी में चूक की। इसके बाद, यसबैंक लिमिटेड ने एसेट्स केयर एंड रिकंस्ट्रक्शन एंटरप्राइज लिमिटेड को प्रतिभूति सहित ऋण आवंटित किया, जिसने अक्टूबर 2018 में जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड/ जयप्रकाश सीमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा भुगतान में चूक के कारण इस तरह के आह्वान का नोटिस देने का संकल्प लिया। जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड ने जनवरी 2019 में सेल को इन घटनाक्रमों के बारे में सूचित किया।

लेखापरीक्षा ने पाया कि सेल और जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड के बीच शेयरधारक करार के समाप्ति खंड 19.1 में अनुबंध किया गया है कि 'जिस तारीख को जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड की शेयर धारिता संयुक्त उद्यम कंपनी की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी के 50 प्रतिशत से कम हो जाती है, से जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड को नोटिस देकर करार समाप्त कर सकता है। इसके अलावा, खंड 19.2.6 यह निर्धारित करता है कि यदि कोई भी पार्टी शेयरों का अनधिकृत हस्तांतरण करता है तो करार समाप्त किया जा

सकता है। इस प्रकार, जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड द्वारा भिलाई जे पी सीमेंट लिमिटेड में अपने शेयरों को गिरवी रखकर शेयर धारक करार का महत्वपूर्ण उल्लंघन किया गया था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि सेल को तीन वर्षों (नवंबर 2015 से जनवरी 2019) से अधिक समय से उपरोक्त मामले की जानकारी नहीं थी, हालांकि भिलाई जेपी सीमेंट लिमिटेड के बोर्ड में सेल के तीन नामित निदेशक मौजूद थे। भिलाई जेपी सीमेंट लिमिटेड के बोर्ड में सेल नामित निदेशकों के विरुद्ध कार्रवाई की सिफारिश करने के लिए सेल में गठित एक समिति ने निष्कर्ष निकाला कि किसी भी नामित निदेशक की ओर से कोई लापरवाही नहीं थी क्योंकि उनमें से किसी को भी जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड द्वारा शेयरों के गिरवी रखने या जनवरी 2019 से पहले के आगामी घटनाक्रम के बारे में कोई सूचना नहीं थी। सेल के बोर्ड की उपसमिति ने पाया (अगस्त 2019) कि सेल के नामित निदेशकों को अधिक सतर्क होना चाहिए था और इन मुद्दों को सेल बोर्ड के ध्यान में बहुत पहले लाना चाहिए था। भिलाई जेपी सीमेंट लिमिटेड के मुद्दे (जुलाई 2019) पर इस्पात मंत्री द्वारा भी नाराजगी व्यक्त की गई थी।

भिलाई जेपी सीमेंट लिमिटेड लगातार घाटे (2013-14 से 2019-20) में था, और 31 मार्च 2020 को इसकी निवल सम्पत्ति नकारात्मक थी। भिलाई जेपी सीमेंट लिमिटेड का संचित घाटा 2019-20 में ₹457.87 करोड़ था। इस प्रकार, नकदी की स्थिति को देखते हुए, सेल को संयुक्त उद्यम कंपनी में इसके गठन के 13 वर्षों के बाद भी ₹52.51 करोड़ के निवेश का लाभ नहीं मिल सका। इसके अलावा, शास्ति/अन्य प्रभारों के कारण ₹82 करोड़ की वसूली भी अनिश्चित थी।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (मई 2021) कि भिलाई इस्पात संयंत्र ने बकाया शास्ति/देयों के लिए भिलाई जेपी सीमेंट लिमिटेड के साथ नियमित रूप से प्रयास किया है। सेल ने जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड द्वारा कार्रवाई में गम्भीर कपट जांचकर्ता अधिकारी द्वारा जांच शुरू करने और एसोसिएट्स केयर एंड रिकंस्ट्रक्शन एंटरप्राइज लिमिटेड के विरुद्ध निषेधाज्ञा के लिए राष्ट्रीय कम्पनी कानून अधिकारण में याचिका दायर की ताकि किसी तीसरी पार्टी को शेयरों के आगे हस्तांतरण को रोका जा सके।

लेखापरीक्षा ने पाया कि सेल बोर्ड ने जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड के विरुद्ध लगभग दो वर्ष (जनवरी 2019 से नवंबर 2020) के विलंब के बाद 6 नवंबर 2020 को कानूनी

कार्यवाही के लिए मंजूरी दी। बोर्ड के निर्णय के तीन महीने (22 फरवरी 2021) के बाद कानूनी कार्रवाई शुरू की गई थी।

2.4.5.2 सेल-एससीएल केरल लिमिटेड

केरल सरकार ने स्टील कॉम्प्लेक्स लिमिटेड¹⁷ को वित्तीय/तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए इस्पात मंत्रालय के माध्यम से सेल से संपर्क किया (मई 2007) ताकि इसे स्वतः स्थायी बनाया जा सके। सेल ने अपने प्रबंधन नियंत्रण के साथ समान शेयर होल्डिंग पैटर्न पर स्टील कॉम्प्लेक्स लिमिटेड के सह-प्रवर्तकों के रूप में मिलकर कार्य करने के लिए केरल सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए (मई 2008)। सेल ने केरल सरकार के साथ एक 'व्यावसायिक सहयोग और शेयरधारक करार (संयुक्त उद्यम करार)' पर हस्ताक्षर किए (दिसंबर 2008) और ₹8.38 करोड़ के लिए स्टील कॉम्प्लेक्स लिमिटेड (दिसंबर 2010) में 43.80 प्रतिशत¹⁸ शेयरों का अधिग्रहण किया। इसने नई रोलिंग मिल परियोजना के लिए इक्विटी योगदान के रूप में ₹9.71 करोड़ का और योगदान दिया। सेल और केरल सरकार के बीच संयुक्त उद्यम कंपनी का गठन 31 दिसंबर 2010 से प्रभावी हुआ था। 24 अप्रैल 2014 से कंपनी का नाम स्टील कॉम्प्लेक्स लिमिटेड से बदलकर सेल-एससीएल केरल लिमिटेड में कर दिया गया था।

- लेखापरीक्षा ने पाया कि कार्यशील पूंजी की अनुपलब्धता, उत्पादन की उच्च लागत, पुराने और अप्रचलित उपकरणों के कारण कंपनी का निष्पादन संतोषजनक नहीं था। 2014 में बिलेट का उत्पादन बंद कर दिया गया था। इसके बाद, जून 2015 में ₹51.21 करोड़ की लागत से 65,000 टन प्रति वर्ष थर्मो-मैकेनिकल ट्रीटेड बार रोलिंग मिल संस्थापित की गई थी। हालांकि, उत्पादन की उच्च लागत और बिलेट की अनुपलब्धता के कारण, थर्मो-मैकेनिकल ट्रीटेड बार रोलिंग मिल ने दिसंबर 2016 से काम करना बंद कर दिया था। सेल ने बिलेट्स को थर्मो-मैकेनिकल ट्रीटेड बार में बदलने के लिए रूपांतरण एजेंट¹⁹ के रूप में सेल-एससीएल केरल लिमिटेड को नियुक्त किया (अक्टूबर 2015)। रूपांतरण गतिविधियों को निलंबित कर दिया गया क्योंकि यह वित्तीय रूप से अव्यवहार्य

¹⁷ केरल राज्य आईडीसी विकास निगम द्वारा प्रवर्तित 55,000 टन बिलेट्स की वार्षिक संस्थापित क्षमता वाली एक कंपनी।

¹⁸ प्रत्येक ₹10 के 70 लाख शेयरों में से, केरल सरकार और उपक्रमों के पास 87.60 प्रतिशत शेयर थे और शेष वित्तीय संस्थानों/अन्य के पास थे।

¹⁹ सेल का एक एजेंट जो री-रोलेबल्स/सेमी/बिलेट्स को तैयार उत्पादों में बदलने का कार्य करता है।

था और फरवरी 2017 से रूपांतरण के लिए बिलेट की आपूर्ति बंद कर दी गई थी। प्रत्यक्ष सत्यापन के दौरान, प्रबंधन ने ₹2.49 करोड़ मूल्य के बिलेट/थर्मो-मैकेनिकल ट्रीटेड बार कम पाए।

- मार्च 2020 तक, सेल ने सेल-एससीएल केरल लिमिटेड में इक्विटी निवेश के रूप में ₹18.75 करोड़ का निवेश किया था। सेल ने ₹21.18 करोड़²⁰ की वित्तीय सहायता भी दी थी। केरल सरकार ने सेल-एससीएल केरल लिमिटेड को कार्यशील पूंजी ऋण के रूप में 13.50 प्रतिशत प्रतिवर्ष की ब्याज दर से ₹10.12 करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान की। दूसरी ओर सेल ने अपने वित्तीय हितों की रक्षा किए बिना ब्याज मुक्त अग्रिम प्रदान किया।
- सेल-एससीएल केरल लिमिटेड उत्पादन बंद होने और कार्यशील पूंजी की कमी के कारण नकदी संकट का सामना कर रहा था। केनरा बैंक को भुगतान में चूक के लिए ₹82.70 करोड़ की वसूली के लिए केनरा बैंक द्वारा एक आवेदन के अनुसरण में ऋण वसूली अधिकरण द्वारा नोटिस दिया गया था। उपरोक्त को देखते हुए, सेल-एससीएल केरल लिमिटेड से देयराशि की वसूली की संभावना कम लगती है।

लेखापरीक्षा ने देखा कि अस्वस्थ भागीदार के साथ संयुक्त उद्यम बनाने का निर्णय विवेकपूर्ण नहीं था क्योंकि स्टील कॉम्प्लेक्स लिमिटेड 16 वर्षों (1992 से 2008) से घाटे में चल रहा था। इसके अलावा, सेल-एससीएल केरल लिमिटेड की ऋण-सेवा क्षमता पर विचार किए बिना ब्याज मुक्त व्यापार अग्रिम देने के परिणामस्वरूप ₹39.93 करोड़ का निष्क्रिय निवेश हुआ। 31 मार्च 2020 को संयुक्त उद्यम कंपनी की निवल सम्पत्ति (-) ₹92.33 करोड़ थी। ब्याज मुक्त व्यापार अग्रिम के लिए सेल-एससीएल केरल लिमिटेड को अनुचित लाभ प्रदान करने के साथ ₹21.18 करोड़ के अग्रिम की वसूली की बहुत कम संभावना है।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (मई 2021) कि केरल सरकार द्वारा स्टील कॉम्प्लेक्स लिमिटेड की बैलेंसशीट को क्लीन स्लेट²¹ करने और नई रोलिंग मिल के लिए इक्विटी देने दोनों में

²⁰व्यापार अग्रिम (दिसम्बर 2007 और जुलाई 2011) ₹8 करोड़ इक्विटी के प्रति अग्रिम (फरवरी 2015): ₹3.52 करोड़ स्ट्रैप/बिलेट (जून 2015) की आपूर्ति के प्रति प्राप्य: ₹4.20 करोड़ रूपांतरण के प्रति अग्रिम: ₹2.97 करोड़ विलेट्स की कमी: 2.49 करोड़।

²¹तुलन-पत्र की क्लीन-स्लेटिंग का अर्थ आम तौर पर यह होता है कि किसी इकाई के पास बहुत कम या कोई ऋण नहीं है।

अत्यधिक विलंब के परिणामस्वरूप क्रमशःसंयुक्त उद्यम करार के प्रचालन और रोलिंग मिल की संस्थापना में विलंब हुआ जिससे संयुक्त उद्यम कंपनीकी वित्तीय स्थिति प्रभावित हुई।

तथ्य यह है कि 13 वर्ष पहले गठित संयुक्त उद्यम कंपनी में ₹39.93 करोड़ के निवेश से अभी भी सेल को लाभ मिलना था।

2.4.5.3 सेल और एमओआईएल फेरो एलॉयज प्राइवेट लिमिटेड

सेल और मैंगनीज ओर इंडिया लिमिटेड ने जुलाई 2008 में उच्चकार्बन फेरो मैंगनीज (एचसी एफइएमएन) और सिलिको-मैंगनीज (एसआईएमएन) का उत्पादन करने के लिए एक 50:50 संयुक्त उद्यम कंपनी का गठन किया, जिसका नाम सेल और एमओआईएल फेरो एलॉयज प्राइवेट लिमिटेड था। प्रारंभिक प्रदत्त पूंजी ₹0.20 करोड़ थी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि संयुक्त उद्यम कंपनी के गठन के 12 वर्षों के बाद भी कोई प्रगति नहीं हुई थी। सेल द्वारा फेरो एलॉय की आवश्यकता में लगातार परिवर्तन होते रहे। संयुक्त उद्यम कंपनी द्वारा प्रस्तावित परियोजना क्षेत्र में विद्युत की मौजूदा कीमतों पर व्यवहार्य नहीं पाई गई। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, सेल बोर्ड ने संयुक्त उद्यम कंपनी को बंद करने का निर्णय लिया (जून 2017)। संयुक्त उद्यम कंपनी ने सेल को ₹12 करोड़ के भू-पट्टा प्रीमियम की लागत का भुगतान नहीं किया। सेल ने 2009-10 में प्राप्त के रूप में पट्टा प्रीमियम राशि के प्रति ₹4.54 करोड़ के पूंजीगत अभिलाभ कर का भुगतान किया।

लेखापरीक्षा ने पाया कि सेल को संयुक्त उद्यम कंपनी²² से अपेक्षित लाभ नहीं मिल सका। संयुक्त उद्यम कंपनी को स्थापना के बाद से नियमित रूप से घाटा हुआ था जो मार्च 2020 तक ₹14.16 करोड़ तक संचित हुआ था। संयुक्त उद्यम कंपनी से ₹12 करोड़ प्राप्त होने की संभावना बहुत कम थी। इसके अलावा, पूंजीगत अभिलाभ कर के लिए भुगतान किए गए ₹4.54 करोड़ भी व्यर्थ हो गए।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (मई 2021) कि सेल बोर्ड ने संयुक्त उद्यम कंपनी से सेल के बाहर निकलने के तौर-तरीकों को मंजूरी दी (30 दिसंबर 2020) और संयुक्त उद्यम कंपनी को बंद करने के लिए 22 मार्च 2021 को कंपनी पंजीयक के पास आवेदन दाखिल किया गया था। सेल ने प्राधिकारियों के साथ पूंजीगत अभिलाभ करके प्रतिदाय के मुद्दे को उठाने की योजना बनाई है।

²²2015 की सी एंड एजी की रिपोर्ट नंबर 21 में इस मुद्दे को उजागर किया गया था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि सेल बोर्ड के निर्णय के चार वर्ष बाद भी संयुक्त उद्यम कंपनी को अभी भी बंद किया जाना था (मई 2021)। इसके अलावा, 10 वर्ष पहले भुगतान किए गए पूंजीगत अभिलाभ कर के प्रतिदाय की कम संभावना थी।

2.4.5.4 एसएंडटी माइनिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड

सेल ने सितंबर 2008 में 50:50 इक्विटी भागीदारी के साथ टाटा स्टील लिमिटेडके साथ एक संयुक्त उद्यम कंपनी का गठन किया, जिसका नाम एसएंडटी माइनिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड था। सेल का योगदान ₹12.94 करोड़ था। संयुक्त उद्यम कंपनी का उद्देश्य कोयला खदानों का अन्वेषण और विकास था। लेखापरीक्षा ने पाया कि भुटगोरिया खानों में अपनी बंद कोयला खानों से कोकिंग कोल के खनन और भेलटांड में एक कोकिंग कोल वाशरी परियोजना स्थापित करने के लिए संयुक्त उद्यम कंपनी के प्रयासों को मूर्तरूप प्रदान नहीं किया गया।

लेखापरीक्षा ने देखा कि संयुक्त उद्यम कंपनी स्थापना से ही घाटे में थी और उन उद्देश्यों को पूरा नहीं कर सकी जिनके लिए इसका गठन²³ किया गया था। सेल बोर्ड ने संयुक्त उद्यम कंपनी को बंद करने का निर्णय लिया (जून 2017)। टाटा स्टील लिमिटेड समापन/बंद करने के प्रस्ताव के साथ सहमत (जनवरी 2018) थी और दिसंबर 2018 में एस एंड टी माइनिंग कंपनी द्वारा स्वैच्छिक परिसमापन का प्रस्ताव सेल को प्रस्तुत किया गया था। सेल बोर्ड ने मार्च 2019 में संयुक्त उद्यम कंपनी के स्वैच्छिक परिसमापन को मंजूरी दी। सेल और टाटा इस्पात लिमिटेड दोनों ने जून 2019 में संयुक्त उद्यम कंपनी को बंद करने के खर्च को कवर करने के लिए इक्विटी के रूप में ₹5.20 करोड़ का योगदान दिया। इस प्रकार अभिदान की गई और प्रदत्त इक्विटी पूंजी बढ़कर ₹36.28 करोड़ हो गई। सेल का योगदान बढ़कर ₹18.14 करोड़ हो गया। इसके अलावा, सेल ने ₹18.14 करोड़ के अंकित मूल्य वाली एसएंडटी माइनिंग कंपनी में अपनी 50 प्रतिशत हिस्सेदारी टाटा इस्पात लिमिटेड को ₹1 पर बेचने का फैसला (सितंबर 2020) किया। इस प्रकार, ₹18.14 करोड़ का निवेश निष्फल हो गई।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (मई 2021) कि परियोजनाओं का संचालन नहीं किया जा सका क्योंकि भुटगोरिया की खदानें व्यवहार्य नहीं पाई गईं और भेलटांड वाशरी के लिए कच्चे

²³सी एंड एजी की 2015 की रिपोर्ट नंबर 21 में इस मुद्दे को उजागर किया गया था।

कोयले के लिए लिंकेज की अनुपस्थिति के कारण भी नहीं किया जा सका। हालांकि, प्रबंधन के उत्तर में संयुक्त उद्यम कंपनी में अपनी 50 प्रतिशत हिस्सेदारी टाटा इस्पात लिमिटेड को ₹1 पर बेचने से संबंधित मुद्दे पर कुछ उल्लेख नहीं किया गया था। संयुक्त उद्यम कंपनी में सेल के ₹18.14 करोड़ के निवेश से कंपनी को कोई लाभ नहीं हो सका।

सिफारिश संख्या 4: संयुक्त उद्यमों/अन्य में निधियों के निवेश के लिए नीति तैयार की जा सकती है और इष्टतम प्रतिफल सुनिश्चित करने के लिए निधियों का विवेकपूर्ण तरीके से निवेश किया जाना चाहिए।

2.4.6 लाभांश पर निवेश और सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग के दिशानिर्देशों का अनुपालन न करना

निवेश और सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग, वित्त मंत्रालय ने 27 मई 2016 को केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के पूंजी पुनर्गठन पर दिशानिर्देश जारी किए। लाभांश के लिए दिशानिर्देश 31 मार्च 2016 को या उसके बाद समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष से लागू थे। दिशानिर्देशों के पैरा 5 में कहा गया है कि प्रत्येक सीपीएसई कर के बाद लाभ के 30 प्रतिशत या निवल सम्पत्ति के पांच प्रतिशत, जो भी अधिक हो, का न्यूनतम लाभांश का भुगतान करेगा, जो कि मौजूदा कानूनी प्रावधानों के तहत अनुमत अधिकतम लाभांश के अधीन है। सेल द्वारा कर के बाद लाभ, निवल सम्पत्ति और सेल द्वारा प्रदत्त और देय लाभांश का विवरण नीचे तालिका में दिया गया है:

तालिका 2.8: सेल द्वारा कर के बाद लाभ, निवल सम्पत्ति, देय और प्रदत्त लाभांश का विवरण

(राशि: ₹ करोड़ में)

वर्ष	कर के बाद लाभ (हानि)	कुल सम्पत्ति	देय लाभांश	प्रदत्त लाभांश	निवेश और सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग से छूट की प्राप्ति
2015-16	(-) 4021	39196	1960	0	छूट प्राप्त
2016-17	(-) 2833	36009	1800	0	छूट प्राप्त
2017-18	(-) 482	35714	1786	0	छूट प्राप्त
2018-19	2179	38152	1908	206.53	सेल द्वारा मांगी गई छूट
2019-20	2022	39777	1989	0	सेल द्वारा मांगी गई छूट
कुल			9443	206.53	

लेखापरीक्षा ने नोट किया कि भारत सरकार की सेल की इक्विटी में 75 प्रतिशत²⁴ (31 मार्च 2020 तक) शेयरधारिता थी। सेल ने इससे पहले इस्पात मंत्रालय के माध्यम से निवेश और सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग से वित्तीय वर्ष 2015-16, 2016-17 और 2017-18 के लिए लाभांश के भुगतान पर दिशानिर्देशों का पालन करने से छूट प्राप्त करने के लिए आवेदन किया था। सीपीएसइ में सरकारी निवेश की प्रबंधन समिति ने सेल को उपर्युक्त अवधि के लिए लाभांश के भुगतान से छूट दी थी। सेल ने इस्पात मंत्रालय के माध्यम से निवेश और सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग से वित्त वर्ष 2018-19 के लिए प्रदत्त शेयर पूंजी के 5 प्रतिशत की कम दर पर लाभांश की छूट के लिए अनुरोध किया। 2019-20 के लिए, सेल ने छूट के लिए निवेश और सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग के साथ मामले को उठाने का मंत्रालय (अगस्त 2020) से अनुरोध किया। वर्ष 2018-19 और 2019-20 के लिए छूट अभी तक प्राप्त होनी।

लेखापरीक्षा में नोट किया गया कि 2015-20 के दौरान सेल द्वारा ₹9,443 करोड़ का लाभांश देय था। सेल को वर्ष 2015-18 के लिए ₹5,546 करोड़ के सम्बन्ध में छूट मिली थी। कंपनी ने 2018-19 के दौरान नाममात्र लाभांश (प्रदत्त शेयर पूंजी का 5 प्रतिशत होने के नाते ₹206.53 करोड़) की घोषणा की और लाभ में होने के बावजूद 2019-20 के दौरान कोई लाभांश नहीं दिया। इस प्रकार, सेल ने निवेश और सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए वर्ष 2018-19 और 2019-20 के लिए अपने शेयरधारकों (भारत सरकार सहित) को ₹3,690 करोड़ (₹3,897 करोड़ - ₹207 करोड़) की राशि के लाभांश का भुगतान नहीं किया है।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (मई 2021) कि सेल ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए लाभांश के भुगतान में छूट के लिए अनुरोध किया था। वित्तीय स्थिति में सुधार के साथ सेल ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए अंतरिम लाभांश का भुगतान किया।

वर्ष 2018-19 के लिए लाभांश की छूट के मुद्दे पर प्रबंधन के उत्तर में उल्लेख नहीं है। इसके अलावा, लाभांश के भुगतान से छूट प्राप्त करके या छूट की मांग करके, शेयरधारकों को उनके निवेश पर प्रतिफल से इनकार कर दिया गया था। लाभांश के अलावा, सरकार

²⁴ भारत सरकार - 75 प्रतिशत, बीमा कंपनियां - 10.02 प्रतिशत, सार्वजनिक - 5.82 प्रतिशत, म्यूचुअल फंड - 3.60 प्रतिशत, एफआईआई - 2.91 प्रतिशत, बैंक, बॉडी कॉर्पोरेट और अन्य - 2.65 प्रतिशत।

को शेयरधारकों को भुगतान किए गए लाभांश पर लागू लाभांश कर से भी वंचित कर दिया गया था।

2.4.7 सेलम इस्पात संयंत्र, विश्वेश्वरैया लौह एवं इस्पात संयंत्र और एलाय स्टील प्लांट के विनिवेश में विलंब

आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति, भारत सरकार ने 27 अक्टूबर, 2016 को सेल की तीन इकाइयों अर्थात् सेलम इस्पात संयंत्र, विश्वेश्वरैया लौह और इस्पात संयंत्र और एलाय स्टील प्लांट के नीतिगत विनिवेश के लिए 'सैद्धांतिक' अनुमोदन प्रदान किया। तीन संयंत्र (सेलम इस्पात संयंत्र, विश्वेश्वरैया लौह और इस्पात संयंत्र और एलाय स्टील प्लांट) 2011-12 से सेल की घाटे में चल रही इकाइयां थीं और सेल को अकेले 2017-20 के दौरान इन तीन इकाइयों में ₹1,262 करोड़ की संचयी हानि हुई थी। विनिवेश की पूर्ण प्रक्रिया समयबद्ध तरीके से किए जाने की आवश्यकता थी। तथापि, लेखापरीक्षा में कहा गया कि विनिवेश के निर्णय के चार वर्ष बीत जाने के बावजूद इस्पात संयंत्रों का विनिवेश प्रारंभिक चरण में था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि:

- (i) प्रबंधन ने 27 अक्टूबर 2016 को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति के अनुमोदन की तारीख से नीतिगत विनिवेश के लिए बोर्ड के अनुमोदन में तीन महीने से अधिक का समय लिया।
- (ii) डीआईपीएम द्वारा जारी मार्गदर्शन नोट (मई 2018) के अनुसार, पहला कदम सलाहकारों की नियुक्ति करना था, उसके बाद प्रारंभिक सूचना जापन/रुचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित करना था। सेल ने लेन-देन सलाहकार, कानूनी सलाहकार और परिसंपत्ति मूल्यांकक को नियुक्ति पत्र जारी करने में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति के अनुमोदन से लगभग आठ महीने और कर-सह-लेखांकन सलाहकार की नियुक्ति के लिए दस महीने का समय लिया। सेलम इस्पात संयंत्र और विश्वेश्वरैया लौह एवं इस्पात संयंत्र के लिए प्रारंभिक सूचना जापन/रुचि की अभिव्यक्ति को जारी करने में लेन-देन सलाहकार की नियुक्ति की तारीख से लेकर 24 महीने से अधिक का समय लगा। 14 फरवरी 2018 को और 4 जुलाई 2019 को जारी किए गए एलाय स्टील प्लांट के लिए प्रारंभिक सूचना जापन/रुचि की अभिव्यक्ति के लिए कोई रुचि की अभिव्यक्ति प्राप्त नहीं हुई।

- (iii) प्रबंधन ने जुलाई 2020 में लेनदेन सलाहकार के साथ गोपनीय सूचना जापन से संबंधित सूचना साझा की, जबकि प्रारंभिक सूचना जापन/रुचि की अभिव्यक्ति जुलाई 2019 में जारी की गई थी। इस प्रकार, गोपनीय सूचना जापन तैयार करने के लिए लेन-देन सलाहकार को वांछित सूचना प्रदान करने में एक वर्ष का विलंब हुआ।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि विनिवेश प्रक्रिया में विलंब हुआ था। सीपीएसई के विनिवेश की प्रास्थिति की समीक्षा के दौरान प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव ने एलाय स्टील प्लांट और विश्वेश्वरैया लौह एवं इस्पात संयंत्र के मामले में विनिवेश प्रक्रिया में मंत्रालय और सेल के स्तर पर अनुचित विलंब को देखा।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (मई 2021) कि सेल की इन तीन इकाइयों में विनिवेश प्रक्रिया अंतर-मंत्रालयी समूह के मार्गदर्शन से चल रही थी। सेल ने कदम-दर-कदम सभी प्रक्रियाओं का पालन किया है और विनिवेश प्रक्रिया में कोई विलंब नहीं हुआ।

उत्तर को इस तथ्य के मद्देनजर देखा जा सकता है कि डीआईपीएएम ने वित्तीय बोलियां खोलने और नीतिगत भागीदार के अनुमोदन के लिए अंतर-मंत्रालयी समूह को सिफारिश करने के लिए अंतर-मंत्रालयी समूह के गठन की तारीख से 202 दिनों (अर्थात् 15 जून 2017) की समय सीमा तैयार की थी। अंतर-मंत्रालयी समूह का गठन 25 नवंबर 2016 को किया गया था। मई 2021 तक इन इकाइयों का विनिवेश चार वर्ष से अधिक बीतने के बाद भी पूरा नहीं हुआ था।

2.4.8 प्राप्य राशियों का प्रबंधन

केन्द्रीय विपणन संगठन के माध्यम से बिक्री सेल की कुल बिक्री का लगभग 85-90 प्रतिशत है। इस्पात सामग्री क्रेडिट पर भी बेची जाती (दोनों प्रतिभूत और अप्रतिभूत) थी। केन्द्रीय विपणन संगठन की क्रेडिट नीति में क्रेडिट का विस्तार करने के लिए ग्राहक की उपयुक्तता का निर्णय लेने, इसमें शामिल जोखिम को कम करने और क्रेडिट की स्वीकृति और मानीटरिंग के लिए पद्धति का निर्णय करने के लिए दिशानिर्देश निर्धारित किए गए हैं। वर्ष 2009 में जारी सेल की मौजूदा क्रेडिट पालिसी को 2014 में संशोधित किया गया था। लेखापरीक्षा ने पाया कि, हालांकि मौजूदा क्रेडिट पॉलिसी की समीक्षा के लिए निदेशक (वाणिज्यिक) के निर्देशों पर एक समिति का गठन किया गया था (नवंबर 2018), और

इसने जनवरी 2019 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, लेकिन क्रेडिट पालिसी को अभी संशोधित किया जाना था।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (मई 2021) कि सुझावों की समीक्षा करने और 30 सितंबर 2021 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए एक नई समिति का गठन किया जा रहा था।

2.4.8.1 ग्राहकों से देय राशि की वसूली में विलंब

देनदार या प्राप्य सामान्य कारोबार में माल या सेवाओं की बिक्री से ग्राहकों द्वारा फर्म को बकाया राशि के द्योतक होते हैं। पिछले पांच वर्षों के दौरान सेल में व्यापार प्राप्य राशियों, संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान और देनदार टर्नओवर अनुपात²⁵ का ब्यौरा नीचे तालिका में दिया गया है:

तालिका: 2.9

पिछले पांच वर्षों के दौरान सेल में व्यापार प्राप्य राशियां, संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान और देनदारों के टर्नओवर अनुपात

(राशि: ₹ करोड़ में)

वर्ष	कुल बिक्री	राशियों को व्यापार प्राप्य 31मार्च	संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	देनदार टर्नओवर अनुपात (दिनों की संख्या में *) या औसत संग्रहण अवधि
2015-16	43342	3297	153	51
2016-17	49114	3098	176	57
2017-18	58215	4060	190	48
2018-19	66165	4693	198	51
2019-20	60902	9020	208	61

* 365 / देनदार टर्नओवर अनुपात। इसे औसत संग्रहण अवधि के रूप में भी जाना जाता है।

यह देखा गया था कि देनदार ₹3,297 करोड़ (2015-16) से बढ़कर ₹9,020 करोड़ (2019-20) हो गए थे। 82 प्रतिशत से अधिक देनदार रक्षा, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और रेलवे जैसी सरकारी एजेंसियों से संबंधित थे। कंपनी ने 2019-20 के लिए संदेहास्पद वसूली के लिए लेखाओं में ₹208 करोड़ का प्रावधान किया था, जिसमें से ₹134 करोड़ (64 प्रतिशत) सरकारी एजेंसियों से संबंधित थे। सेल में देनदारों से औसत संग्रहण अवधि 48 से 61 दिनों के बीच थी। सरकारी विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से उगाही

²⁵ देनदारों का टर्नओवर अनुपात: निवल क्रेडिट बिक्री / औसत व्यापार प्राप्य

में विलम्ब²⁶ के कारण उच्चतर संग्रहण अवधि रही जो सरकारी/रक्षा/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के ग्राहकों से विलंबित भुगतान के लिए ब्याज प्रभारित न करने और प्रमुख ग्राहकों को बिल प्रस्तुत करने के लिए मानक प्रचालन प्रक्रिया के अभाव के कारण था। उच्च संग्रहण अवधि के परिणामस्वरूप निधियां अवरुद्ध हुईं और उधार लेने की लागत अधिक रही। चूंकि उपरोक्त ग्राहकों से वसूली में विलंब की भरपाई ब्याज के भुगतान से नहीं की गई थी, इसलिए तीन महीने से अधिक के विलंब से उपर्युक्त अतिदेय भुगतान के कारण कंपनी को ₹262 करोड़ प्रति वर्ष की लागत होगी, जैसा कि केंद्रीय विपणन संगठन की देनदार समीक्षा समिति द्वारा किए गए विश्लेषण (जनवरी 2019) से निकाला गया है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि ₹242.38 करोड़ की राशि के 1,922 चालानों में, प्रत्येक बीजक के मूल्य का 80 प्रतिशत से अधिक (₹241.66 करोड़ की राशि) 101 और 1,959 दिनों के बीच की अवधि के लिए अप्राप्य रहा। इसके अलावा, ऐसे बीजक प्रबंधन के पास आसानी से उपलब्ध नहीं थे जो देनदारों पर प्रभावी नियंत्रण के अभाव को दर्शाता है।

तालिका: 2.10

कुछ प्रमुख ग्राहकों वाले मुद्दे जिसके कारण उच्च संग्रहण अवधि रही और लंबे समय से अतिदेय भुगतान रहे

ग्राहक का नाम	सेल द्वारा आपूर्ति की गई सामग्री	31 मार्च 2020 को देनदार	औसत संग्रहण अवधि	वसूली में विलंब के कारण
भारतीय रेल	रेल, व्हील और एक्सल और अन्य लंबे और फ्लैट उत्पाद	₹6,208 करोड़	72दिन (2016-17)से 168दिन (2019-20)	रेलवे के पास बजट की बाधाएं (₹5,803.85 करोड़), रसीद नोटों की प्राप्ति न होना/रसीद नोटों में कमियां (₹60.46 करोड़), परेषिती पुष्टि की अनुपस्थिति, निरीक्षण प्रमाण पत्र/रेलवे रसीदों की प्राप्ति न होना, रेलवे बोर्ड द्वारा आबंटन के विरुद्ध क्षेत्रीय रेल प्राधिकारियों द्वारा कवरिंग खरीद आदेश जारी न करना (₹143.31 करोड़)।

²⁶रेलवे के मामले में 60 से 90 दिन, भेल, एनटीपीसी, एल एंड टी आदि जैसे परियोजना ग्राहकों के मामले में 90-120 दिन, रक्षा के मामले में 90-180 दिन।

एनटीपीसी लिमिटेड	फ्लैट उत्पाद	₹77.31 करोड़	36दिन (2016-17) से 107 दिन (2019-20)	एनटीपीसी से प्रभारित किए गए मूल्य का निर्णय तिमाही आधार पर किया गया था और इसे तिमाही के पहले महीने की 15 तारीख तक सूचित किया जाना था। सेल द्वारा त्रैमासिक कीमतों की सूचना में 10 से 124 दिनों का विलंब हुआ। इसके परिणामस्वरूप जुलाई 2017 से सितंबर 2020 के दौरान ₹8.15 करोड़ (की गई आपूर्ति के लिए राजस्व अंतर को पूरा करने के लिए उधार लागत के कारण) का परिहार्य व्यय हुआ।
भेल	प्लेट, शीट, संरचनात्मक, थर्मोमकेनिकली ट्रीटेड बार	₹308.14 करोड़	12 दिन (2018-19) से 57 दिन (2019-20)	भेल के साथ सहमति जापन में सभी त्रुटियों से रहित परेषण, बीजक और अन्य दस्तावेजों की प्राप्ति के 60 दिनों (अक्टूबर 2018 से संशोधित करके 120 दिन किया गया) के बाद भुगतान का प्रावधान है। लेखापरीक्षा में पाया गया कि भेल को आपूर्ति के प्रति वसूली के लिए लिया गया समय सहमति जापन में सहमत अवधि से अधिक था और यह 1,164 दिनों तक था।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (मई 2021) कि 50-60 दिनों की संग्रहण अवधि उचित प्रतीत होती है। 31 मार्च 2021 तक, कुल रेलवे देनदार लगभग ₹3,900 करोड़ थे। एनटीपीसी के मामले में (31 मार्च 2021 तक ₹109.41 करोड़ बकाया थे), कुछ मामलों में 120 दिनों तक भी विलम्ब हुआ और कुछ मामलों में विलम्ब कंपनी प्रबंधन की ओर से प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त करने में रहा। भेल के मामले में, मई 2021 तक ₹16.50 करोड़ बकाया थे।

प्रबंधन के उत्तर पर इस तथ्य के मद्देनजर विचार किया जा सकता है कि अकेले रेलवे से संग्रहण की अवधि 2019-20 और 2020-21 में 5 महीने से अधिक थी और इस तथ्य के मद्देनजर भी विचार किया जा सकता है कि सेल में देनदारों से औसत संग्रहण अवधि 48 से 61 दिनों के बीच थी जो काफी अधिक थी। प्रबंधन ने प्रशासनिक अनुमोदन में विलंब को स्वीकार किया था। इसके अलावा, भेल को बिलों के वास्तविक रूप से प्रस्तुत किए जाने की तारीख का पता लगाने के लिए किसी प्रणाली के अभाव में, लेखापरीक्षा में

प्रस्तुत करने में विलंब की मात्रा निर्धारित नहीं की जा सकी। प्रबंधन ने बिल प्रस्तुत करने की वास्तविक तारीख को अभिग्रहण करने के लिए एक प्रणाली स्थापित करने का आश्वासन दिया था।

सिफारिश संख्या 5: कंपनी त्रैमासिक कीमतों को समय पर अंतिम रूप देने और सूचित करने के लिए प्रयास कर सकती है और एनटीपीसी को अनंतिम कीमत के आधार पर भुगतान करने के लिए समझा सकती है।

2.4.8.2 क्रेडिट बिक्री पर ब्याज का त्रुटिपूर्ण प्रशासन

केन्द्रीय विपणन संगठन की क्रेडिट पालिसी में यह निर्धारित किया गया था कि ब्याज सामान्य या शास्तिक, जैसा भी लागू हो और 18 प्रतिशत पर जीएसटी को विस्तारित क्रेडिट सुविधा समय समय पर घोषित दरों पर प्रभारित किया जाएगा। लेखापरीक्षा में क्रेडिट बिक्री पर ब्याज के प्रशासन में निम्नलिखित कमियों को पाया गया।

(i) ब्याज प्रभारित करने में विलंब

सिस्टम एप्लीकेशन और उत्पाद प्रणाली में प्रचलित तंत्र के अनुसार, ब्याज बिल तब तक नहीं बनाए जा सकते जब तक कि क्रय आदेश (कई बीजकों से मिलकर) के प्रति कुल बकाया की पूरी तरह से उगाही नहीं की जाती है, भले ही आपूर्ति आदेश/बीजक के प्रति बहुत मामूली राशि लंबित हो।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि ग्राहकों पर ब्याज बिल बनाने के लिए किसी भी विशिष्ट समय सीमा के अभाव में, बीजक के प्रति अंतिम भुगतान की तारीख के बाद 1,648 दिनों²⁷ तक का विलंब हुआ। इसके परिणामस्वरूप ग्राहकों को अनुचित लाभ प्रदान किया गया क्योंकि मूलधन (बीजक मूल्य) के अंतिम भुगतान की तारीख तक ब्याज प्रभारित किया जाता है और अप्रदत्त रही ब्याज राशि पर ब्याज प्रभारित नहीं जाता है। इस प्रकार, समय पर ब्याज प्रभारित न करने के कारण क्रेडिट सीमा को अनावश्यक रूप से बढ़ाया गया था। चूंकि ब्याज बिलों के सृजन में विलंब के परिणामस्वरूप वसूली में परिणामी विलंब हुआ, सेल को 2015-16 से 2019-20 की अवधि के दौरान उधार ली गई निधियों पर ₹7.78 करोड़ की वित्त लागत वहन करनी पड़ी।

²⁷ 7 दिनों तक: 35 प्रतिशत, 8-30 दिन: 21 प्रतिशत, 31-60 दिन: 15 प्रतिशत, 61-180 दिन: 19 प्रतिशत और 180 दिनों से अधिक: 10 प्रतिशत

लेखापरीक्षा ने यह भी नोट किया कि 2015-16 से 2019-20 के दौरान, मूलधन की वसूली के लम्बित रहते 1,250 दिनों तक की अवधि के लिए 165 बीजकों में आज तक ₹18 करोड़ की राशि का ब्याज प्रभारित नहीं किया गया था, जो बीजक मूल्य के 5 प्रतिशत से कम था। इसी तरह, ₹8.93 करोड़ की राशि के 78 बीजकों के मामले में, 865 दिनों तक ब्याज प्रभारित नहीं किया गया था।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (मई 2021) कि अगस्त 2020 के दौरान ब्याज बिल तैयार करने के माँड्यूल पर फिर से विचार किया गया था। अगस्त 2020 से यथा संशोधित नया ब्याज बिल तैयार करने का प्रोग्राम बीजक मूल्य की वसूली पर ब्याज बिल के तैयार करने पर आधारित है और इसलिए ब्याज बिल तुरंत तैयार किया जा सकता था।

प्रबंधन के उत्तर को इस तथ्य के मद्देनजर देखा जा सकता है कि सेल को ब्याज प्रभारित करने में विलंब के कारण 2015-16 से 2018-19 के दौरान परिहार्य हानि हुई और प्रबंधन द्वारा केवल अगस्त 2020 में सुधारात्मक कार्रवाई की गई।

(ii) ब्याज की वसूली में विलंब

क्रेडिट पॉलिसी के अनुसार, क्रेडिट बिक्री के प्रति वसूल की गई राशि को पहले मूलधन अर्थात् भौतिक मूल्य के प्रति समायोजित किया जाएगा, उसके बाद ब्याज दिया जाएगा। अगले लेनदेन के लिए भौतिक मूल्य की वसूली शुरू करने से पहले पूर्ण ब्याज को समायोजित किया जाएगा।

2015-16 से 2019-20 के दौरान क्रेडिट बिक्री पर प्रभारित किया गया ब्याज ₹593.01 करोड़ बनता था। इस संबंध में, लेखापरीक्षा में पाया गया कि बाद के बीजकों के मूलधन के समायोजन से पहले प्रभारित किए गए ब्याज की पूरी वसूली नहीं की गई थी, जिसके परिणामस्वरूप ब्याज की वसूली में 1,460 दिनों²⁸ तक का विलंब हुआ (39 प्रतिशत मामलों में 60 दिनों से अधिक) जो वित्तपोषण की लागत के लिए ₹7.96 करोड़²⁹ के परिणामी बोझ के साथ था।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (मई 2021) कि ब्याज की प्राप्ति में विलंब हुआ, लेकिन यह मुख्य रूप से लार्सन एंड टुब्रो तक सीमित था। 2020-21 में विशेष अभियान चलाया गया था

²⁸30 दिनों तक: 57392 मामले, 31-60 दिन: 16,630 मामले, 61-180 दिन: 27,370 मामले, >180 दिन: 19,292 मामले।

²⁹2015-20 के दौरान लागू वित्त की लागत की न्यूनतम दर को मानते हुए अर्थात् 7.51 प्रतिशत।

और 2018-19 तक प्राप्य ब्याज समायोजित किया गया था। तथापि, प्रबंधन के उत्तर में बाद के बीजकों के मूलधन के समायोजन से पहले ब्याज की पूर्ण वसूली न करने पर क्रेडिट पालिसी के उल्लंघन पर उल्लेख नहीं किया गया है।

(iii) विलंबित वसूली पर ब्याज की वसूली न होना

लेखापरीक्षा में नोट किया गया कि सेल द्वारा भेल, रक्षा, एनटीपीसी आदि को सामग्री की आपूर्ति में विलंब के लिए निर्णीत हर्जानों का भुगतान किया जाता है। तथापि, कंपनी इस संबंध में किसी सक्षम खंड के अभाव के कारण इन ग्राहकों को विस्तारित क्रेडिट अवधि के बाद देय राशियों की वसूली में विलंब के लिए प्रभारित ब्याज नहीं करती है। 2015-16 से 2019-20 के दौरान, इन ग्राहकों ने सामग्री की आपूर्ति में विलंब के कारण निर्णीत हर्जानों के रूप में ₹89.91 करोड़ की कटौती की। दूसरी ओर, ब्याज मुक्त क्रेडिट दिनों से आगे बकाया राशि की वसूली में विलंब के कारण इन ग्राहकों से ₹170.89 करोड़ की राशि का ब्याज (प्रत्येक वर्ष के दौरान अतिदेय राशियों पर न्यूनतम लागू ब्याज को ध्यान में रखते हुए) प्रमार्थ था। तथापि, केन्द्रीय विपणन संगठन प्रभार्य ब्याज के प्रति निर्णीत हर्जाने को समायोजित नहीं कर सका।

प्रबंधन ने कहा (मई 2021) कि इन ग्राहकों को नीतिगत महत्व वाला माना गया था और क्रेडिट पालिसी के अनुसार ब्याज माफ कर दिया गया था। तथापि, इसने ऐसे ग्राहकों द्वारा भुगतान में विलम्ब की स्थिति में ब्याज प्रभारित करने के लिए सक्षम खंड की अनुपस्थिति के तथ्य को स्वीकार किया। प्रबंधन ने आगे कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और सरकारी संगठनों द्वारा एक बार जीईएम के माध्यम से अधिप्राप्ति का विकल्प चुनने पर भुगतान को सुव्यवस्थित किए जाने की उम्मीद थी।

प्रबंधन के उत्तर पर इस तथ्य के मद्देनजर विचार किया जा सकता है कि जबकि सेल ने ब्याज को माफ कर दिया था, इसने उन्हीं ग्राहकों को निर्णीत हर्जाने के रूप में काफी राशि का भुगतान किया था।

सिफारिश संख्या 6: कंपनी अपने वित्तीय हित की रक्षा के लिए नियत तारीखों के बाद देयों की वसूली के मामले में ब्याज के उद्ग्रहण के लिए एक खंड को शामिल करने का प्रयास कर सकती है।

2.4.8.3 कीमत भिन्नता के लिए डेबिट नोट प्रस्तुत करने में विलंब

पूर्वव्यापी प्रभाव से केन्द्रीय विपणन संगठन द्वारा जारी किए गए कीमत परिपत्रों और केन्द्रीय विपणन संगठन के शाखा बिक्री कार्यालयों द्वारा प्रदान की गई छूटों के अनुमोदन/अस्वीकृति के आधार पर ग्राहकों को डेबिट/क्रेडिट नोट जारी किए जाते हैं। इस संबंध में, लेखापरीक्षा ने नोट किया कि 66 प्रतिशत मामलों³⁰ में, एक महीने के दौरान कीमत परिवर्तनों को बाद के महीने में डेबिट नोट जारी करके विनियमित किया गया था। हालांकि, डेबिट नोटों को प्रस्तुत करने के लिए किसी विशिष्ट समय सीमा के अभाव में, लेखापरीक्षा ने 30 दिनों को एक उचित अवधि के रूप में माना और 2015-16 से 2019-20 के दौरान ₹228.52 करोड़ के डेबिट नोटों को प्रस्तुत करने में 1,800 दिनों तक का विलंब देखा, जिसके परिणामस्वरूप 2015-20 के दौरान ₹2.43 करोड़ की अतिरिक्त वित्त लागत आई।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (मई 2021) कि डेबिट/क्रेडिट नोटों को समय पर जारी करना सुनिश्चित करने के लिए 2020-21 की दूसरी तिमाही से नियमित अनुवर्ती कार्रवाई की गई है। प्रबंधन के उत्तर में 2015-16 से 2019-20 के दौरान अपनी ओर से निष्क्रियता को उजागर किया गया है और कि 2020-21 की दूसरी तिमाही से ही सुधारात्मक कार्रवाई शुरू की गई है।

2.4.8.4 रेल की लागत के लिए प्रासंगिक सूचना प्रस्तुत करने में विलंब

भिलाई इस्पात संयंत्र से लंबी रेलों की आपूर्ति के लिए सेल और भारतीय रेलवे के बीच एक सहमति ज्ञापन (2003) किया गया था। सहमति ज्ञापन के प्रावधानों के अनुसार, रेल कीमत निर्धारण भारतीय रेलवे और सेल की संयुक्त कीमत निर्धारण समिति द्वारा किया जाना था जिसमें रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा और दोनों पार्टियों के लिए बाध्यकारी होगा। 2012-13 से 2018-19 के दौरान आपूर्ति की गई रेल की कीमत को कंपनी लेखाओं के अनुमोदन से 9 से 46 महीनों के बाद 2015-20 के दौरान अंतिम रूप दिया गया था। कीमत को अंतिम रूप देने में विलंब के कारण भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा मुख्य सलाहकार, लागत, वित्त मंत्रालय को संगत सूचना प्रेषित करने में विलंब हुआ था। भिलाई इस्पात संयंत्र ने बोर्ड द्वारा लेखापरीक्षित लेखाओं के अनुमोदन की तारीख से 1 से

³⁰ उद्धृत किए गए 66 प्रतिशत मामले भारतीय रेल को छोड़कर हैं क्योंकि रेलों की कीमत को रेलवे के साथ समझौता ज्ञापन के अनुसार अंतिम रूप दिया जाता है और इसमें अधिक समय लगा और यह सेल के नियंत्रण में नहीं था।

16 महीने के विलंब के साथ उपर्युक्त अवधि के लिए प्रासंगिक लागत आंकड़े प्रस्तुत किए। मुख्य सलाहकार, लागत ने 29 मई 2015 की अपनी रिपोर्ट में कहा था कि भिलाई इस्पात संयंत्र में संरचित और मजबूत लागत लेखांकन और सूचना प्रणाली नहीं थी जिससे वास्तविक समय लागत डेटा प्रदान किया जा सके। यह सिफारिश की गई थी कि सेल को उत्पाद-वार और प्रक्रिया-वार खपत/इनपुट-आउटपुट विवरण और नियमित आधार पर लागत डेटा उपलब्ध कराने के लिए सुपरिभाषित लागत लेखांकन प्रणाली विकसित करनी चाहिए।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि, बाद की रिपोर्टों (जनवरी 2020 में नवीनतम) में इसी तरह की सिफारिश के बावजूद इस संबंध में कोई विकास नहीं हुआ था। 2017-18 और 2018-19 से संबंधित अंतिम सूचना क्रमशः 31 मई 2019 और 1 नवंबर 2019 को भेजी गई थी। मुख्य सलाहकार, लागत को संगत लागत आंकड़े प्रस्तुत करने में विलंब के परिणामस्वरूप संयुक्त मूल्य निर्धारण समिति द्वारा रेलों की कीमत को अंतिम रूप देने में विलंब हुआ। परिणामस्वरूप, सेल 2012-13 से 2018-19 के दौरान आपूर्ति की गई रेल के लिए कीमत वृद्धि के लिए ₹1,959.46 करोड़ का दावा संबंधित वर्षों के लिए लेखाओं के अनुमोदन की तारीख से 9 से 46 महीने के बाद ही कर सका। इसके परिणामस्वरूप वित्तपोषण की लागत के लिए ₹51.49 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

प्रबंधन ने अपने उत्तर (मई 2021) में कीमत को अंतिम रूप देने में शामिल प्रक्रियाओं का उल्लेख किया। इसने आगे बताया कि सेल/भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा मुख्य सलाहकार, लागत की आवश्यकता का अनुपालन करते हुए सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्रस्तुत किए गए थे।

प्रबंधन का उत्तर प्रासंगिक नहीं है क्योंकि निदेशक मंडल द्वारा लेखापरीक्षित लेखाओं को अपनाए जाने के बाद मुख्य सलाहकार, लागत को लागत के संबंध में पहली सूचना प्रस्तुत करने में सेल की ओर से किए गए विलंब पर ही लेखापरीक्षा में विचार किया गया था। लेखापरीक्षित लेखाओं को अपनाने के बाद मुख्य सलाहकार, लागत, वित्त मंत्रालय को लागत संबंधी आंकड़े प्रस्तुत करने में विलंब के कारणों पर भी प्रबंधन के उत्तर में उल्लेख नहीं था।

सिफारिश संख्या 7: कंपनी मुख्य सलाहकार, लागत, वित्त मंत्रालय को वास्तविक समय के आधार पर उत्पाद-वार और प्रक्रिया-वार खपत/इनपुट-आउटपुट विवरण और लागत डेटा प्रदान करने के लिए एक संरचित और मजबूत लागत लेखांकन और सूचना प्रणाली विकसित कर सकती है ताकि विक्रेताओं (रेलवे) से दावों में विलंब न हो और वित्तपोषण की लागत पर अतिरिक्त व्यय न हो।

2.4.8.5 उत्पाद शुल्क की वसूली न होना

सेल और भारतीय रेलवे (2003) के बीच सहमति ज्ञापन के अनुसार, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष भारतीय रेलवे और सेल की संयुक्त कीमत निर्धारण समिति की सिफारिश पर रेल की अंतिम कीमत तय करेंगे। अंतिम कीमत को अंतिम रूप दिए जाने तक, रेल की आपूर्ति अनंतिम कीमत पर की जाती है जिस पर प्रचलित दर पर उत्पाद शुल्क/जीएसटी का भी भुगतान किया गया हो। लेखापरीक्षा में नोट किया गया कि जनवरी, 2008 से मार्च, 2012 के दौरान आपूर्ति की गई रेलों की कीमत को अक्टूबर, 2013 में रेलवे बोर्ड द्वारा अंतिम रूप दिया गया था। जनवरी, 2008 से जून, 2010 तक की अवधि के लिए कीमत में गिरावट आई और जुलाई, 2010 से मार्च, 2012 की अवधि के लिए ऊर्ध्वगामी संशोधन किया गया था। डी-एस्केलेशन के लिए सेल ने भारतीय रेलवे को क्रेडिट नोट जारी किए और इसी तरह कीमतों में वृद्धि के लिए, भारतीय रेलवे ने सेल को लागू उत्पाद शुल्क के साथ-साथ विभेदक राशि का भुगतान किया। तथापि, भारतीय रेलवे ने डी-एस्केलेटेड कीमतों पर विभेदक उत्पाद शुल्क के कारण ₹34.12 करोड़ की कटौती की। सेल को अभी तक राशि का प्रतिदाय प्राप्त होना है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि कंपनी अंतिम कीमत में वृद्धि/वृद्धि को कम करने के मामले में उत्पाद शुल्क के पारस्परिक समायोजन के लिए सहमति ज्ञापन में उपयुक्त खंड न जोड़कर अपने वित्तीय हितों की रक्षा करने में विफल रही। उत्पाद शुल्क की वसूली पर सहमति ज्ञापन में किसी भी खंड के अभाव में, सेल को ₹34.12 करोड़ की हानि हुई।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (मई 2021) कि उत्पाद शुल्क के प्रतिदाय के लिए रेलवे के साथ मामले को लगातार उठाया जा रहा है। इसने आगे बताया कि लेखाओं में आवश्यक प्रावधान किए गए हैं। तथ्य यह है कि प्रबंधन ने अपने वित्तीय विवरणों में बकाया के विरुद्ध एक प्रावधान बनाया है, यह दर्शाता है कि वसूली की संभावना दूरस्थ है।

2.4.9 विदेशी मुद्रा जोखिम प्रबंधन नीति का अननुपालन

सेल ने फरवरी 2013 में विदेशी मुद्रा जोखिम प्रबंधन नीति को अनुमोदित किया ताकि कंपनी के संपर्क में आने वाले विदेशी मुद्रा जोखिमों की पहचान की जा सके। विदेशी मुद्रा जोखिम की समीक्षा करने के लिए एक विदेशी मुद्रा जोखिम प्रबंधन समिति का गठन किया गया था (अप्रैल 2013) और महीने में एक बार इसकी बैठक होनी आवश्यक थी। लेखापरीक्षा ने नोट किया कि विदेशी मुद्रा जोखिम प्रबंधन समिति की बैठक अगस्त 2014 तक नियमित रूप से आयोजित की गई थी और उसके बाद, मार्च 2020 तक केवल एक बैठक आयोजित की गई थी (अगस्त 2018 में)। इसके अलावा, सेल का विदेशी मुद्रा प्रकटन 2015-16 से 2019-20 के दौरान ₹31,912 करोड़ था और एलआईबीओआर 0.2708 प्रतिशत (अप्रैल 2015) से 2.58 प्रतिशत (अप्रैल 2019) तक बढ़ती हुई प्रवृत्ति में वृद्धि कर रहा था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि विदेशी मुद्रा जोखिम प्रबंधन नीति के परिकल्पित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अगस्त 2014 के बाद विदेशी मुद्रा जोखिम प्रबंधन समिति की बैठक नियमित रूप से नहीं की गई थी।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (मई 2021) कि नियमित आधार पर विदेशी मुद्रा जोखिम प्रबंधन समिति की औपचारिक बैठक की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ब्याज दर स्वैप क्रियान्वयन के समय, विदेशी मुद्रा जोखिम प्रबंधन समिति के सदस्यों से परामर्श किया जाता है। ब्याज दर के स्वैप के लिए अनुमोदन निदेशक (वित्त) द्वारा प्रदान किया जाता है। एलआईबीओआर गतिविधि पर कड़ी नजर रखी जाती है।

उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि विदेशी मुद्रा जोखिम प्रबंधन समिति के सदस्यों के साथ क्रियान्वयन के समय परामर्श को दर्शाने वाला कुछ भी अभिलेख में नहीं था। विदेशी मुद्रा जोखिम प्रबंधन नीति के अनुसार, विदेशी मुद्रा जोखिम प्रबंधन समिति को महीने में एक बार बैठक करने की आवश्यकता थी। इसके अलावा, विदेशी मुद्रा जोखिम प्रबंधन समिति में विभिन्न विभागों (वाणिज्यिक, परियोजना, कोयला आयात आदि) के सदस्य थे और विदेशी मुद्रा प्रकटन के लिए जाने से पहले उनके राय लेना महत्वपूर्ण हैं।

2.4.10 निधियों का उपयोग

सेल इस्पात निर्माण के लिए आवश्यक विभिन्न संसाधनों और सेवाओं की अधिप्राप्ति के लिए अपनी निधियों का उपयोग करता है। संसाधनों में गैस, विद्युत शक्ति, पानी आदि शामिल हैं। इस्पात निर्माण के लिए रेल सेवाएं भी महत्वपूर्ण हैं। इन संसाधनों और

सेवाओं को या तो आंतरिक उत्पादन से या बाहरी पार्टियों से क्रय के माध्यम से मंगाया जाता है।

2.4.10.1 गैसों और विद्युत

इस्पात संयंत्रों की ब्लास्ट फर्नेस में गर्म धातु के उत्पादन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। सेल ने न्यूनतम गारंटीकृत गैसों का आहरण न करने के कारण अतिरिक्त व्यय किया, जैसी कि नीचे पैरा में चर्चा की गई है:

(i) बोकारो इस्पात संयंत्र ने ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और आर्गन गैसों की अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए आईएनओएक्स एयर प्रोडक्ट्स लिमिटेड के साथ एक करार किया (जून, 2006)। करार में आईएनओएक्स द्वारा बिल्ट, आउन और आपरेट आधार पर एक संयंत्र के निर्माण को दिसंबर, 2008 तक पूरा करने के लिए निर्धारित किया गया था। करार में बोकारो इस्पात संयंत्र द्वारा संयंत्र से गैसों के न्यूनतम गारंटीकृत ऑफ टेक की परिकल्पना की गई थी, जिसमें विफल रहने पर इस्पात संयंत्र शास्ति का भुगतान करने के लिए दायी था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि बोकारो के गर्म धातु उत्पादन को वांछित स्तर तक नहीं बढ़ाया जा सका और परिणामस्वरूप गैसों के न्यूनतम गारंटीकृत ऑफ टेक को लगातार नहीं किया जा सका। करार के अनुसार ऑक्सीजन का आहरण न्यूनतम गारंटीकृत मात्रा से अधिक था। हालांकि, नाइट्रोजन और आर्गन के मामले में गिरावट रही थी। बोकारो इस्पात संयंत्र ने 2015-16 से 2019-20 के दौरान करार के अनुसार गैसों के न्यूनतम ऑफ टेक को प्राप्त करने में विफलता के लिए शास्ति के रूप में ₹7.27 करोड़ का भुगतान किया।

(ii) मैसर्स प्रैक्स एयर ने भिलाई इस्पात संयंत्र में बिल्ट, आउन और आपरेट आधार पर एक ऑक्सीजन संयंत्र संस्थापित किया। करार के अनुसार, कम मांग के मामले में, इस्पात संयंत्र गैसों के न्यूनतम ऑफ-टेक में कमी के लिए कीमत का भुगतान करेगा। भिलाई इस्पात संयंत्र ने 2015-16 से 2019-20 के दौरान कम मात्रा में गैस की अधिप्राप्ति/खपत की और न्यूनतम ऑफ-टेक प्राप्त करने में विफलता के लिए आपूर्तिकर्ता को ₹27.99 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान किया। लेखापरीक्षा में पाया गया कि 2015-16 से 2019-20 के दौरान गर्म धातु और कच्चे इस्पात के उत्पादन में कमी आई थी। इस प्रकार, असंगत प्रचालन के कारण भिलाई इस्पात संयंत्र को ₹27.99 करोड़ का अतिरिक्त व्यय करना पड़ा।

(iii) राउरकेला इस्पात संयंत्र ने जनवरी, 2009 में मैसर्स लिंडे इंडिया लिमिटेड के साथ गैस आपूर्ति करार किया था बिल्ड आउन और आपरेट आधार पर एक ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित करने के लिए था। कम मांग के मामले में करार के खंड 15.3 के अनुसार, खरीदार को ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और आर्गन के लिए एक एयर सेपरेशन यूनिट के प्रति घंटा के आधार पर 75 प्रतिशत क्षमता के न्यूनतम आफ टेक के अध्यक्षीन मासिक नियत सुविधा प्रभार और वास्तविक उपभोग आधार पर आपूर्ति की गई गैस की कीमत का भुगतान करना जारी रखना चाहिए।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि राउरकेला इस्पात संयंत्र ने 2015-16 से 2019-20 के दौरान ऑक्सीजन की क्षमता (30,750 सामान्य घन मीटर प्रति घंटे) की परिकल्पित न्यूनतम ऑफ टेक की तुलना में कम मात्रा में ऑक्सीजन प्राप्त की। ऑक्सीजन गैस की कम मांग ब्लास्ट फर्नेस में शटडाउन/ब्रेकडाउन, कम ऑक्सीजन संवर्धन, स्टील मैल्टिंग शॉप में कम ब्लो आदि के कारण हुई थी। परिणामस्वरूप, राउरकेला इस्पात संयंत्र को 22767.075 हजार सामान्य घन मीटर ऑक्सीजन के लिए ₹8.93 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान करना पड़ा, जिसका उपयोग इसके द्वारा नहीं किया गया था।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (मई 2021) कि प्रौद्योगिकीय बाधाओं के कारण, बोकारो इस्पात संयंत्र न्यूनतम टेक ऑफ पॉइंट क्लॉज को मानने के लिए मजबूर था। भिलाई में 2015-16 से 2019-20 के दौरान गर्म धातु/कच्चे इस्पात का उत्पादन असंगत था और इसलिए ऑक्सीजन की खपत सहमत न्यूनतम मात्रा से कम थी। राउरकेला में, जब भी संभव था, मैसर्स लिंडे द्वारा निर्मित संयंत्र की एक इकाई को कम ऑक्सीजन खपत के कारण न्यूनतम टेक ऑफ प्वाइंट के तहत भुगतान से बचने के लिए बंद कर दिया गया था।

प्रबंधन के उत्तर में आगे लेखापरीक्षा अभ्युक्ति का समर्थन किया गया है कि संयंत्र न्यूनतम गारंटीकृत गैसों को आहरित करने में असमर्थ थे जिसके कारण शास्ति का भुगतान किया गया। प्रबंधन ने इस तरह की शास्ति से बचने के लिए पिछले वर्षों के वास्तविक खपत पैटर्न के आधार पर न्यूनतम ऑफ टेक मात्रा को नीचे की ओर संशोधित करने की पहल नहीं की।

सिफारिश संख्या 8: प्रबंधन इस तरह की शास्ति से बचने के लिए पिछले वर्षों में गैसों के वास्तविक खपत पैटर्न को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम टेक ऑफमात्रा को नीचे की ओर संशोधित करने के लिए पहल कर सकता है।

(iv) आंतरिक विद्युत संयंत्र से विद्युत प्राप्त करने के अलावा, राउरकेला इस्पात संयंत्र द्वारा उड़ीसा लिमिटेड की वेस्टर्न इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी से विद्युत का क्रय किया जाता है। ऊर्जा प्रभार औद्योगिक टैरिफ (₹5.20/ यूनिट) पर था जिसमें आहरित उस कुल विद्युत का 10 प्रतिशत छोड़ दिया गया था जिसे कॉलोनी खपत के रूप में ₹4.60 / यूनिट पर चार्ज किया गया था। राउरकेला इस्पात संयंत्र ने अपनी टाउनशिप के लिए एक अलग विद्युत आपूर्ति संविदा के लिए निर्णय लिया (जून 2014), जिससे ओडिशा विद्युत विनियामक आयोग द्वारा निर्धारित विद्युत टैरिफ संरचना के मद्देनजर प्रति वर्ष ₹15 करोड़ के ऊर्जा बिल में औसत बचत होगी।

राउरकेला इस्पात संयंत्र ने उड़ीसा लिमिटेड की पश्चिमी विद्युत आपूर्ति कंपनी से विद्युत के लिए एक अलग संविदा के लिए संपर्क किया (जून, 2014)। एक वर्ष बीत जाने के बाद ही राउरकेला इस्पात संयंत्र ने उड़ीसा लिमिटेड की पश्चिमी विद्युत आपूर्ति कंपनी से मौजूदा नेटवर्क से 33 केवी पर 40 एमवीए की संविदा मांग के साथ अपनी टाउनशिप के लिए अलग विद्युत आपूर्ति करार की अनुमति के लिए अनुरोध किया था (जून 2015)। राउरकेला इस्पात संयंत्र ने मार्च 2020 में उड़ीसा लिमिटेड की पश्चिमी विद्युत आपूर्ति कंपनी से संपर्क करने तक साढ़े चार वर्ष तक इस मामले पर कार्रवाई नहीं की। विद्युत कंपनी ने उत्तर दिया (जून 2020) कि कॉलोनी के लिए अलग-अलग बिलिंग की अनुमति नहीं दी जा सकती थी क्योंकि दो अलग-अलग स्रोतों से आपूर्ति को एक ही परिसर में पूरा नहीं किया जा सकता है। लेखापरीक्षा में पाया गया कि आवेदन प्रस्तुत करने में विलंब और राउरकेला इस्पात संयंत्र द्वारा अपनी टाउनशिप के लिए थोक घरेलू टैरिफ पर एक अलग विद्युत आपूर्ति संविदा प्राप्त करने के लिए कार्रवाई के अभाव के कारण, इसे विद्युत की कम दर का लाभ नहीं मिल सका, जिसके परिणामस्वरूप जुलाई 2015 से मार्च 2020 के दौरान ₹61.06 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (मई 2021) कि इस मुद्दे को सितंबर 2020 में उड़ीसा लिमिटेड की पश्चिमी विद्युत आपूर्ति कंपनी के साथ उठाया गया था और कि यदि यह सहमत नहीं हुआ, तो प्रबंधन ओडिशा विद्युत नियामक आयोग के समक्ष अपील दायर करने पर विचार कर सकता है।

प्रबंधन के उत्तर पर इस तथ्य के मद्देनजर विचार किया जा सकता है कि अगस्त 2021 तक, वह विद्युत आपूर्ति कंपनी के साथ अपने अनुरोध को करने के बाद से सात वर्ष

बीत जाने के बावजूद अपनी टाउनशिप के लिए अलग से विद्युत कनेक्शन प्राप्त करने में असमर्थ था।

2.4.10.2 कर्मचारियों को अनुचित लाभ

(i) राउरकेला इस्पात संयंत्र द्वारा ₹7.89 करोड़ के नियत प्रभारों और विद्युत शुल्क की कम वसूली

राउरकेला इस्पात संयंत्र आंतरिक विद्युत संयंत्रों से विद्युत प्राप्त करता है या इसे बाहरी स्रोतों से क्रय करता है। विद्युत के कुछ भाग की टाउनशिप में खपत की जाती है। इस्पात संयंत्र उपभोक्ताओं से विद्युत प्रभारों की वसूली करता है। विद्युत शुल्क अधिनियम, 1961 के खंड 3 के अनुसार, विद्युत शुल्क किसी भी उपभोक्ता द्वारा, या किसी ऐसे व्यक्ति (लाइसेंसी या बोर्ड नहीं होने के नाते) पर ऊर्जा की खपत पर लगाया जाएगा, जो समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित दरों पर अपने स्वयं के उपयोग या खपत के लिए ऐसी ऊर्जा उत्पन्न करता है। राउरकेला इस्पात संयंत्र के विद्युत टैरिफ परिपत्र के अनुसार, विद्युत शुल्क अधिनियम, 1961 के अंतर्गत ओडिशा सरकार द्वारा लगाए गए विद्युत शुल्क और किसी कानून के तहत लगाए गए किसी भी अन्य सांविधिक उद्ग्रहण को उपभोक्ताओं द्वारा देय टैरिफ के अतिरिक्त प्रभारित किया जाएगा।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि राउरकेला इस्पात संयंत्र ने इस्पात टाउनशिप के उपभोक्ताओं से ऊर्जा प्रभारों पर भार और विद्युत शुल्क के तदनुरूप नियत प्रभारों की वसूली नहीं की। उपभोक्ताओं से इन प्रभारों की कम वसूली के कारण 2015-16 से 2019-20 की अवधि के दौरान ₹7.89 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (मई 2021) कि अधिकांश उपभोक्ता कर्मचारी थे और उनके लिए सद्भावना और कल्याण उपाय के रूप में विद्युत शुल्क नहीं लगाया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उपभोक्ताओं से विद्युत शुल्क की वसूली न करना राउरकेला इस्पात संयंत्र के विद्युत टैरिफ परिपत्र के अनुरूप नहीं था और साथ ही विद्युत शुल्क अधिनियम, 1961 और ओडिशा सरकार की अधिसूचनाओं का अनुपालन नहीं किया गया था। इसके अलावा, कर्मचारियों के लिए कोई भी सद्भावना या कल्याण उपाय किसी अनुमोदित प्रोत्साहन योजना या नीति के आधार पर होना चाहिए।

(ii) भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा पानी पर ₹45.22 करोड़ का अतिरिक्त व्यय

भिलाई इस्पात संयंत्र के लिए पानी की वार्षिक आवश्यकता 110 मिलियन घन मीटर है, जिसमें संयंत्र और टाउनशिप के लिए पीने का पानी (60 प्रतिशत) और औद्योगिक मेकअप वाटर (40 प्रतिशत) शामिल है। भिलाई इस्पात संयंत्र ने 1 जनवरी, 2005 से शुरू होकर 30 वर्षों के लिए अप्रैल, 2006 में जो छत्तीसगढ़ सरकार के साथ एक करार किया था छत्तीसगढ़ जल संसाधन विभाग के जलाशयों से इसके उपयोग के लिए 113 मिलियन घन मीटर (4 हजार मिलियन घन मीटर) जल की निकासी के लिए किया गया था। पानी संयंत्र में औद्योगिक उपयोग के लिए और कॉलोनी में घरेलू उपयोग के लिए था। छत्तीसगढ़ जल संसाधन विभाग ने सूचित किया (अगस्त 2008) कि पानी की आपूर्ति मुख्य रूप से औद्योगिक उद्देश्य के लिए थी। घरेलू उद्देश्य के लिए इसका उपयोग केवल 50 प्रतिशत तक ही सीमित था और भिलाई इस्पात संयंत्र को 50 प्रतिशत से अधिक खपत वाले पानी के लिए औद्योगिक दर पर भुगतान करना आवश्यक था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि घरेलू प्रयोजन के लिए पानी की खपत सहमत मात्रा का लगभग 61.65 प्रतिशत थी जो 50 प्रतिशत की अनुमत मात्रा से अधिक थी और इसके परिणामस्वरूप भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा ₹58.33 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान किया गया था। हालांकि, इस्पात संयंत्र ने उपयोगकर्ताओं से केवल ₹13.11 करोड़ की वसूली की। इसके परिणामस्वरूप 2015-16 से 2019-20 के दौरान ₹45.22 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (मई 2021) कि लेखापरीक्षा अभ्युक्ति के अनुपालन में, पेयजल की वास्तविक खपत के आधार पर कीमत निर्धारण और बिलिंग के मामले को जल संसाधन विभाग के कर्मचारियों के साथ उठाया जा रहा है।

प्रबंधन पानी की अतिरिक्त लागत की वसूली के लिए कर्मचारियों के साथ भी इस मामले को उठा सकता है।

2.4.10.3 रेलभाड़ा

रेलवे के माध्यम से कच्ची सामग्री, तैयार माल और उपस्करों/मशीनरी का परिवहन किया जाता है। सेल ने 2015-16 से 2019-20 के दौरान रेलभाड़े के कारण ₹9,015.58 करोड़ व्यय किए। लेखापरीक्षा में पाया गया कि सेल ने 2015-16 से 2019-20 के दौरान

विलम्ब प्रभारों, इंजन किराया प्रभारों, अतिलदान पर शास्ति आदि पर परिहार्य व्यय किया, जैसी कि नीचे पैरा में चर्चा की गई है:

(i) विलम्ब प्रभारों के कारण ₹152.84 करोड़ का परिहार्य व्यय

सामग्री के लदान और उतराई के लिए रेलवे मुफ्त समय प्रदान करता है। यदि लदान/उतराई के लिए लिया गया समय मुफ्त समय सीमा से अधिक हो जाता है, तो विलम्ब प्रभार लगाया जाता है। लेखापरीक्षा में नोट किया गया कि रेलवे द्वारा अनुमत मुफ्त समय के भीतर सामग्री का लदान/उतराई करने में असमर्थता के कारण इस्पात संयंत्रों ने 2015-20 के दौरान विलम्ब प्रभार के रूप में ₹152.84 करोड़³¹ का भुगतान किया।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (मई 2021) कि भिलाई इस्पात संयंत्र, भारतीय लौह और इस्पात कंपनी इस्पात संयंत्र (बर्नपुर में स्थित) और बोकारो इस्पात संयंत्र में 2020-21 में वैगनों के अवरोधन घंटे काफी कम कर दिए गए हैं। इसने आगे बताया कि दुर्गापुर में विलम्ब को कम करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की गई है और कि राउरकेला इस्पात संयंत्र द्वारा रेलवे से वर्ष 2019-20 के लिए विलम्ब प्रभार की राशि (प्रबंधन के अनुसार रेलवे के लिए जिम्मेदार) को माफ करने का अनुरोध किया गया है।

प्रबंधन का उत्तर इस तथ्य पर प्रकाश डालता है कि निवारक और पूर्व सक्रिय कदम उठाकर, यह अवरोधन के घंटों और विलम्ब प्रभारों को कम कर सकता था। इसलिए, यदि इस तरह की कार्रवाई पहले की गई होती, तो 2015-16 से 2019-20 के दौरान भुगतान किए गए विलम्ब प्रभारों को कम से कम किया जा सकता था।

(ii) भारतीय लौह और इस्पात कंपनी इस्पात संयंत्र (बर्नपुर में स्थित) द्वारा इंजन किराया प्रभार के प्रति ₹41.09 करोड़ का परिहार्य व्यय

रेलवे बोर्ड ने 1 अप्रैल, 2006 के बाद आने वाले सभी साइडिंगों के लिए इंजन ऑन लोड योजना लागू की। इस योजना के अंतर्गत, यदि किसी साइडिंग धारक को निर्धारित मुफ्त समय के भीतर रेल के लदान या उतराई के दौरान ट्रेन इंजन का उपयोग करने की

³¹ भिलाई इस्पात संयंत्र- ₹35.90 करोड़, राउरकेला इस्पात संयंत्र- ₹38.01 करोड़, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र- ₹16.08 करोड़, बोकारो इस्पात संयंत्र- ₹20.09 करोड़ और इंडियन आयरन एंड इस्पात कंपनी इस्पात संयंत्र (बर्नपुर में स्थित)- ₹33.76 करोड़।

आवश्यकता होती है, तो उसे किसी अतिरिक्त प्रभारों का उद्ग्रहण किए बिना अनुमत किया जाएगा। इंजन किराया प्रभार मुफ्त समय के बाद प्रभारित चार्ज किया जाएगा। उपर्युक्त को सुविधाजनक बनाने के लिए लोड अवधारणा और डिजाइन यार्ड लेआउट पर इंजन पर लदान और उतराई के लिए सुविधाएं विकसित करने की शर्त के साथ रेलवे बोर्ड द्वारा नवंबर, 2008 में यातायात की आवाजाही के लिए रेल परिवहन स्वीकृति प्रदान की गई थी। भारतीय लौह और इस्पात कंपनी इस्पात संयंत्र ने जनवरी 2014 में रेलवे के साथ लोड प्रचालन पर इंजन के लिए एक करार किया था। भारतीय लौह और इस्पात कंपनी इस्पात संयंत्र ने दिसंबर 2015 में लोड अवधारणा पर इंजन के तहत एक नयी कच्ची सामग्री संमलाई यार्ड विकसित किया। रेलवे द्वारा खुले रेकों को उतारने के लिए पांच घंटे के मुफ्त समय की अनुमति दी गई थी। लेखापरीक्षा ने नोट किया कि 2015-20 के दौरान ₹41.09 करोड़ का भुगतान अनुमत मुक्त समय के बाद इंजन के अवरोधन के कारण किया गया था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि लगभग 70 प्रतिशत मामलों में, उतराई का समय पांच घंटे से अधिक था, जो मुख्य रूप से रूट स्टॉप, शिफ्ट परिवर्तन, प्लेसमेंट विलंब और हूपर जाम जैसे कारणों की वजह से था, जो प्रबंधन के नियंत्रण में थे। इस प्रकार, निर्धारित समय के भीतर सामग्री की उतराई करने में प्रबंधन की असमर्थता के परिणामस्वरूप ₹41.09 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (मई 2021) कि उतराई में विलंब के कारण हमेशा उनके नियंत्रण में नहीं होते हैं। निवारक और पूर्व सक्रिय कार्रवाई करने के कारण विलंब में काफी कमी आई थी जिसके परिणामस्वरूप इंजन किराया प्रभारों में कमी आई थी।

प्रबंधन का उत्तर इस तथ्य को सत्यापित करता है कि निवारक और पूर्व सक्रिय कार्रवाई करके, इंजन किराया प्रभार को शामिल किया जा सकता था।

(iii) अतिलदान प्रभारों के लिए निष्क्रिय भाड़े और शास्ति का भुगतान

रेलवे एक वैगन की वहन क्षमता के लिए भाड़ा प्रभारित करता है। यदि वैगन कम लदान वाला है, तो ग्राहक को उन सामग्रियों के लिए भाड़े का अतिरिक्त खर्च वहन करना पड़ता है जो वास्तव में परिवहन नहीं किए गए हैं। वैगनों के अतिलदान के मामले में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा शास्तिक भाड़ा/अतिलदान प्रभारों का भुगतान किया जाना होता है।

लेखापरीक्षा में नोट किया गया कि सेल के पांच इस्पात संयंत्रों ने 2015-20 के दौरान ₹397.90 करोड़³² के निष्क्रिय भाड़े का भुगतान किया। इसके अतिरिक्त भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर में इस्पात संयंत्रों द्वारा उसी अवधि के दौरान वैगनों के अतिलदान के लिए शास्ति के रूप में ₹7.66 करोड़³³ का भुगतान किया गया था।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (मई 2021) कि भिलाई इस्पात संयंत्र खनन साइडिंग में इष्टतम लदान/ भाड़े को सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए गए थे। दुर्गापुर में वैगनों के कम लदान/अतिलदान से बचने के लिए पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली थी। बोकारो में निष्क्रिय को कम करने के लिए विभिन्न माध्यमों से अनुकूलन किया जा रहा था। इसने आगे बताया कि शून्य सहिष्णुता के साथ लदान करना व्यावहारिक रूप से बहुत मुश्किल था। प्रबंधन ने आगे कहा (अक्टूबर 2021) कि भारतीय रेलवे द्वारा अलग-अलग वहन क्षमता वाले विभिन्न प्रकार के वैगनों की आपूर्ति के मद्देनजर उत्पाद मिश्र के संबंध में निष्क्रिय भाड़े के लिए कोई सहिष्णुता सीमा निर्धारित करना संभव नहीं था।

प्रबंधन के उत्तर पर इस तथ्य के मद्देनजर विचार किया जा सकता है कि यदि शून्य सहिष्णुता के साथ लदान व्यावहारिक नहीं था, तो इसे कम से कम सहिष्णुता की सबसे कम सीमा निर्धारित करनी चाहिए थी। प्रबंधन को वैगनों को सही ढंग से लदान करने और अतिलदान के लिए निष्क्रिय भाड़े और शास्ति के कारण व्यय को कम करने के लिए प्रभावी कदम उठाने चाहिए, क्योंकि कंपनी इसके कारण अत्यधिक व्यय कर रही है।

सिफारिश संख्या 9: कंपनी (क) विलम्ब प्रभावों में कमी के लिए लक्ष्य निर्धारित कर सकती है (ख) इंजन किराया प्रभावों को कम करने के लिए योजना के तहत अनुमत निर्धारित समय के भीतर सामग्री के लदान करने/उतराई में नियंत्रणीय विलंब को रोकने के लिए आवश्यक उपाय कर सकती है (ग) निष्क्रिय भाड़े के कारण परिहार्य व्यय को कम करने के लिए वैगनों के प्रकार, आकार और वहन क्षमता के संदर्भ में निष्क्रिय भाड़े के लिए सहनशीलता सीमा निर्धारित कर सकती है।

³² भिलाई इस्पात संयंत्र: ₹116.25 करोड़, बोकारो इस्पात संयंत्र: ₹41.03 करोड़, राउरकेला इस्पात संयंत्र: ₹33.74 करोड़, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र: ₹53.84 करोड़ और इंडियन आयरन एंड ओर कंपनी इस्पात संयंत्र (बर्नपुर में स्थित): ₹153.04 करोड़।

³³ राउरकेला इस्पात संयंत्र: ₹5.57 करोड़, भिलाई इस्पात संयंत्र: ₹1.84 करोड़ और दुर्गापुर इस्पात संयंत्र: ₹0.25 करोड़।

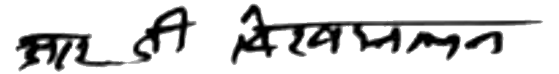
2.7 निष्कर्ष

सेल को 2015-16 से 2017-18 के दौरान घाटा हुआ और बाद में 2018-19 और 2019-20 के दौरान मुख्य रूप से सब-ग्रेड फाइन्स, स्क्रेप आदि के मूल्यांकन के कारण इसने लाभ अर्जित किया। कंपनी को पिछले पांच वर्षों में क्रेडिट रेटिंग में गिरावट/ स्थिरता का सामना करना पड़ा, जो कमजोर परिचालन निष्पादन, ऋण स्तर और ब्याज लागत के कारण था। सेल द्वारा उधारी 2011-12 में ₹16,320 करोड़ से बढ़कर 31 मार्च 2020 को ₹54,127 करोड़ हो गई थी। कंपनी निदेशक मंडल द्वारा तैयार किए गए दीर्घावधि ऋणों और अल्पकालिक ऋणों के अनुपात को बनाए रखने में सक्षम नहीं थी। कंपनी द्वारा ऋण और ब्याज को प्रतिरक्षा करने का निर्णय सुसंगत नहीं था। विदेशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव के रूप में 400 मिलियन अमरीकी डालर के ऋणों को प्रतिरक्षा न करने के कारण ₹194 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ। कंपनी ने मार्च 2017 से दिसंबर 2017 के दौरान कुछ मामलों को छोड़कर क्रेता के क्रेडिट (एलआईबीओआर) पर ब्याज का प्रतिरक्षा नहीं किया।

सेल की 21 संयुक्त उद्यम कंपनियों में से आठ प्रचालनात्मक थीं, तीन परियोजना/व्यवहार्यता चरण में थीं और दस निष्क्रिय या बंद होने के अधीन थीं। कंपनी ने संयुक्त उद्यम कंपनियों में निधियों के निवेश के लिए कोई नीति या दिशानिर्देश तैयार नहीं किए थे। सेल द्वारा संयुक्त उद्यम कंपनियों में निष्फल निवेश के मामलों की लेखापरीक्षा की गई। कंपनी ने लाभांश के भुगतान के संबंध में निवेश और सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग के दिशानिर्देशों का पालन नहीं किया। कंपनी ने 2018-19 के दौरान नाममात्र लाभांश (₹206.53 करोड़) की घोषणा की और लाभ में होने के बावजूद 2019-20 के दौरान कोई लाभांश नहीं दिया। देनदार ₹3,297 करोड़ (2015-16) से बढ़कर ₹9,020 करोड़ (2019-20) हो गए थे। प्रासंगिक लागत आंकड़े प्रस्तुत करने में विलंब और परिणामस्वरूप रेलों की कीमत को अंतिम रूप देने में विलंब के कारण रेलों के लिए कीमत वृद्धि के प्रति ₹1,959.46 करोड़ का दावा प्रस्तुत करने में विलंब हुआ था। इस्पात संयंत्रों द्वारा न्यूनतम गारंटीकृत गैसों का आहरण न किए जाने के कारण

अतिरिक्त व्यय किया गया था। रेलवे द्वारा अनुमत मुक्त समय के बाद इंजन के अवरोधन के कारण भारतीय लौह और इस्पात कंपनी इस्पात संयंत्र (बर्नपुर में स्थित) द्वारा इंजन किराया प्रभारों के लिए ₹41.09 करोड़ का परिहार्य व्यय किया गया था। सेल ने वैगनों के कम लदान के कारण ₹397.90 करोड़ और वैगनों के अतिलदान के लिए शास्ति के रूप में ₹7.66 करोड़ के निष्क्रिय भाड़े का भुगतान किया। अनुमत मात्रा से अधिक पानी की खपत के कारण भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा ₹58.33 करोड़ का अतिरिक्त व्यय किया गया।

प्रबंधन ने स्वयं अपनी क्रेडिट रेटिंग के नीचे की ओर संशोधन के आसन्न खतरे को स्वीकार किया। इस तरह के नीचे के संशोधन से उधार लेने की लागत में वृद्धि होगी और भविष्य में निधियां जुटाने में कठिनाई होगी। ऋण इक्विटी अनुपात, ब्याज कवरेज अनुपात और शुद्ध ऋण का ब्याज, करों, मूल्यहास और परिशोधन से पहले की आय से अनुपात जैसे इसकी वित्तीय स्थिति को दर्शाने वाले महत्वपूर्ण अनुपात भी वित्तीय अस्थिरता और कंपनी के बिगड़ते क्रेडिट प्रोफाइल का संकेत देते हैं।



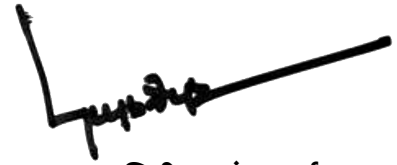
(आर जी विश्वनाथन)

उप नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
(वाणिज्यिक) तथा अध्यक्ष, लेखापरीक्षा बोर्ड

नई दिल्ली

दिनांक: 31.03.2022

प्रतिहस्ताक्षरित



(गिरीश चंद्र मुर्मू)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली

दिनांक: 31.03.2022

© भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in